



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 15 अप्रैल, 2025

चैत्र 25, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या 1281/चार-2025-4095-2023

लखनऊ, 15 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0-31

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022) की धारा 45 के साथ पठित धारा 46 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय हेतु निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाती हैं:-

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2025

अध्याय-एक

1- (1) यह परिनियमावली भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, संक्षिप्त नाम और 2025 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 15 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

धारा 45 2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली परिभाषायें में,-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022) से है;

(ख) 'सम्बद्धता' में इसके व्याकरणिक रूपभेदों के साथ किसी महाविद्यालय के संबंध में तथा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को ऐसे महाविद्यालयों में ग्रहण किया जाना सम्मिलित है;

(ग) 'खंड' का तात्पर्य परिनियम के उस खंड से है जिसमें वह पद आया हो;

(घ) महाविद्यालय का तात्पर्य किसी संस्था से है, चाहे वह इस प्रकार के या किसी अन्य नाम से जाना जाए जो विश्वविद्यालय से किसी भी अर्हता को प्राप्त करने के लिये 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त अध्ययन कार्यक्रम का प्रबंध करता हो और जो विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसे अध्ययन कार्यक्रम को प्रबंध करने हेतु सक्षम रूप से मान्यता प्राप्त हो;

(ङ) 'पाठ्यक्रम' का तात्पर्य एक इकाई जिसमें अध्ययन कार्यक्रम समाविष्ट हो;

(च) "सहायता अनुदान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय से है जो अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो;

(छ) "कार्यक्रम"/"अध्ययन कार्यक्रम" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपाधि प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करना है;

(ज) "सांविधिक"/"विनियामक निकाय" का तात्पर्य उच्च शिक्षा के सुसंगत क्षेत्रों में मानकों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा इस प्रकार गठित किये गये किसी निकाय से है;

(झ) "छात्र" का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाला और अनुसरण करने वाला कोई व्यक्ति से है;

(ञ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(ट) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(2) ऐसे शब्द और पद, जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में अपरिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

धारा-45

(3) इस परिनियमावली में अध्यापकों की आयु के संबंध में समस्त निर्देश सम्बंधित अध्यापकों की जन्म तिथि के प्रति जो उसके हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में यथा उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्य निर्वाहिक अध्याय-दो

कुलाधिपति	धारा 10 (4)	3-(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 68 के अधीन निर्दिष्ट किया जाये, पर विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिन्हें वह आवश्यक समझें मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं। (2) जहां कुलाधिपति खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांगे, वहां कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसे दस्तावेज या सूचना उन्हें तुरन्त प्रदान की जाए।
कुलपति	धारा 12 एवं 45 (ग)	4-कुलपति को किसी सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के संबंध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे, उसको मांगने की शक्ति होगी।
कुलसचिव	धारा 14(3), 20(1) 7, 20(8) 45 (ग) और (ङ)	5-(1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अध्याधीन कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों पर होगा, जो निम्नलिखित न हों, अर्थात:- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारी; (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वे अध्यापक के रूप में कार्य से सम्बंधित हों या किसी भी पारिश्रमिक अधिकारी के पद पर रहते हुए या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक हों; (ग) पुस्तकालयाध्यक्ष, ; (घ) धारा 17 में निर्दिष्ट अन्य कर्मचारीगण ; (ङ) विश्वविद्यालय के लेखा तथा संपरीक्षा अनुभाग में कर्मचारीगण;

(2) खण्ड (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पवितच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने या उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी को जांच होने तक, यदि कोई हो, निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जांच न कर ली जाये, जिसमें कर्मचारी को उसके विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहां जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति की बाबत अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये, किन्तु उक्त अभ्यावेदन ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा :

परन्तु यह कि खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है) यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था:—

- (क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसके अधिष्ठायी रैंक में प्रतिवर्तित करने का आदेश;
- (ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश;
- (ग) किसी कर्मचारी को उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश;
- (घ) निलम्बन का आदेश।

धारा 20 व
45

(4) परिनियम 6 (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परिनियम 20(1) के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुल सचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 14

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन कुल सचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—

- (क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति 8 का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;
- (ख) धारा 14(4) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के बैठकों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनाएं जारी करना और ऐसी समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;
- (ग) कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के शासकीय पत्र व्यवहार का संचालन करना;
- (घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों के कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनाम पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों का सत्यापन करना;

धारा 9 (घ)

6—(1) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो, तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति नाम निर्दिष्ट करें।

वित्त अधिकारी

- धारा 15 (7) (2) (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;
 (ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है;
 (ग) नकद तथा बैंक में अतिशेष की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत दृष्टि रखेगा;
 (घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा;
 (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जायें और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टॉक की नियमित जांच की जाती हो;
 (च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;
 (छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे, मंगा सकेगा;
 (ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक संपरीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा और ऐसे बिलों की संपरीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;
 (झ) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;
 (ञ) अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन परिनियम 6(1) के खण्ड (2) और (3) के अर्थान्तर्गत विश्वविद्यालय के संपरीक्षा तथा लेखा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा) से निम्न श्रेणी के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।
- धारा 12 (3) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।
- संकायों के संकायाध्यक्ष धारा 27 (3) 7-(1) यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ज्येष्ठतम आचार्य और यदि उस संकाय में कोई आचार्य न हों तो संकायाध्यक्ष का पद सह-आचार्य द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई सह-आचार्य न हो तो उस संकाय में अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता क्रम में धारित किया जायेगा।
- धारा 45 (2) यदि किसी व्यक्ति को उसके पूर्व पद जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष नियुक्त हुआ है, से हटाया जाता है तो वह संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।
- धारा 27 (4) (3) कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक पर, और
 (क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिये संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जायगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और इन परिनियमों के प्रारम्भ में ज्येष्ठता क्रम में पात्र अगला अध्यापक, संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा;
 (ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठता क्रम में अगला अध्यापक, संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।
 (4) ऐसी अवधि की जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ,—

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक ने विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण किया था, उसको निकाल दिया जायेगा;

(ख) जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गयी हो, उस अवधि की गणना संकायाध्यक्ष की पदावधि के प्रयोजनार्थ उसकी बारी अगली बार आने पर की जायेगी, यदि अन्त में यह पाया जाय कि उस अवधि में उस पद को धारण करने का विधिक हक उसे नहीं था।

धारा 18 संकायाध्यक्ष की निम्नलिखित कर्तव्य व शक्तियाँ होंगी:—

(5)

(एक) वह संकाय बोर्ड के समस्त बैठकों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं;

(दो) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(तीन) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा के लिये आवश्यक उपाय करेगा;

(चार) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों के किसी बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

धारा 18 (4)

8—(1) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें अन्यून दस वर्ष का अध्यापन—कार्य का अनुभव हो और जो सह—आचार्य से अनिम्न रैंक के हों, कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी।

छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

धारा 45

(2) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा।

धारा 45

(3) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिये होंगी, जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाये :

परन्तु यह कि इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को संकायाध्यक्ष का पद धारण करने वाला छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष परिनियम 8 (1) के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(4) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता अध्यापकों का (जिनका चयन परिनियमों में निर्धारित रीति से किया जायेगा) एक दल करेगा, जो अध्यापक के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार चुने गये अध्यापक छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे।

(5) छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालयों की महिला अध्यापकों में से नियुक्त किया जायेगा जो बालिका छात्रों की कल्याण की देखभाल करेंगी।

(6) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे छात्रों की ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग दर्शन अपेक्षित है, सामान्यतः सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया छात्रों तथा भावी छात्रों को,—

(क) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने;

(ख) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने;

(ग) निवास स्थान ढूँढने;

(घ) भोजन व्यवस्था करने;

(ङ) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने;

(च) छात्रवृत्तियाँ, वृत्ति का अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने;

(छ) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिए यात्रा—सुविधायें प्राप्त करने;

(ज) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने;

(झ) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहे, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या अध्ययन करने में, उचित रूप से संचालित होने में सहायता करना और सलाह देना।

(7) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसमें उसकी सहायता अपेक्षित हो आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

(8) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो तथा विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायें।

(9) कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

(10) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत करे।

विभागाध्यक्ष

9—(1) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति संभावित सीमा तक चक्रानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार कुलपति द्वारा की जाएगी। ऐसी नियुक्ति से कार्य परिषद् को सूचित किया जाएगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई वरिष्ठ अध्यापक, जो विद्यमान चक्रानुक्रम के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा कर चुके लोगों से वरिष्ठ है या उन कनिष्ठ अध्यापकों से, जो उसी क्षमता में सेवा कर रहे हैं, किसी या अन्य कारणवश विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है, यह कुलपति पर होगा कि वह विभागाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर संबंधित विभाग में वरिष्ठ अध्यापक को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, परन्तु यह कि वह इस रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो।

(3) विभागाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि का होगा। कोई व्यक्ति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(4) खंड (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी विभागाध्यक्ष की नियुक्ति लंबित होने की स्थिति में अथवा अवकाश के कारण अनुपस्थिति की स्थिति में, कुलपति प्रचलित स्थिति का आकलन करने के पश्चात् संबंधित विभाग के आचार्य या सह-आचार्य को विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर यथास्थिति या तो विभाग के प्रमुख के कर्तव्यों का जवाब देने या विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करने का निर्देश दे सकता है।

नोट: वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम का सिद्धांत लागू होगा। कोई अध्यापक जो पहले विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुका है या कर रहा है, उससे अगला वरिष्ठ अध्यापक विभागाध्यक्ष पद का हकदार होगा।

(5) प्रत्येक विभाग का प्रमुख विशेष रूप से संबंधित विभाग का आचार्य होगा। यदि किसी विभाग में केवल एक आचार्य है या किसी आचार्य के पास विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की पात्रता नहीं है, तो किसी सह-आचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और यदि किसी विभाग में कोई आचार्य या सह-आचार्य विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु पात्र नहीं हो, वहां वरिष्ठ अध्यापक संबंधित विभाग के प्रमुख का कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(6) जिन विभागाध्यक्षों ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, उन्हें तुरंत बदल दिया जाएगा और जिन्होंने अभी तक अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है, उन्हें शेष कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् रखा जाएगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

धारा 29
1(ड)

10—(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्य परिषद् द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) कुलपति;

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न संभाले, तब तक कार्य परिषद्, ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी परिनियमों में व्यवस्था की जाय।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय।

(5) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण करना और उसकी सेवा को ऐसी रीति से, जो अध्यापन कार्य और अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना, पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

(6) पुस्तकालयाध्यक्ष, कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा:

परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

धारा 17
और 45

11—(1) कुलानुशासक विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कुलानुशासक कुलपति, को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त समनुदेशित किये जाये।

कुलानुशासक

(2) कुलानुशासक की सहायता के लिए सहायक कुलानुशासक होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जायेगी।

(3) कुलपति कुलानुशासक के परामर्श से सहायक कुलानुशासक नियुक्त करेंगे।

(4) कुलानुशासक और सहायक कुलानुशासक एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु यह कि प्रत्येक कुलानुशासक या सहायक कुलानुशासक जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, उस पद पर बना रहेगा:

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर, कुलानुशासक को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है:

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक कुलानुशासक को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकते हैं।

(5) कुलानुशासक और सहायक कुलानुशासकों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत करें।

12—(1) विश्वविद्यालय में एक कुलानुशासक होगा, जो विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन का प्रभारी होगा।

कुलानुशासक की
शक्तियाँ और
कृत्य

(2) कुलानुशासक की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर होगी जो इस निमित्त कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

(3) कुलानुशासक, कुलपति के नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) किसी छात्र या छात्रों द्वारा अनुशासन के उल्लंघन के ऐसे समस्त मामलों को कुलानुशासक, कुलपति को कार्यवाही के लिए निर्दिष्ट करेगा जो मामले कार्यवाही के लिए उचित समझी जाये। उसके पास किसी भी छात्र से पूछताछ करने और विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति होगी ताकि वह अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हो सके।

(5) कुलानुशासक, विश्वविद्यालय के समारोहों के आयोजन में समय-समय पर आवश्यक सभी सहायता देगा।

(6) जब भी कुलानुशासक द्वारा अपेक्षित हो, छात्रों को अपना पहचान-पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वह छात्रों को पहचान-पत्र जारी करने का प्रभारी भी होगा। उसके पास कुलपति को अर्थदण्ड की अनुशंसा करने की शक्ति होगी।

(7) कुलानुशासक, विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी मामले पर कुलपति को सलाह दे सकता है।

(8) (क) छात्रावास वार्डन, पुस्तकालयाध्यक्ष और कक्षा-अध्यापकों की अधिकारिता में होने वाले अनुशासन के उल्लंघन के मामलों को संबंधित अधिकारी द्वारा सीधे कुलपति को सूचित किया जाएगा।

(ख) इस परिणियमावली के उपबंध पुस्तकालयाध्यक्ष या छात्रावास वार्डन या कक्षा-अध्यापकों को उनकी अधिकारिता के अधीन छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने से वंचित नहीं करते हैं।

(9) कुलानुशासक के पास कुलपति को किसी भी छात्र पर अर्थदण्ड की अनुशंसा करने की शक्ति होगी जो उसकी राय में अनुशासनिक कार्यों में दोषी पाया गया है।

अध्याय-तीन

कार्य-परिषद्	धारा 19	13-(1) संकायों के संकायाध्यक्ष जो धारा 19 के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिणियम 16(1) में प्रगणित हैं।
	धारा 19	(2) धारा 19 के खंड (एक) के अधीन विश्वविद्यालय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार होगा।
	धारा 45	(3) कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का न सदस्य होगा और न तो सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य हो जाये, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्त के दिनोंक से रिक्त कर दिया है, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था।
	धारा 21	(4) कार्य परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें संकल्प में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।
	धारा 20 व 45	(5) कार्य परिषद् की बैठकें कुलपति के निदेश से बुलाई जायेंगी।
	धारा 20 व 45	(6) कार्य-परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसमें वित्तीय विवक्षा अन्तर्ग्रस्त हो, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।
		(7) कार्य परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

अध्याय-चार

विद्यापरिषद्	धारा 22	14-(1) विश्वविद्यालय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व धारा-22 के खंड (तीन) के अधीन अधिनियम के अनुसार होगा।
		(2) कुलपति किसी भी समय स्वयं की पहल पर या विद्या परिषद् के अन्यून 5 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग प्राप्त होने पर कुल सचिव को विद्या परिषद् की बैठक आहूत करने लिए कहेंगे।
		(3) बैठक के समय और स्थान के बारे में अन्यून 3 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाएगी।
		(4) अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
		(5) कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता के लिए एक सदस्य का चुनाव बैठक में से किया जाएगा।
		(6) विद्या परिषद् की समस्त बैठकों में अध्यक्ष का एक मत और निर्णायक मत होगा।
		(7) विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव या संकल्प की सूचना बैठक से अन्यून 14 दिन पूर्व कुलसचिव के पास होनी चाहिए।
		(8) किसी प्रस्ताव या संकल्प में संशोधन की सूचना, जिससे पूर्व में सूचित किया गया हो, विद्या परिषद् की बैठक से कम से कम 7 दिन पूर्व कुलसचिव के पास होना चाहिए, जिस पर प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तुत किया जाना है।

(9) पैरा 14(3) और 14(6) में किसी भी बात के होते हुये भी, अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव जो स्वीकार करने या कार्य करने योग्य हो की अनुमति दे सकता है जिसे प्रस्तुत करने या चर्चा करने के लिए आवश्यक समय सीमा नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, बोर्ड, परिषद, समिति या उप-समिति या ऐसे किसी निकाय की समिति या उप-समिति की किसी सिफारिश या रिपोर्ट पर, और जहां इस अध्याय के पैरा 6 और 7 द्वारा आवश्यक नोटिस देना असंभव हो गया हो, परन्तु यह कि अध्यक्ष को इस बात का समाधान हो गया हो तब विश्वविद्यालय के कार्य को जारी रखने के उद्देश्य से प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय प्राप्त करना आवश्यक है।

(10) कार्य परिषद की बैठकों में किसी कार्य की सूचना और चर्चा से संबंधित विनियमन विद्या परिषद की बैठकों में यथासंभव लागू किया जाएगा।

(11) प्रत्येक वर्ष विद्या परिषद् की एक बैठक होगी जिसे वार्षिक बैठक कहा जायेगा।

(12) मानद उपाधियाँ प्रदान करने के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:—

(क) विद्या परिषद की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित करने से पहले मानद उपाधि प्रदान करने के प्रत्येक प्रस्ताव को कुलपति की सदस्यता वाली एक समिति को विचार हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) समिति तब विचार करेगी यदि प्रस्तावित व्यक्ति,—

(एक) अपनी शिक्षा/कला हेतु प्रतिष्ठित है; या

(दो) ने शिक्षा/कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएँ दी हैं; या

(तीन) ने अपनी दानशीलता से शिक्षा/कला के निमित्त का वर्धन किया है; या

(चार) ने अन्य प्रकार से उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा की है, और अन्यथा उपाधि प्रदान हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है।

इस प्रकार के विचार के पश्चात यदि यह प्रस्ताव विद्या परिषद की स्वीकृति के लिए अनुशंसित की जाती है तो इसका प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ विद्या परिषद के समक्ष रखी जाएगी।

(ग) यदि समिति के विचार में प्रस्ताव से संबंधित सभी अग्रतर कार्यवाही को निरस्त करना उचित है, तो प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य को ऐसे विचार से अवगत कराया जाएगा और मामले में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि वह लिखित रूप में इसकी पुष्टि न कर दे कि जिस स्थिति में प्रस्ताव को उस विषय पर समिति की कार्यवाही के साथ विद्या परिषद के समक्ष रखा जाएगा उसी स्थिति में उसका प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है।

(घ) मानद उपाधि प्रदान करने के सभी प्रस्तावों पर (एक) बिना चर्चा के और (दो) मतपत्र द्वारा मतदान किया जाएगा।

(ङ) विद्या परिषद द्वारा मानद उपाधि प्रदान करने के किसी भी प्रस्ताव को तब तक पारित घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अन्यून 2/3 सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में मतदान न कर दे।

अध्याय—पाँच

धारा 15—(1) व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में वित्त समिति सम्मिलित न हों, निम्नलिखित दशाओं में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी :—
24, 25,
26 व 45

(एक) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें दस हजार रुपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्गस्त हो; और

(दो) आवर्ती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रुपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्गस्त हो:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह किसी ऐसे मद को जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हो, छोटी-छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करें और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करें।

धारा (2) वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा कि परिनियम द्वारा इस निमित्त
24, 25, उपबंधित किया जाय, परिनियम 15 (1) अथवा परिनियम 15 (3) के अधीन उसको
26 व निर्दिष्ट की गई व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी
45 सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

(3) यदि कार्य परिषद्, वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम 15(1)में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

(4) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान, वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो।

(6) वित्त समिति की बैठकें कुलपति के निदेश के अधीन बुलायी जायेंगी और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसी बैठकों को बुलाने के लिए सभी नोटिस वित्त अधिकारी द्वारा जारी की जायेंगी जो सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा।

अध्याय—छह

संकाय/अध्ययन विभाग धारा27(1)

16—(1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे अर्थात्:

- (एक) संगीत
- (दो) नृत्य
- (तीन) दृश्य कला
- (चार) कला और भाषा
- (पांच) लोक संगीत और कला

2—अध्ययन विभाग—

(एक) संकायों में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अध्ययन विभाग निम्नानुसार होंगे:—

1—संगीत संकाय

- (एक) स्वर संगीत विभाग (हिन्दुस्तानी)
- (दो) वाद्य संगीत विभाग
- (तीन) ताल वाद्य विभाग

2—नृत्य संकाय

- (एक) कथक नृत्य विभाग
- (दो) भरतनाट्यम नृत्य विभाग
- (तीन) मणिपुरी नृत्य विभाग

3—दृश्य कला संकाय

- (एक) चित्रकला विभाग
- (दो) मूर्तिकला विभाग
- (तीन) ग्राफिक्स विभाग
- (चार) अनुप्रयुक्त कला विभाग
- (पांच) कला इतिहास व सौंदर्यशास्त्र विभाग
- (छः) शिल्प एवं डिजाइन विभाग।

4—कला व भाषा संकाय

- (एक) हिन्दी विभाग
- (दो) अंग्रेजी विभाग
- (तीन) संस्कृत विभाग
- (चार) प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति व पुरातत्व विभाग
- (पांच) जीवनपर्यन्त अधिगम विभाग
- (छः) नाट्य विभाग
- (सात) योग केंद्र
- (आठ) दर्शनशास्त्र विभाग

5—लोक संगीत व कला संकाय

- (एक) लोक संगीत विभाग
- (दो) लोक नृत्य विभाग

17-(1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:-

संकायों का गठन
और कृत्य

- (एक) संकाय के संकायाध्यक्ष;
 - (दो) उस संकाय के अध्ययन विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष;
 - (तीन) संकाय के समस्त आचार्य;
 - (चार) संकाय में प्रत्येक अध्ययन विभाग से चक्रानुक्रम वरिष्ठता के अनुसार एक सह-आचार्य और एक सहायक आचार्य;
 - (पांच) स्नातक अध्ययन तक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में से ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से दो सह-आचार्य;
 - (छः) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से तीन अध्यापक;
 - (सात) संकाय के प्रत्येक विभाग से एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हो और विषय का विशेष ज्ञान रखता हो व संकाय द्वारा सहयोजित हो;
 - (आठ) संकाय के किसी भी विषय का विशेष ज्ञान होने के कारण विद्या परिषद द्वारा चुने गए दो बाह्य सदस्य।
- (2) अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन संकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

- 1-विद्या परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन संकाय को सौंपे गए विषयों का विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित करने के लिए।
 - 2-अध्ययन विभागों से परामर्श के पश्चात विद्या परिषद को विभिन्न परीक्षाओं हेतु अध्ययन पाठ्यक्रमों को अनुशंसित करना।
 - 3-विद्या परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विशिष्ट पुरस्कारों हेतु शर्तों को विनियमित करना।
 - 4-विद्या परिषद द्वारा निर्दिष्ट अथवा अध्यादेशों और विनियमों द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले से निपटना।
- (3) उपर्युक्त गठन में वर्णित संकाय की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी।

18-अध्ययन बोर्ड का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:-

अध्ययन बोर्ड

- (क) संबंधित संकायाध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
- (ख) विश्वविद्यालय के उन विषयों के विभागाध्यक्ष जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया है।
- (ग) विश्वविद्यालय के विभागों से एक आचार्य और एक सह-आचार्य जो उन विषयों का अध्यापन करते हैं, उन्हें ज्येष्ठता के अनुसार कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (घ) विषयों के दो से अनधिक सहायक आचार्य जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (ङ) बोर्ड द्वारा सहयोजित एक सदस्य जो बाह्य विषय विशेषज्ञ होगा।
- (च) अध्ययन बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- (छ) तीन सदस्यों से गणपूर्ति की जा सकती है, जिसमें एक बाह्य विषय विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है।

अध्याय-सात

धारा-76

19-अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी समय-समय पर ऐसी और इतनी मात्रा में स्थायी समितियों या उप-समितियों या बोर्डों का गठन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे तो उन्हें नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे प्राधिकरणों के सदस्य नहीं हैं। ऐसी समितियाँ या बोर्ड उन्हें प्रत्यायोजित किये गए किसी भी विषय का निपटारा कर सकते हैं, जो उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टीकरण के अध्यधीन हो।

स्थायी समितियाँ

अनुशासनिक
समितियाँ

धारा 45

20—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति, या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रति कुलपति और उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति सम्मिलित होंगे:

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् इसे समीचीन समझती है, तो वह विभिन्न मामलों या मामलों की श्रेणियों पर विचार करने हेतु एक से अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकती है।

(2) कोई भी अध्यापक जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़ा कोई मामला लंबित है तो वह उस मामले से निपटने वाली अनुशासनात्मक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद् किसी भी प्रक्रम पर, एक अनुशासनिक समिति के किसी मामले को दूसरी अनुशासनिक समिति को अन्तरित कर सकती है।

धारा 45

(4) (1) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) परिनियमावली के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े मामलों की जांच करना;

(ग) उपर्युक्त उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध जांच लंबित होने या विचाराधीन होने पर उसे निलंबित करने की अनुशंसा करना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(2) समिति के सदस्यों में, मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(3) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट, यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी जिससे कार्य परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

धारा 45

(4) परिनियम 9(1) के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागीय समिति होगी।

धारा 45

(5) विभागीय समिति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे:—

(एक) विभागाध्यक्ष, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) विभाग के समस्त आचार्य और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त सह-आचार्य।

(तीन) जिस विभाग में आचार्य के साथ-साथ सह-आचार्य भी न हो, वहां तीन वर्ष की अवधि हेतु ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम के अनुसार दो सहायक आचार्य होंगे:

परन्तु यह कि किसी विषय या विद्या — विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिये उस विषय या विद्या — विशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषतः आमन्त्रित किया जायेगा।

(6) विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(एक) विभाग के अध्यापकों के बीच अध्यापन कार्य के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना।

(दो) विभाग में अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना।

(तीन) उस विभाग में ऐसे कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करना जिसके लिए विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी है।

(चार) विभाग के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना।

- धारा 45 (7) समिति की बैठक एक तिमाही में कम से कम एक बार होगी। इसकी बैठक के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- धारा 45 21-परीक्षा समिति धारा-29 में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप-समिति की सिफारिश पर, किसी परीक्षार्थी को तीन वर्षों की अवधि के लिए आगामी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकती है, यदि समिति की राय में, ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में कदाचार या अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाया जाता।

परीक्षा समिति

अध्याय-आठ

- धारा 29 एवं 46 22-(1) कला और भाषा, संगीत, नृत्य, दृश्य कला और लोक संगीत और कला संकायों में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :-
- (1) आचार्य;
- (2) सह-आचार्य;
- (3) सहायक आचार्य;
- धारा 29 एवं 46 (2) विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे। अनुसंधान सहचर या अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।
- धारा 29 (3) कार्य परिषद, विद्या परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है।
- (4) इस निमित्त परिनियमों/अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।
- (5) अवैतनिक प्रतिष्ठित (एमिरिटस) आचार्य, जो-
- (क) विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;
- (ख) अनुसंधान- कार्य का मार्ग दर्शन करेंगे;
- (ग) सम्बद्ध संकाय बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के हकदार होंगे और उसके विचार-विमर्श में भाग लेंगे, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;
- (घ) जिन्हें यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में अध्ययन और अनुसंधान कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेगी; और
- (ङ) समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे:
- परन्तु यह कि कोई व्यक्ति विभाग में अवैतनिक प्रतिष्ठित (एमिरिटस) आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।
- (6) (क) अनुदेशक या अध्यापन अनुसंधान सहायक, ऐसी शर्तों और निबन्धनों जैसा कि परिनियम/अध्यादेशों में उपबंध किया जाय, पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।
- 23-विद्या परिषद की अनुशंसा पर उनकी अध्येतावृत्ति और उच्च बौद्धिक उपलब्धियों के लिए कार्य परिषद द्वारा नियुक्त मानद आचार्य या सह-आचार्य के पास निम्नलिखित कृत्य और विशेषाधिकार होंगे:-
- (क) कृत्य-
- 1-एक शैक्षणिक वर्ष में अपने विषय के कुछ क्षेत्रों पर या तो नई व्याख्या के माध्यम से या नए अभिविन्यास के माध्यम से या अपने विषय में नई प्रवृत्तियों पर कम से कम 6 व्याख्यान माला देना।
- 2-छात्रों को उनकी प्रायोगिक कक्षाओं में मार्गदर्शन करना।
- 3-मान्यता प्राप्त आचार्य की हैसियत से अनुसंधान कर्मियों का मार्गदर्शन करना और मान्यता प्राप्त आचार्य या सह-आचार्य के रूप में अपने विषय में विशेष व्याख्यानमाला प्रदान करना।
- (ख) विशेषाधिकार -
- (एक) मानद आचार्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का सदस्य होगा लेकिन वह किसी भी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन से सम्बन्धित नहीं होगा और विश्वविद्यालय के किसी भी निकाय में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

अध्यापकों का वर्गीकरण

मानद आचार्य की नियुक्ति, उनके निबन्धन व शर्तें

(दो) उन्हें विश्वविद्यालय में उनके भ्रमण की अवधि में उपलब्ध आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और वे समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय के हकदार होंगे।

(तीन) मानद आचार्य या सह-आचार्य को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय—नौ

भाग—एक

अध्यापक की
न्यूनतम योग्यता

24—विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्य तथा अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण।

(1) व्याप्ति—

उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने और वेतनमान की पुनरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों और पुस्तकालयाध्यक्ष के संवर्गों में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों हेतु न्यूनतम अर्हता।

(2) विश्वविद्यालय अध्यापक से संबंधित विधा में अध्यापन पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ,—

(एक) परन्तु यह कि उस स्थिति में जहां परिनियम द्वारा कोई मानदंड या मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, उस स्थिति में यू0जी0सी0 विनियम उस समय तक लागू होंगे जब तक कि विनियामक प्राधिकारी द्वारा कोई मानक या मानदंड निर्धारित नहीं किये जायें।

(दो) परन्तु अग्रतर यह कि उन विधाओं, जिनमें सहायक आचार्य और समतुल्य पदों पर नियुक्ति राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के माध्यम से की गई हो, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द्वारा किया गया हो अथवा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी), जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ यू0जी0सी0 द्वारा प्रत्यायित निकायों द्वारा आयोजित किया गया हो उनमें एनईटी/एसईएलटी/एसईटी में अर्हता प्राप्त करना एक अतिरिक्त अपेक्षा होगी।

वेतनमान तथा वेतन निर्धारण—

वेतनमान तथा
वेतन निर्धारण

25—(1) वेतनमान के पुनरीक्षण को कार्यान्वित किये जाने की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2016 होगी।

भर्ती तथा अर्हताएं—

भर्ती तथा
अर्हताएं

26—(1) विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य और वरिष्ठ आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर इस परिनियम के अधीनकृत उपबंधों के अनुसार विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा।

(2) इस परिनियम में सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं अपेक्षित होंगी।

(3) (एक) जहां कहीं भी इस परिनियम में यह उपबंधित हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा प्रत्यायित परीक्षा (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एसएलईटी/एसईटी) सहायक आचार्य और समकक्ष पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त एसएलईटी/एसईटी सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में विधिमिन्य होगा:

परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, को विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य या समकक्ष पद पर भर्ती या नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:

परन्तु अग्रतर यह कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबन्धों द्वारा अभिशसित होगा। ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधधीन विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी /एसएलईटी /एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की जाएगी।

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध कम से कम दो वाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

(दो) ऐसे विषयों में एनईटी / एसएलईटी / एसईटी को उत्तीर्ण करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनके लिए एनईटी /एसएलईटी / एसईटी आयोजित नहीं की गई हो।

(4) किसी भी स्तर पर अध्यापकों और अन्य समकक्ष संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए निष्णात स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) अनिवार्य अर्हता होगी।

(एक) सीधी भर्ती हेतु पात्रता के प्रयोजनार्थ और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) (असंपन्न वर्ग)/ निःशक्त (क) दृष्टिहीनता तथा निम्न दृश्यता (ख) बधिर और कम सुनाई देना (ग) लोकोमोटर निःशक्तता जिसमें सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मरक्यूलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता (ङ) गूंगापन—अंधापन सहित (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट केवल रियायती अनुकम्पा अंक प्रक्रिया को सम्मिलित किये बिना अर्हकारी अंक पर अनुज्ञेय होगी।

(5) उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।

(6) एक सुसंगत ग्रेड जिसे 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी विधिमान्य माना जाएगा।

(7) आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(8) सह-आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(9) विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(10) दिनांक 01 जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(11) अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए दावे हेतु एमफिल और/अथवा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय को अध्यापन/अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश लिए बिना अध्यापन कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा अवधि को सीधी भर्ती/पदोन्नति के उद्देश्य के लिए अध्यापन अनुभव माना जाएगा कुल संकाय संख्या (चिकित्सा/मातृत्व छुट्टी पर गए संकाय सदस्यों के अलावा) के बीस प्रतिशत तक नियमित आधार पर कार्यरत संकाय सदस्यों को उनकी संबंधित संस्थाओं द्वारा पीएचडी की उपाधि के लिए अध्ययन छुट्टी लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

अर्हताएं

अर्हताएं:—

27—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति इस परिणियम में उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।

सीधी भर्ती:—

सीधी भर्ती

28—(1) कला, मानविकी, और भाषा विधाओं के लिए

(एक) सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क—(एक) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

(दो) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो उन्हें एनईटी /एसएलईटी/एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:

परन्तु यह कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे और ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:—

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड) अभ्यर्थी ने यू0जी0सी0/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी अन्य समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;
इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट: उन विषयों में ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी का आयोजन यूजीसी, सीएसआईआर या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/एसईटी नहीं किया जाता है।

अथवा

किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान जिसकी रैंकिंग विश्व के विश्वविद्यालय रैंकिंग में (किसी भी समय) शीर्ष 500 में हो जो निम्नलिखित में किसी एक द्वारा प्रदत्त हो—

(ख) क्वेक्वरेली सायमंड (क्यूएस) (दो) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई) अथवा (तीन) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू) से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गयी हो।

नोट: परिशिष्ट (दो) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांक केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

दो सह-आचार्य:

सह-आचार्य:

पात्रता

(एक) संबंधित/संबद्ध/सुसंगत विधाओं में पीएचडी की उपाधि के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड।

(दो) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(तीन) किसी भी शैक्षणिक / अनुसंधान पद पर शिक्षण और / अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान / उद्योग में सहायक आचार्य के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यू0जी0सी0 सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात शोध पत्र प्रकाशित हो और परिशिष्ट दो तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अनुसंधान प्राप्तांक हो।

तीन आचार्य:

आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क— (एक) कोई प्रतिष्ठित विद्वान जिसे संबंधित /संबद्ध /सुसंगत विधा में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ— साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से अभिनियोजित हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस प्रकाशन और परिशिष्ट —दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हों।

(दो) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आचार्य/सह-आचार्य /आचार्य स्तर पर न्यूनतम दस वर्ष का अध्यापन अनुभव और /अथवा विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डाक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

अथवा

ख— कोई उत्कृष्ट वृत्तिक जिसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान (उपर्युक्त 'क' में सम्मिलित नहीं)/ उद्योग से सुसंगत/ संबद्ध/ अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने संबंधित/संबद्ध /सुसंगत विधा के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें यह उपबंधित हो कि उसे दस वर्षों का अनुभव है, से समर्थित हो।

विश्वविद्यालय में
वरिष्ठ आचार्य

चार विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य

विश्वविद्यालय में आचार्यों की विद्यमान संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत संख्या तक सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।

पात्रता

पांच पात्रता:

(एक) कोई प्रतिष्ठित विद्वान जिसका समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रकाशन का अच्छा निष्पादन रिकार्ड हो तथा इन विधाओं में महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान और अनुसंधान पर्यवेक्षण किया हो।

(दो) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी संस्थान में आचार्य के रूप में अथवा समतुल्य ग्रेड में अध्यापन / अनुसंधान का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।

(तीन) यह चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, तीन प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ आचार्य के पद से कम न हो, अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभव वाले आचार्य की अनुकूल समीक्षा पर आधारित होगा।

(चार) यह चयन समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में सर्वोत्तम दस प्रकाशनों और यूजीसी विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के साथ सहक्रिया के साथ— साथ पिछले 10 वर्षों के दौरान उनकी पर्यवेक्षण में कम से कम दो अभ्यर्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदत्त किए जाने पर आधारित होगा।

29—संगीत, परफार्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परंपरागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि।

सहायक
आचार्य:
पात्रता

एक सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क— (एक) किसी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कही भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(दो) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी / एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल / पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

परन्तु अग्रतर यह कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:—

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड) अभ्यर्थी ने यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएसएसआर अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हों।

नोट 1: इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।

नोट 2: ऐसी विधाओं में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी/एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख— एक परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विधा में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने—

(एक) प्रसिद्ध परंपरागत उस्ताद (उस्तादों)/कलाकार (कलाकारों) के अधीन अध्ययन किया हो;

(दो) वह आकाशवाणी /दूरदर्शन में श्रेणी 'क' का कलाकार रहा हो;

(तीन) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

(चार) संबंधित विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

दो सह—आचार्य

पात्रता (क अथवा ख):

क— (एक) डॉक्टोरल उपाधि के साथ उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड।

(दो) उच्च वृत्तिक मानक के साथ कार्य निष्पादन क्षमता।

(तीन) किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य में आठ वर्ष का अनुभव और/अथवा किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव जोकि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आचार्य के समतुल्य हो।

(चार) उन्होंने गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख— एक परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि हो और जिन्हें संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो, जो

(एक) आकाशवाणी/दूरदर्शन में श्रेणी 'क' का कलाकार रहा हो;

(दो) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

(तीन) नए पाठ्यक्रम और/अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो;

(चार) प्रसिद्ध संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/संगीत गोष्ठियों में भाग लिया हो; और

(पांच) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

सह—आचार्य
पात्रता

आचार्यः
पात्रता

तीन आचार्यः

पात्रता (क अथवा ख):

क—(एक) डॉक्टरल उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान ।

(दो) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन और /अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ सक्रिय रूप से अभिनियोजित हो ।

(तीन) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम 6 अनुसंधान प्रकाशित हुआ हो ।

(चार) परिशिष्ट —दो के अनुसार अनुसंधान में कुल 120 प्राप्तांक हो ।

अथवा

ख— एक परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो,

(एक) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो,

(दो) आकाशवाणी/दूरदर्शन में श्रेणी 'क' का कलाकार रहा हो;

(तीन) विशेषज्ञता के क्षेत्र में दस वर्ष का उत्कृष्ट कार्य निष्पादन की उपलब्धि रही हो;

(चार) विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और अनुसंधान में मार्गदर्शन करने की क्षमता हो;

(पांच) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों /सम्मेलनों/ कार्यशालाओं/ संगीत गोष्ठियों में भागीदारी की हो और/अथवा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार /अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हो;

(छः) संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

(सात) उक्त विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो ।

नाट्य विधा:
सहायक आचार्य

30—नाट्य विधा:

एक सहायक आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क. (एक) भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्कूल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।

(दो) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्राप्त किये हों ।

अग्रतर यह कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी —

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ;

(ड.) अभ्यर्थी ने यूजीसी/सीएसआईआर/आईसीएसएसआर अथवा ऐसी किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो शोध पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

नोट 1—इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए।

नोट 2—ऐसी विधाओं में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. संबंधित विषय में उच्च उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रखने वाला कोई परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार, जिसके पास:

(एक) भारतीय नाट्य विद्यालय अथवा भारत या विदेश में किसी अन्य ऐसे ही संस्थान से 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड के साथ तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ वृत्तिक कलाकार रहा हो;

(दो) साक्ष्य सहित, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांच वर्ष का नियमित रूप से प्रशंसनीय कार्यनिष्पादन रहा हो; और

(तीन) संबंधित विषय की तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो और संबंधित विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत को पढ़ाने की पर्याप्त जानकारी हो;

दो—सह-आचार्य:

सह-आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

पात्रता

क. (एक) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुप्रमाणित उच्च वृत्तिक मानकों के कार्यनिष्पादन की क्षमता के साथ पीएचडी की उपाधि सहित उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड रहा हो।

(दो) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन कार्य में और/अथवा किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में शोध कार्य में आठ वर्ष का अनुभव रहा हो जोकि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सहायक आचार्य के समतुल्य हो।

(तीन) गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख. कोई परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो और जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो, जो:-

(एक) रंगमंच/रेडियो/टेलीविजन में मान्यता प्राप्त कलाकार रहा हो;

(दो) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्य निष्पादन उपलब्धि रहा हो;

(तीन) नए पाठ्यक्रम और/अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो;

(चार) प्रख्यात संस्थाओं में संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया हो; और

(पांच) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

आचार्य

तीन- आचार्य

पात्रता

(क अथवा ख)

क. डॉक्टरेट की उपाधि सहित अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से अभिनियोजित प्रख्यात विद्वान हो और विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धियों के साथ डॉक्टरेट स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन प्रदान करने में अनुभव सहित विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अध्यापन और/अथवा अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव हो साथ ही समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 5 अनुसंधान प्रकाशन एवं परिशिष्ट – दो तालिका –2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार शोध में कुल 120 अंक प्राप्त किए हो।

अथवा

ख. कोई परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो और जिनके पास:

(एक) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो;

(दो) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में दस वर्ष की उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

(तीन) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया हो;

(चार) अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान किया हो;

(पांच) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी की हो और/अथवा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हो;

(छ:) संबंधित विषय को तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो;

(सात) उक्त विधा में दृष्टांत सहित सिद्धांत को पढ़ाने हेतु पर्याप्त ज्ञान हो।

योग विधा

सहायक आचार्य:

पात्रता

31—योग विधा

एक—सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख)

क. अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड के साथ, योग अथवा किसी अन्य सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

अथवा

ख. किसी भी विधा में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप योग में पीएचडी उपाधि।

***नोट:** योग के इस नए उभरते क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प दिया गया है और यह इस परिनियम के अधिसूचना के दिनांक से केवल पांच वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगा।

दो-सह-आचार्य

आचार्य

(एक) संबंधित विषय अथवा सुसंगत विषय में पीएचडी उपाधि के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड।

(दो) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(तीन) किसी शैक्षणिक/अनुसंधान पद जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/उद्योग में सहायक आचार्य के समतुल्य हो, में प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन कार्य और/अथवा अनुसंधान का अनुभव हो और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में पुस्तकों और/अथवा अनुसंधान/नीति-पत्रों के रूप में कम से कम सात प्रकाशन किए हो और परिशिष्ट- दो तालिका- 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम कुल पचहत्तर (75) अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

तीन-आचार्य:

आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क. (एक) संबंधित विषय या किसी सहबद्ध/सुसंगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से अभिनियोजित हो और प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में पुस्तकों और/अथवा नीति-पत्रों के रूप में कम से कम दस प्रकाशन किए हो और परिशिष्ट दो तालिका- 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम कुल 120 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

(दो) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्षों का अध्यापन अनुभव और/अथवा विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों/ उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव हो और डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

अथवा

ख. सुसंगत क्षेत्र में प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट वृत्तिक जिन्होंने प्रत्यायन द्वारा अभिपुष्टि किए जाने वाले संबंधित/सहबद्ध/सुसंगत विषय में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

32-विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष और विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं।

एक-(एक) विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्षविश्वविद्यालय
सहायक
पुस्तकालयाध्यक्ष

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य वृत्तिक उपाधि।

(दो) पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत रूप से अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड।

(तीन) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को यूजीसी सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय - समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

परन्तु यह कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के विद्यमान अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी-

क. अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

ख. पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

ग. पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ. अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

ङ. अभ्यर्थी ने यूजीसी-आईसीएसएसआर-सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित-वित्तपोषित-सहायता प्राप्त सम्मेलनों-विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

नोट-(एक)-इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

(दो) ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में एनईटी / एसएलईटी / एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा एनईटी / एसएलईटी / एसईटी अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एसएलईटी / एसईटी आयोजित नहीं की जाती हो।

दो-(एक) विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष-

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।

(दो) सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में आठ वर्षों का अनुभव।

(तीन) पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

(चार) पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान / अभिलेख और पुस्तकालय की पांडुलिपियों का रखरखाव / कंप्यूटरीकरण करने में पीएचडी की उपाधि।

तीन-(एक) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष-

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।

(दो) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में किसी भी स्तर पर पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कम से कम दस वर्षों का अनुभव अथवा पुस्तकालय विज्ञान में सहायक/सह-आचार्य के रूप में दस वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा किसी महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में दस वर्षों का अनुभव।

(तीन) किसी पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

(चार) पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान/अभिलेख और पुस्तकालय की पांडुलिपियों का रखरखाव / कंप्यूटरीकरण करने में पीएचडी की उपाधि।

भाग - दो

चयन समिति और चयन प्रक्रिया

33-चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश:

(1) चयन समिति की संरचना

एक-विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य-

क. विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति अन्तर्विष्ट होंगे:

(एक) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलाधिपति द्वारा आचार्य से अनिम्न रैंक के शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय उप
पुस्तकालयाध्यक्ष

विश्वविद्यालय
पुस्तकालयाध्यक्ष

चयन समिति और
चयन प्रक्रिया
विश्वविद्यालय में
सहायक आचार्य

(चार) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष।

(पांच) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

(छः) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निःशक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

ख. दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

दो-विश्वविद्यालय में सह-आचार्य-

विश्वविद्यालय में
सह-आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में सह-आचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(एक) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलाधिपति द्वारा आचार्य से अनिम्न रैंक के शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जायेगा।

(चार) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष।

(पांच) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

(छः) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निःशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो कुलपति द्वारा इन श्रेणियों से किसी शिक्षाविद को नामनिर्देशित किया जायेगा।

ख. दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

तीन- विश्वविद्यालय में आचार्य

विश्वविद्यालय में
आचार्य

क. विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति अन्तर्विष्ट होंगे:

(एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलाधिपति द्वारा आचार्य से अनिम्न रैंक के शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय /क्षेत्र में तीन विशेषज्ञों का नामनिर्देशन किया जायेगा।

(चार) संकाय का संकायाध्यक्ष।

(पांच) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

(छह) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निःशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो कुलपति द्वारा इन श्रेणियों से किसी शिक्षाविद को नामनिर्देशित किया जायेगा।

वरिष्ठ आचार्य

ख. दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

चार-वरिष्ठ आचार्य-

क. विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति अन्तर्विष्ट होंगे:-

(एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कोई शिक्षाविद, जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो और वह वरिष्ठ आचार्य/आचार्य अनिम्न रैंक का हो, जो कुलाधिपति का नामनिर्देशनी होगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञों का नामनिर्देशन, जो वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक के होंगे और उनके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा।

(चार) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष (न्यूनतम दस वर्षों के अनुभव के साथ वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक)।

(पांच) संबंधित विभाग का अध्यक्ष (वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक का होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा) अथवा वरिष्ठतम आचार्य (वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक का होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा)।

(छः) शिक्षाविद (वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक का होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि चयन समिति में कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

पांच-पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समितियां क्रमशः आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के समान ही होगी, और सिवाय कि पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष चयन समिति में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध होंगे।

छः-सहायक आचार्य/पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष संवर्गों में एक स्तर से उच्चतर स्तर में सीएस प्रोन्नति के लिए 'छानबीन सह मूल्यांकन समिति' निम्नानुसार होगी:

क. विश्वविद्यालय के अध्यापकों हेतु-

(एक) कुलपति, समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष;

(तीन) संबंधित विभाग का अध्यक्ष; और

(चार) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ के पैनलों में से संबंधित विषय के एक विषय विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) छानबीन सह मूल्यांकन समिति, इन विनियमों के आधार पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि प्रारूप के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेडों का सत्यापन/मूल्यांकन कर:

(क) सहायक आचार्य के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट दो तालिका -1 में, और

(ख) पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट दो तालिका -4 में;

कार्य परिषद् को कार्यान्वयन हेतु सीएस के अधीन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की प्रोन्नति की उपयुक्तता के विषय में सिफारिश करेगी।

विश्वविद्यालय के
अध्यापक

(3) चयन प्रक्रिया को चयन समिति की बैठक के दिन अंतिम दिन ही पूरा किया जाएगा, जहां कार्यवृत्त अभिलिखित किया जायेगा और साक्षात्कार में किए गए निष्पादन के आधार पर अनुशंसा की जाएगी जिस पर चयन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी चयन समितियों के लिए विभागाध्यक्ष को जिस रैंक/पद के लिये साक्षात्कार आयोजित किया जाना है, उसके समकक्ष अथवा उच्चतर रैंक/पद में होना चाहिए।

ख-विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु:-

विश्वविद्यालय
सहायक
पुस्तकालयाध्यक्ष

(एक) कुलपति, समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संकाय का संकायाध्यक्ष;

(तीन) पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पुस्तकालय और

(चार) विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ जो कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष हो।

नोट:-समस्त श्रेणियों में इन समितियों के लिये तीन सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी, जिसमें एक विषय विशेषज्ञ/विश्वविद्यालय का नामनिर्देशित सम्मिलित होगा।

34-चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

एक-समग्र चयन प्रक्रिया में आवेदकों के गुणावगुण और प्रत्ययपत्रों के विश्लेषण की पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय प्रविधि सम्मिलित होगी जो विभिन्न सुसंगत मानदंडों में अभ्यर्थी के निष्पादन को दिए गए भारांक और परिशिष्ट दो तालिका - 1, 2, 3 और 4 के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली प्रोफार्मा में उनके निष्पादन पर आधारित होगा। प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वविद्यालय साक्षात्कार के स्तर पर अध्यापन और अथवा शोध में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में संगोष्ठियों अथवा कक्षा की स्थिति में व्याख्यान के माध्यम से अध्यापन की योग्यता और अथवा अनुसंधान अभिवृत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। जहां कहीं इन परिनियम में चयन समितियां विहित की गई हैं, वहां यह प्रक्रियाएं सीधी भर्ती और सीएसए प्रोन्नति दोनों के लिए अपनाई जा सकती है।

दो-विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों के लिए परिशिष्ट दो तालिका 1, 2, 3 और 4 को समाहित करते हुए अपने संबंधित सांविधिक निकायों के माध्यम से परिनियम चयन समितियों और चयन प्रक्रिया को अपनाएगा। विश्वविद्यालय इन परिनियम में विनिर्दिष्ट परिशिष्ट दो तालिका 1, 2, 3 और 4 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अध्यापकों के लिए अपना स्व-मूल्यांकन-सह निष्पादन समीक्षा प्रपत्र तैयार कर सकती है।

तीन-यदि विश्वविद्यालय में अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए इसमें उपबंधित समस्त चयन समितियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं/निःशक्त श्रेणियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कुलपति द्वारा उक्त श्रेणियों से संबंध रखने वाले किसी शिक्षाविद को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु इस प्रकार नामनिर्दिष्ट शिक्षाविद आवेदक के संवर्ग के स्तर से एक स्तर ऊपर का होगा और ऐसा नामनिर्देशित यह सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त श्रेणियों संबंधित राज्य सरकार के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

चार-आचार्य के चयन की प्रक्रिया में इस अध्याय के परिशिष्ट दो तालिका 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन आमंत्रित करना तथा अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण करना सम्मिलित है:

परन्तु यह कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकाशन को अर्हक अवधि के दौरान प्रकाशित किया गया हो:

परन्तु अग्रतर यह कि साक्षात्कार किए जाने से पूर्व ऐसे प्रकाशनों को मूल्यांकन हेतु विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रकाशनों के मूल्यांकन को चयन के निष्कर्षों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

पांच-ऐसे संकाय सदस्यों के चयन के मामले में, जो शैक्षणिक क्षेत्र के बाहर से हों तथा जिन पर इस अध्याय के खंड 4.1 (तीन ख), 4.2 (एक ख. दो ख. तीन ख). 4.3 (एक, दो, तीन ख) और 4.4 (तीन ख) के अधीन विचार किया गया हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे उत्कृष्ट वृत्तिक जो विश्वविद्यालयी ज्ञान प्रणाली में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं, उनका चयन किया जाय।

छ:-कतिपय विधाओं/क्षेत्रों यथा संगीत तथा ललित कला, विज्ञान आर्ट्स तथा परफार्मिंग आर्ट्स, और पुस्तकालय जिनमें भिन्न स्वरूप के उत्तरदायित्व होते हैं, से अन्तर्ग्रस्त पदों के चयन प्रक्रिया में, इस अध्याय के विनियम में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित दायित्वों के स्वरूप पर बल दिया जाना चाहिए जिस पर सीधी भर्ती तथा सीएएस प्रोन्नति दोनों के लिए प्ररूप को विकसित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

सात-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) दिशानिर्देशों के अनुसार कुलपति की अध्यक्षता में समस्त विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना की जाएगी। आईक्यूएसी, विश्वविद्यालय के लिए प्रलेखन तथा अभिलेखों का रखरखाव करने वाले प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा जिसमें इस अध्याय के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि प्ररूप विकसित करने में सहायता प्रदान करना सम्मिलित हैं। जहां कहीं भी संभव हो, आईक्यूएसी संस्थागत मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि प्ररूप में प्रत्येक अध्यापक के संबंध में छात्र के मूल्यांकन के घटक को सम्मिलित नहीं करते हुए एनएएसी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर सकता है।

क. सीएएस प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नवत मानदंडों पर आधारित है:

(एक) अध्यापन- ज्ञान अर्जन और मूल्यांकन: कक्षा में नियमित रूप से आने, कक्षा में समय पर आने, कक्षा के समय में या उसके बाद सुधारात्मक अध्यापन और संशय मिटाने, परामर्श और मार्गदर्शन, जब आवश्यकता हो तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में सहायता हेतु अतिरिक्त अध्यापन इत्यादि जैसे ध्यान देने योग्य संकेतकों पर आधारित अध्यापन की वचनबद्धता, परीक्षा और मूल्यांकन कार्यकलाप जैसे परीक्षा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करना, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाना, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भाग लेना, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं संचालित करना।

(दो) अध्यापन और शोध कार्यकलापों से संबंधित व्यक्तिगत विकास: प्रबोधन/पुनश्चर्या/कार्यविधि पाठ्यक्रम में भाग लेना, ई - विषयवस्तु और एमओओसी का विकास, संगोष्ठियाँ/सम्मलेनों/कार्यशालाओं का आयोजन/पत्र प्रस्तुत करना और सत्रों की अध्यक्षता करना/शोध परियोजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में शोध निष्कर्षों का प्रकाशन इत्यादि।

(तीन) प्रशासनिक सहायता और छात्र सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर कार्यकलापों में सहभागिता।

मूल्यांकन प्रक्रिया

ख. मूल्यांकन प्रक्रिया-

सभी स्तरों पर सीएएस के अधीन प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित तीन चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है:

पहला चरण:-विश्वविद्यालय के अध्यापक विहित प्ररूप में वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसे परिशिष्ट दो की तालिका 1 से 4 के आधार पर बनाया जाएगा। यह रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अध्यापक, वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में किए गए दावों के लिए साक्ष्यों के दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। जो विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जायेगा। इसे विभागाध्यक्ष (एचओडी) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

दूसरा चरण:—सीएएस के अधीन प्रोन्नति हेतु आवश्यक वर्षों के अनुभव को पूर्ण किए जाने और नीचे उपदर्शित अन्य अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के पश्चात् अध्यापक सीएएस के अधीन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

तीसरा चरण:—सीएएस प्रोन्नति इस अध्याय के खण्ड 6.4 में उल्लिखित पद्धति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(1) मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि—

मूल्यांकन मानदण्ड
और प्रविधि

(क) परिशिष्ट दो की तालिका 1 से 3, विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य / सह-आचार्य / आचार्य / वरिष्ठ आचार्य के चयन के लिए लागू है; और

(ख) परिशिष्ट दो की तालिका 4, कॅरियर उन्नति योजना के अधीन प्रोन्नति हेतु सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और उप पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए लागू है।

(2) उक्त संवर्गों के लिए चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया तथा मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि चाहे वह सीधी भर्ती के लिए हो या कॅरियर उन्नति योजना के अधीन हो, इस अध्याय के अनुसार होंगी।

(3) इस अध्याय के अधीन निर्धारित कॅरियर उन्नति योजना के अधीन प्रोन्नतियों के लिए मानदण्ड, यूजीसी गजट अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 में प्रकाशित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार प्रभावी होंगे। तथापि, पहले से अर्हित अथवा शीघ्र अर्ह होने वाले संकाय के सदस्यों की कठिनाई कम करने के लिए उन्हें प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है, यह विकल्प यूजीसी गजट अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 में प्रकाशित यूजीसी विनियम, 2018 की अधिसूचना के दिनांक से केवल तीन वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है।

(एक) सीएएस के अधीन प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के इच्छुक अध्यापक को, अंतिम दिनांक से तीन माह के भीतर अग्रिम रूप में विश्वविद्यालय को लिखित में यह प्रस्तुत करना होगा कि वह सीएएस के अधीन समस्त अर्हताओं को पूरा करता है/करती है और इस अध्यादेश में दिये गये मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त प्रत्यय पत्रों सहित, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि प्ररूप विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीएएस के अधीन विभिन्न पदों के लिए चयन समिति की बैठकों के आयोजन में किसी विलंब से बचने के लिए विश्वविद्यालय जांच / चयन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है और आवेदन प्राप्ति से छः माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त इस अध्याय के अधिसूचित होने के दिनांक को अथवा तक इस अध्याय में दिए गए समस्त अन्य मानदण्डों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए उन पर इन पात्रता शर्तों को पूरा करने की तिथि के बाद से अथवा उस तिथि से प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है।

(दो) खण्ड 4.1 से 4.4 में यथा अंतर्विष्ट चयन समिति संबंधी विनिर्दिष्टताएं संकाय पदों अथवा समकक्ष संवर्गों और सहायक आचार्य से सह-आचार्य, सह-आचार्य से आचार्य, आचार्य से वरिष्ठ आचार्य (विश्वविद्यालय में) और समकक्ष संवर्गों के लिए सभी सीधी भर्ती तथा कॅरियर उन्नति योजना के लिए लागू होंगे।

(तीन) सहायक आचार्य के एक निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक सीएएस प्रोन्नति परिशिष्ट-दो की तालिका 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पालन करते हुए एक "जाँच सह मूल्यांकन समिति" के माध्यम से संचालित की जाएगी।

(चार) सीएएस के अधीन प्रोन्नति मूल संस्वीकृत पद को धारण करने वाले अध्यापक की वैयक्तिक प्रोन्नति है, उसकी अधिवर्षता पर उक्त पद मूल संवर्ग में वापस चला जाएगा।

(पांच) सीएएस के अधीन प्रोन्नति के लिए आवेदक अध्यापक को चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाले दिनांक को विश्वविद्यालय की सक्रिय सेवा और भूमिका में होना चाहिए।

(छः) यदि अभ्यर्थी सुसंगत मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि तालिकाओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम ग्रेडिंग को पूरा करता/करती है तो वह आवेदन तथा अपेक्षित मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि प्रारूप प्रस्तुत करते हुए प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा/करेगी। ऐसा वह अंतिम दिनांक से तीन माह पूर्व कर सकता/सकती है। विश्वविद्यालय, पात्र अभ्यर्थी से सीएएस प्रोन्नति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए वर्ष में दो बार एक सामान्य परिपत्र निकालेगा।

एक—यदि एक अभ्यर्थी न्यूनतम पात्रता अवधि के पूर्ण होने पर प्रोन्नति के लिए आवेदन करता है और सफल हो जाता तो प्रोन्नति का दिनांक पात्रता की न्यूनतम अवधि को पूर्ण किये जाने का दिनांक होगा।

दो—तथापि, यदि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह परिशिष्ट दो की तालिकाओं 1, 2 और 4 में यथा विनिर्दिष्ट सीएस प्रोन्नति मानदण्डों को किसी पश्चातवर्ती दिनांक को पूरा करेगा और वह उस दिनांक को आवेदन करता है तथा सफल हो जाता है तो उसकी प्रोन्नति उसके द्वारा पात्रता मानदण्ड पूरा करने के दिनांक से प्रभावी होगी।

तीन—ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के पश्चात ही किया जाएगा। जब ऐसे अभ्यर्थी पारिणामिक मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष मानी जाएगी।

चार—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय, संबंधी विनियम, 2010 और इसमें बाद में किए गए संशोधनों में यथा उपबंधित कैरियर उन्नति योजना के अधीन एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन में प्रोन्नतियों के लंबित मामलों के संबंध में अध्यापक को एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन में प्रोन्नति पर विचार किए जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प दिया जाएगा:

(क) इस अध्याय के अधीन अध्यापकों के, एक अकादमिक स्तर / ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु सीएस के अनुसार विचार किया जाएगा।

अथवा

(ख) एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु संकाय के सदस्यों पर सीएस के अनुसार विचार किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 तथा इसमें बाद में किए गए संशोधनों पर आधारित होगा जिसमें इस अध्याय की अधिसूचना के दिनांक तक अकादमिक निष्पादन संकेतकों (एपीआई) पर आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएस) की अर्हताओं में छूट प्रदान की जाएगी।

सारणी-क

विश्वविद्यालय के विभागों में सीएस के अधीन अध्यापकों की प्रोन्नति के लिये अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0

क्रम संख्या		सहायक आचार्य स्टेज-1/ ए0जी0पी0 रू0 6000/- स्टेज-2/ ए0जी0पी0 रू0 7000/-	सहायक आचार्य स्टेज-2/ ए0जी0पी0 रू0 7000/- स्टेज-3/ ए0जी0पी0 रू0 8000/-	सहायक आचार्य स्टेज-3/ ए0जी0पी0 रू0 8000/- सह-आचार्य स्टेज-4/ ए0जी0पी0 रू0 9000/-	सह-आचार्य स्टेज-4/ ए0जी0पी0 रू0 9000/- आचार्य स्टेज-5/ ए0जी0पी0 रू0 10000/-
1	अनुसंधान एवं शैक्षणिक योगदान (श्रेणी तीन)	40 / मूल्यांकन अवधि	100 / मूल्यांकन अवधि	90 / मूल्यांकन अवधि	120 / मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रणाली	स्क्रीनिंग समिति	स्क्रीनिंग समिति	चयन समिति	चयन समिति

सारणी-ख

विश्वविद्यालय में सीएएस के अधीन पुस्तकालय कर्मचारिवृन्द की प्रोन्नति के लिये न्यूनतम अपेक्षित ए0पी0आई0

क्रम संख्या		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज-1 / ए0जी0पी0 रू0 6000/-	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज-2 / ए0जी0पी0 रू0 7000/-	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष चयन ग्रेड/उप पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज-3 / ए0जी0पी0 रू0 8000/-	उप पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज-4 / ए0जी0पी0 रू0 9000/-
1	अनुसंधान एवं शैक्षणिक योगदान (श्रेणी तीन)	40 / मूल्यांकन अवधि	100 / मूल्यांकन अवधि	90 / मूल्यांकन अवधि	120 / मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रणाली	स्क्रीनिंग समिति	स्क्रीनिंग समिति	चयन समिति	चयन समिति

आठ-सीएएस के अधीन प्रोन्नतियों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अपेक्षा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य नहीं होगी।

भाग-तीन

35-कॅरियर उन्नति योजना के अधीन पदधारी और नव-नियुक्त सहायक आचार्य/ सह-आचार्य/आचार्यों की प्रोन्नति के चरण

सीएएस के अधीन प्रोन्नति

क- प्रवेश स्तर पर सहायक आचार्य (स्तर 10), कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अधीन प्रोन्नति लिए दो क्रमिक स्तरों (स्तर 11 और स्तर 12) के माध्यम से पात्र होंगे बशर्ते वे इस अध्याय के खण्ड 6.3 में निर्धारित पात्रता और निष्पादन मानदण्ड को पूरा करते हों।

ख- महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

एक-सहायक आचार्य (अकादमिक स्तर 10) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11)

ग- योग्यता

योग्यता

(एक) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने सेवा में चार वर्ष पूरे कर लिए हों और पीएचडी की उपाधि धारक हो अथवा सेवा में पांच वर्ष पूरे कर लिए हों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एमफिल/स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों जैसे एलएलएम, एम0टेक0, एम0वी0एससी, और एम0डी0 अथवा जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पीएचडी/एम0फिल/स्नातकोत्तर की उपाधि धारक नहीं हो और जिन्होंने सेवा में छह वर्ष पूरे कर लिए हो और निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करते हों;

(दो) शिक्षण प्रविधि पर 21 दिवस की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(तीन) निम्नलिखित में से किसी एक कार्यक्रम में भाग लिया हो:-
पुनश्चर्या/शोध प्रविधि पाठ्यक्रम/कार्यशाला, पाठ्यचर्या उन्नयन
कार्यशाला/प्रशिक्षण शिक्षण- ज्ञान अर्जन मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/कम से
कम एक सप्ताह (5 दिवस) की अवधि का संकाय विकास कार्यक्रम अथवा मूल्यांकन
अवधि के दौरान एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई- प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो
अथवा चार चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु का विकास/एमओओसी पाठ्यक्रम पूरा किया
हो; और

(चार) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में एक शोध प्रकाशन प्रकाशित
हुआ हो।

सीएसएस प्रोन्नति
मानदण्ड

घ-सीएसएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि:-

एक-उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/पाँच/छह वर्षों में से कम से
कम तीन-चार-पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन
रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट दो,
सारणी 1 में यथाविनिर्दिष्ट है, और

दो-प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

तीन-सहायक आचार्य (ज्येष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य
(चयन श्रेणी/अकादमिक स्तर 12)

योग्यता

योग्यता:

एक-ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने वेतनमान अकादमिक स्तर 11/ज्येष्ठ
वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

दो-संगत /संबद्ध/संगत विषय में पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की हो।

तीन-अकादमिक स्तर-11/ज्येष्ठ वेतनमान के पिछले पांच वर्षों के दौरान
निम्नलिखित में से कोई दो किए हो: मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो
सप्ताह (10 दिन) की अवधि [अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि
के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच
दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों] के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम /शोध
कार्यविधि पाठ्यक्रम /कार्यशालाओं /पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला /शिक्षण- ज्ञान
अर्जन- मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम /संकाय विकास कार्यक्रम /पाठ्यक्रम पूर्ण
किए हो अथवा संगत विषय में (ई-प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया
हो, एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक
चतुर्थांश) में ई- विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो /एमओओसी पाठ्यक्रम
संचालित करने में योगदान दिया हो।

चार-मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ
हो।

सीएसएस प्रोन्नति
मानदण्ड

घ-सीएसएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि:-

एक-मूल्यांकन अवधि के पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार इनमें से
जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में संतोषजनक अथवा
'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो (जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 1 में यथाविहित किया गया
है)।

दो-प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

तीन-सहायक आचार्य (चयन वेतनमान/अकादमिक स्तर 12) से सह-आचार्य
(अकादमिक स्तर 13 क)

योग्यता मानदण्ड

योग्यता मानदण्ड:

एक-ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 12 /चयन वेतनमान
में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

दो-संगत /संबद्ध /संगत विषय में पी0एच0डी की उपाधि प्राप्त की हो।

तीन-पिछले तीन वर्षों दौरान निम्नलिखित से कोई एक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि [अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों] के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यविधि कार्यशाला/पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/शिक्षण-ज्ञान अर्जन मूल्यांकन/प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, अथवा संगत विषय में (ई-प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो. एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई-विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो/एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

चार-समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम सात प्रकाशन जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि में प्रकाशित हुआ हो।

पांच-कम से कम एक पीएच.डी अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

घ-सीएस प्रोन्नति मानदण्ड:

सीएस प्रोन्नति
मानदण्ड

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि:-

एक-जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, और परिशिष्ट दो सारणी-2 के अनुसार कम से कम 70 शोध अंक प्राप्त किए हों।

दो-इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

चार-सह-आचार्य (अकादमिक स्तर 13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14)

योग्यता:

(एक) ऐसे सह-आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) संबंधित /संबद्ध /संगत विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो।

(तीन) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

(चार) पीएच.डी अभ्यर्थी का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

(पांच) परिशिष्ट -दो सारणी 2 के अनुसार न्यूनतम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

ङ-सीएस प्रोन्नति मानदण्ड:

सीएस प्रोन्नति
मानदण्ड

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि:-

(एक) यदि उसे परिशिष्ट- दो सारणी 1 में यथा विहित मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों तथा परिशिष्ट - दो सारणी 2 के अनुसार न्यूनतम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

(दो) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

पांच-आचार्य (अकादमिक स्तर 14) से ज्येष्ठ आचार्य (अकादमिक स्तर 15)

सीएस के अधीन एक आचार्य की वरिष्ठ आचार्य के पद पर प्रोन्नति की जा सकती है। प्रोन्नति शैक्षणिक उपलब्धि, तीन ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों जो न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त ज्येष्ठ आचार्य अथवा आचार्य से अनिम्न रैंक के हों की अनुकूल समीक्षा पर आधारित होगा। प्रख्यात विषय विशेषज्ञों, जो चयन पिछले 10 वर्षों के दौरान 10 सर्वोत्तम प्रकाशनों और इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति के साथ विचार-विमर्श के आधार पर होगा।

योग्यता

योग्यता:

एक—आचार्य के पद पर दस वर्ष का अनुभव।

दो—समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस प्रकाशन और पी0एच0डी0 मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पर्यवेक्षण में दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक उपाधि प्रदान की गई हो।

ज—पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए कैरियर उन्नति योजना (सीएएस)

नोट:

एक—निम्नलिखित उपबंध केवल उन व्यक्तियों पर लागू हैं जो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षण से नहीं जुड़े हों। जिन संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान एक शिक्षण विभाग है वहां के शिक्षक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिये क्रमशः इस अध्याय की धारा 6.4 (ख) में दिये गये उपबंधों के अधीन आच्छादित होंगे।

दो—विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयाध्यक्ष के दो स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14।

झ—विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 10) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (ज्येष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11)

योग्यता

योग्यता:

एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो कि अकादमिक स्तर 10 में हो और पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण विज्ञान में पी0एच0डी0 की उपाधि धारण करते हुये चार वर्ष की सेवा पूर्ण की हो अथवा समकक्ष उपाधि धारक हो अथवा पांच वर्ष का अनुभव हो, कम से कम एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष का अनुभवधारी हो अथवा जो अभ्यर्थी न्यूनतम एम0फिल0 की डिग्री अथवा पीएच.डी की उपाधि नहीं हो उनका छह वर्षों का सेवाकाल हो।

एक—उसने 21 दिवस की अवधि के कम से कम एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो और

दो—परिशिष्ट—दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम 5 दिवस का स्वचालन और डिजिटलीकरण रख-रखाव और संबद्ध क्रियाकलापों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठी अथवा कार्यशाला में भाग लिया हो।

सीएएस प्रोन्नति
मानदण्ड

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रोन्नति दी जा सकती है यदि उसने:—

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/पांच/छः वर्षों में से कम से कम तीन/चार/पांच वर्षों जैसा भी मामला हो, की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में संतोषजनक अथवा अच्छे ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट—दो सारणी —4 में यथाविनिर्दिष्ट है, और

(दो) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

दो—विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (ज्येष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान/अकादमिक स्तर 12)

योग्यता

योग्यता:

1—उन्होंने उस वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2—उन्होंने पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित में से कोई दो कार्य किये हों।

(एक) स्वचालन और डिजिटलीकरण पर प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला/पाठ्यक्रम, (दो) परिशिष्ट—दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि तक के रख-रखाव और अन्य संबद्ध कार्यकलाप [अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) के प्रत्येक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों], (तीन) सुसंगत विषय में (ई—प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो / विकसित किया हो अथवा (चार) पुस्तकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

(ज) सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि:—

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले पांच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 4 में यथाविनिर्दिष्ट है, और (दो) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान / अकादमिक स्तर 12) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क)

योग्यता:

1—उन्होंने उस वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2—उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो कार्य किये हों।

(एक) स्वचालन और डिजिटलीकरण पर प्रशिक्षण / संगोष्ठी / कार्यशाला / पाठ्यक्रम, (दो) परिशिष्ट—दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि तक के रख-रखाव और अन्य संबंधित कार्यकलाप (तीन) कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) के प्रत्येक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों, (चार) सुसंगत विषय में (ई—प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो / विकसित किया हो और (पांच) पुस्तकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

(ट) सीएएस प्रोन्नति मानदंड:

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि:—

सीएएस प्रोन्नति
मानदंड

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 4 में यथाविनिर्दिष्ट है; और

(दो) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

चार—विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13 क) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 14) में सीएएस प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे:

योग्यता:

1—उन्होंने उस वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2—उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किन्हीं एक कार्यक्रम में भाग लिया हो;

(एक) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण / संगोष्ठी / कार्यशाला / पाठ्यक्रम, (दो) परिशिष्ट—दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि तक के रख-रखाव और अन्य संबंधित कार्यकलाप (तीन) कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) के प्रत्येक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों, (चार) सुसंगत विषय में (ई—प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो / विकसित किया हो और (पांच) अथवा पुस्तकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

3—पुस्तकालय आईसीटी समेकन सहित नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं के साक्ष्य हो

4—पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखीकरण/अभिलेख और पाण्डुलिपि संरक्षण में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो।

ठ—सीएएस प्रोन्नति मानदंड

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि:—

सीएएस प्रोन्नति
मानदंड

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 4 में यथाविनिर्दिष्ट है, और

(दो) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

(5) इस व्यवसाय में आने वाले उच्च मैरिट उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान प्रकाशनों की अधिक संख्या और समुचित स्तर पर अनुभव वाले सह-आचार्य अथवा आचार्य का अग्रिम वेतन वृद्धि का विवेकपूर्ण पुरस्कार, संकाय में अन्य अध्यापकों के वेतन ढांचे और मेरिट विशिष्ट कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले की मैरिट के संदर्भ में व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करते समय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय अथवा भर्ती करने वाली संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की सक्षमता पर आधारित होगा। अग्रिम वेतन वृद्धि का यह विवेकपूर्ण पुरस्कार उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो सहायक आचार्य/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के रूप में इस पेशे में आते हैं और जो पीएचडी, एमफिल अथवा एमटेक और एलएलएम की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और रिकॉर्ड के अनुसार सेवा में आने वाले ऐसे सहायक आचार्य/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अग्रिम वेतनवृद्धि के विवेकपूर्ण पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं जिनके पास पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पोस्ट डॉक्टोरल शिक्षा शोध अनुभव और सिद्ध पूर्ववृत्त हों।

(6) सी.ए.एस. के अधीन सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करना—

सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक अध्यापक को सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर डीआरडीओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य वैज्ञानिक/व्यावसायिक संगठनों में सहायक आचार्य, सह-आचार्य अथवा आचार्य अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि—

क— धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो।

ख— पद, सहायक आचार्य (व्याख्याता), सह-आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो / था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो रहा हो।

ग— संबंधित सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य के पास सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए।

घ— ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय / राज्य सरकार/केंद्र सरकार/संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हों।

ङ— किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो।

च— पूर्व तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा परिशिष्ट सेवा (जिस भी नाम से इसे जाना जाए) की सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु गणना की जाएगी, परन्तु यह कि:

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम ना हो;

(दो) पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई हो;

(तीन) पदधारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हों; और

छ- इस खंड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थी, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

36-(1) परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि

परिवीक्षा और
स्थायीकरण की
अवधि

(क) किसी अध्यापक की परिवीक्षा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी, जिसे असंतोषजनक प्रदर्शन किए जाने की स्थिति में एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

(ख) परिवीक्षाधीन अध्यापक को एक वर्ष के अंत में स्थायी किया जाएगा, जब तक कि पहले वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी विनिर्दिष्ट आदेश के माध्यम से इस अवधि को एक और वर्ष बढ़ाया ना गया हो।

(ग) इस विनियम के खंड 11 के अध्याधीन विश्वविद्यालय/संबंधित संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन की यथावत प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर पदधारियों को स्थायी करने का आदेश जारी करें।

(घ) परिवीक्षा और स्थायीकरण नियमों को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी केवल भर्ती के शुरुआती चरण पर ही लागू किया जाएगा।

(ङ) परिवीक्षा और स्थायीकरण संबंधी राज्य सरकार के अन्य समस्त नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) अध्यापकों के पदों का सृजन और उनका भरा जाना

(क) जहां तक व्यवहार्य हो विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का पद पिरामिड क्रम में सृजित किए जाएं, उदाहरण के लिए आचार्य के एक पद के लिए प्रति विभाग सह-आचार्य के दो पद और सहायक आचार्यों के चार पद होने चाहिए।

(ख) विश्वविद्यालय प्रणाली में समस्त स्वीकृत/अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

37-संविदा आधार पर नियुक्तियां

संविदा आधार पर
नियुक्तियां

संविदा आधार पर अध्यापक की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब पूर्ण रूप से अनिवार्य हो और जब छात्र अध्यापक का अनुपात निर्धारित मानदंड पर खरा न उतरता हो ऐसे किसी मामले में उक्त नियुक्तियों की संख्या महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संकाय पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें नियुक्त करने संबंधी अर्हताएं और चयन प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो नियमित आधार पर नियुक्त किए गए अध्यापकों पर लागू होती हैं। उक्त अनुबंधित अध्यापकों को दी गई निर्धारित परिलब्धियां नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में ऐसी नियुक्तियां एक शैक्षणिक सत्र से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए और ऐसे किसी नए अध्यापक के कार्य निष्पादन की अन्य सत्र हेतु संविदा आधार पर नियुक्त करने से पहले शैक्षणिक उपलब्धियों की समीक्षा किया जाना चाहिए। जब प्रसूति छुट्टी, बालचर्या छुट्टी इत्यादि के कारण उद्भूत रिक्तियां भरना पूर्ण रूप से अनिवार्य हो, तभी संविदा आधार पर ऐसी नियुक्तियां की जानी चाहिए।

भाग-चार

38-विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन:

कुलपति का चयन

एक-सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठता, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा। कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम दस वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ दस वर्षों के अनुभव के साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए।

दो-कुलपति के पद हेतु चयन एक खोज सह चयन समिति के माध्यम से एक सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या इनके संयोजन से 3-5 लोगों के एक पैनल द्वारा उचित पहचान के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसी खोज सह चयन समिति के सदस्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए और किसी भी प्रकार से संबंधित विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों से नहीं जुड़े होने चाहिए। पैनल तैयार करते समय खोज सह चयन समिति को शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली से अवगत होने के अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को लिखित रूप में पैनल सहित कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति को देना चाहिए। राज्यों, निजी और सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव हेतु खोज सह चयन समिति के एक सदस्य का नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति द्वारा किया जाना चाहिए।

तीन-कुलपति की नियुक्ति खोज सह चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल के नामों में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

चार-कुलपति का कार्यकाल पदधारी की सेवा अवधि का भाग बन जाएगा, जो उसे सेवा से जुड़े सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगी।

भाग-पांच

शिक्षण के दिवस

39-शिक्षण के दिवस

(1) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कम से कम 180 शिक्षण दिवस होने चाहिए अर्थात् 6 दिवस के सप्ताह में न्यूनतम 30 सप्ताह के वास्तविक शिक्षण दिवस होने चाहिए। शेष अवधि में 12 सप्ताह को प्रवेश और परीक्षा संबंधी क्रियाकलापों और सह- पाठ्यचर्या, खेलकूद, महाविद्यालय दिवस इत्यादि हेतु शिक्षणोत्तर दिवसों के लिए उपयोग किया जा सकता है। 8 सप्ताह प्रावकाश के लिए और 2 सप्ताह विभिन्न सरकारी छुट्टियों के लिए दिए जा सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय पांच दिवसीय प्रति सप्ताह की पद्धति अपनाता है तो सप्ताह की संख्या तदनुसार बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 दिवसीय सप्ताह में 30 सप्ताह के समकक्ष वास्तविक शिक्षण कार्य किया जा सके।

उक्त उपबंध को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है:

	सप्ताह की संख्या: 06 दिवस प्रति सप्ताह पैटर्न		सप्ताह की संख्या: सप्ताह में 05 दिवस पैटर्न	
वर्गीकरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया	30 (180 दिवस) सप्ताह	30 (180 दिवस) सप्ताह	36 (180 दिवस) सप्ताह	36 (180 दिवस) सप्ताह
प्रवेश परीक्षाएं और परीक्षा की तैयारी	12	10	8	8
प्रावकाश	8	10	6	6
सार्वजनिक अवकाश (तदनुसार बढ़ाने और प्रशिक्षण के दिवसों को समायोजित करने के लिए)	2	2	2	2
कुल	52	52	52	52

(2) प्रावकाश में 2 सप्ताह की कमी करने के बदले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के अर्जित अवकाश में उक्त अवधि की एक तिहाई दिवसों के अवकाश की वृद्धि की जा सकती है। तथापि, महाविद्यालय के पास एक वर्ष में कुल 10 सप्ताहों के प्रावकाश का विकल्प होगा और प्रावकाश के दौरान कार्य करने की आवश्यकता के अलावा किसी और कारण से अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के मामले में अर्जित अवकाश के रूप में एक 1/3 अवधि की छुट्टी दी जाएगी।

40—कार्यभार

कार्यभार

(1) पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में अध्यापकों का कार्यभार तीस कार्य सप्ताह (एक सौ अस्सी शिक्षण दिवस) के लिए एक सप्ताह में चालीस घंटों से कम नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कम से कम पांच घंटे प्रतिदिन उपलब्ध हों। अध्यापक अवर—स्नातक पाठ्यक्रमों के मामले में सामुदायिक विकास/पाठ्येतर कार्यकलापों/पुस्तकालय परामर्श/शोध हेतु छात्रों को शिक्षित करने के लिए कम से कम प्रतिदिन दो घंटे (प्रति समन्वयक न्यूनतम 15 छात्र) और/अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में शोध हेतु प्रतिदिन कम से कम दो घंटे का समय देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और अवसरचना प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण—ज्ञान अर्जन कार्यभार निम्नानुसार होना चाहिए:

सहायक आचार्य	16 घंटे प्रति सप्ताह
सह—आचार्य/आचार्य	14 घंटे प्रति सप्ताह

(ख) प्रशासन/विस्तार कार्य में सम्मिलित आचार्य/सह—आचार्य/सहायक आचार्य शिक्षण और सीखने के लिये प्रति सप्ताह दो घंटा निरत रह सकता है।

(2) सेवा करार और ज्येष्ठता का निर्धारण करना

क— विश्वविद्यालय में भर्ती के समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और संबंधित अध्यापक के बीच एक सेवा करार होना चाहिए और उसकी एक प्रति कुलसचिव के पास जमा की जाएगी। ऐसे सेवा करार पर लागू सरकारी दरों के अनुसार सम्यक् रूप से स्टॉम्पित किया जाएगा।

ख— खंड 6.0 और इसके उपखंडों और खंड 6.1 से 6.4 के अनुसार स्व—मूल्यांकन पद्धति और इसमें अंतर्विष्ट सभी उपखंड तथा परिशिष्ट दो की सारणी 1 से 4 के अनुसार पात्रता के अनुसार सेवा करार बनाया जायेगा।

(3) सीधी भर्ती और सी.ए.एस. के अधीन प्रोन्नत किए गए अध्यापकों के मध्य परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण

सीधी भर्ती की परस्पर ज्येष्ठता पर ग्रहण के दिनांक से अवधारित की जायेगी और सी.ए.एस. के अधीन प्रोन्नत किए गए अध्यापकों हेतु पात्रता के दिनांक से किया जाएगा, जैसे कि संबंधित अभ्यर्थियों की चयन समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया है। ज्येष्ठता के अन्य समस्त मामलों के लिए संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे।

भाग—छ:

41—अध्यापक और उनका उत्तरदायित्व

वृत्तिक सदाचार
संहिता

जो कोई भी शिक्षण को वृत्ति के रूप में अपनाता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह वृत्ति के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक अध्यापक निरन्तर अपने छात्रों और बड़े पैमाने पर समाज की संवीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए प्रत्येक अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों प्रसार करना एक अध्यापक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस वृत्त में अग्रतर यह भी आवश्यक है कि अध्यापक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक अध्यापक को:

(एक) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है;

(दो) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि वृत्तिक गरिमा के अनुरूप हों;

(तीन) अध्ययन और शोध के माध्यम से निरन्तर वृत्तिक विकास जारी रखने चाहिए;

(चार) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए वृत्तिक बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए;

(पांच) वृत्तिक संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और वृत्तिक को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;

(छः) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और अनुसंधान कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;

(सात) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में लिप्त नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;

(आठ) विश्वविद्यालय के अधिनियम परिनियम और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और इसके आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए;

(नौ) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और साथ ही साथ निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना; और

(दस) सामुदायिक सेवा सहित सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

अध्यापक और छात्र

दो-अध्यापक और छात्र

अध्यापक को

(एक) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और गरिमा का आदर करना चाहिए;

(दो) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए,

(तीन) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए,

(चार) छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए,

(पांच) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र देश भक्ति सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए,

(छः) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए,

(सात) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए,

(आठ) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए,

(नौ) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए,

(दस) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

तीन-अध्यापक और सहयोगी अध्यापकअध्यापक और
सहयोगी अध्यापक

(एक) वृत्ति से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे,

(दो) अन्य अध्यापकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए,

(तीन) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए,

(चार) अपने वृत्तिक प्रयासों में जाति, रंग, धर्म प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

चार-अध्यापक और प्राधिकारी अध्यापक को चाहिये किअध्यापक और
प्राधिकारी
अध्यापक

(एक) विद्यमान नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और / अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से वृत्तिक हेतु घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो वृत्तिक हित में हो।

(दो) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके वृत्तिक उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो।

(तीन) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना,

(चार) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे,

(पांच) वृत्ति की गरिमा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए,

(छः) संविदा की शर्तों का अनुपालन करेंगे,

(सात) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले सम्यक नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे,

(आठ) जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियाँ लेने से बचेंगे।

पांच-अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्दअध्यापक और
शिक्षणेत्तर कर्मचारी**अध्यापकों को चाहिए कि:**

(एक) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द को अपना सहकर्म और समान सहयोगी समझें।

(दो) अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द से संबंधित संयुक्त कर्मचारिवृन्द परिषदों के कार्य में सहायता करें।

छ-अध्यापक और अभिभावकअध्यापक और
अभिभावक

अध्यापकों को चाहिए कि:

अध्यापक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं अभिभावकों, अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाए और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान-प्रदान और संस्था के हित हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

सात-अध्यापक और समाजअध्यापक और
समाज

अध्यापकों को चाहिए कि

(एक) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें,

(दो) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें,

(तीन) सामाजिक समस्याओं से अवगत हो और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो,

(चार) नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लें और लोक पद के उत्तरदायित्वों में सहायता करें,

(पांच) ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

कुलपति

आठ—कुलपति

कुलपति को चाहिए कि

(एक) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्य नेतृत्व प्रदान करे,

(दो) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और विनिश्चय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो,

(तीन) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें,

(चार) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके,

(पांच) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, वृत्तिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे,

(छः) अपने वृत्तिक प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचारणा से बचें।

पुस्तकालयाध्यक्ष

नौ—पुस्तकालयाध्यक्ष

पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि वह:

(एक) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;

(दो) वृत्ति की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;

(तीन) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;

(चार) समाज सेवा में संलग्न रहते हुए विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लें;

(पांच) अपने वृत्तिक प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

42—उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना:

उच्चतर शिक्षा में शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय /संस्थानों द्वारा निम्नलिखित सिफारिश अपनाई जाएंगी:—

(एक) इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि की मूल्यांकन प्रक्रिया समान होगी। विश्वविद्यालय उन विनियमों को इनकी अधिसूचना के छह मास के भीतर अंगीकार कर लेंगे।

(दो) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत अध्यापकों के लिए पीएचडी अधिसंख्य स्थानों के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा लेकिन, यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(तीन) अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और देश की अनुसंधान उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पीएचडी/एमफिल विद्वानों के पर्यवेक्षण की अनुमति प्रदान करेगा और आवश्यकता आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा। तदनुसार विश्वविद्यालय अपनी परिनियमों तथा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।

(चार) इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार समस्त नव नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल अनुसंधान / कंप्यूटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार प्रारम्भिक धन/स्टार्ट अप अनुदान / अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाएगा।

(पांच) इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि को अनिवार्य अपेक्षा बनाया जाएगा।

(छः) संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित करने के लिए अनुसंधान सुविधाओं, मानव संसाधन कौशल और अवसरचना को साझा करने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के बीच अनुसंधान कलस्टर सृजित किए जाएंगे।

(सात) विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाओं में समस्त नव नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए आदर्श रूप से उनके शैक्षिक कार्य शुरू करने से पहले एक मास का अनुगम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा लेकिन यह नव-नियुक्त संकाय सदस्य की भर्ती के निश्चित रूप से एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय / संस्थाएं अध्यापक और शिक्षण से संबंधित पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना के माध्यम से अपने अधिदेश के अनुरूप उक्त अनुगम कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(आठ) उक्त अनुगम कार्यक्रमों को सीएसएस आवश्यकताओं के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा पहले से चलाए जा रहे अभिविन्यास कार्यक्रमों के समतुल्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्यक्रमों में भेजेंगे जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

(नौ) पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के अंतर्गत स्कूल ऑफ एजुकेशन (एसआई) टीचिंग लर्निंग सेंटर्स (टीएलसी), फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स (एफडीसी), सेंटर्स फॉर अकॅडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट (सीएएलईएम) जैसे केन्द्रों द्वारा अध्यापकों/संकाय सदस्यों हेतु आयोजित एक सप्ताह से लेकर एक मास तक के समस्त अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ अध्यापन संबंधी और विषय विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के अधीन कैरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

भाग—सात

43—अन्य निबंधन और शर्तें—

(1) पीएचडी/एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

(एक) जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला रजिस्ट्रीकरण कोर्स वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(दो) सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(तीन) क—जो अध्यापक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।

(ख) तथापि, उन सेवारत अध्यापकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है, या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

अन्य निबंधन और शर्तें

(चार) अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे अध्यापक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित हैं वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर-मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(पांच) ऐसे सेवारत अध्यापक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर-मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

(छ) ऐसे अध्यापक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय / परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(सात) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विद्या में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी0एच0डी0 प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स वर्क और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर-मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(आठ) क-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स वर्क और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर-मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

ख-तथापि ऐसे अध्यापक, जो सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हो तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(नौ) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित हैं, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर-मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(दस) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और उच्च पुस्तकालय पदों पर आसीन सेवारत व्यक्ति, जो पीएचडी में अभी तक नहीं नामांकित हैं, केवल उस स्थिति में प्रवेश स्तर पर तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(ग्यारह) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि है के लिए प्रवेश स्तर पर दो गैर-मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो सेवा के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि प्राप्त करते हैं के लिए प्रवेश स्तर पर एक गैर-मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

(बारह) पूर्वगामी खंडों में किसी शर्त के बावजूद भी, जो पहले से ही इस विनियम या पूर्व योजनाओं/विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर या सेवा के दौरान पीएचडी /एमफिल की उपाधि के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस विनियम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं होंगे।

(तेरह) अध्यापक, पुस्तकालय संवर्ग जिन्होंने सेवा के दौरान पहले ही पीएचडी /एमफिल की उपाधि प्राप्त करने हेतु विद्यमान नीति के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(चौदह) उन पदों के लिए जहाँ पूर्व योजनाओं/विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएचडी/एमफिल की उपाधि के आधार पर कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी, वहाँ पीएचडी /एमफिल की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा, जो इन विनियमों के लागू होने पर या इसके पश्चात् की गई हैं।

भाग—आठ

44—पदोन्नति

पदोन्नति भत्ते और
प्रसुविधायें

जब किसी व्यक्ति की पदोन्नति होगी, तो पदोन्नति पर उनका वेतन नीचे दिए गए पे मैट्रिक्स अनुसार विहित किया जायेगा:

पदोन्नति पर अध्यापक या समकक्ष पद को उस स्तर पर अगले उच्चतर प्रकोष्ठ में प्रविष्ट करके उसके विद्यमान वेतन के अकादमिक वेतन स्तर में कल्पित वेतनवृद्धि की जाएगी और इस प्रकोष्ठ में दर्शाया गया वेतन अब उस पद के अनुरूप नए शैक्षणिक स्तर पर निर्धारित होगा, जहाँ उसे प्रोन्नत किया गया है। यदि उस वेतन के समान एक प्रकोष्ठ नए स्तर पर उपलब्ध है, तो यह प्रकोष्ठ नया वेतन होगा, अन्यथा उस स्तर पर अगला प्रकोष्ठ अध्यापक या समकक्ष पद का नया वेतन होगा यदि नए स्तर पर इस पद्धति से परिकलित वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ से कम है, तो वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ पर नियत किया जाएगा।

(1) भत्ते और प्रसुविधायें

भत्ते और प्रसुविधायें

(एक) अध्यापकों और पुस्तकालय संवर्ग हेतु अन्य भत्ते और प्रसुविधायें जैसे कि गृहनगर यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत, विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र आधारित विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता आदि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संगत नियमों द्वारा शासित होंगे।

(दो) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन, उपदान, अनुग्रह राशि इत्यादि भी राज्य विश्वविद्यालय के अध्यापकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग संबद्ध और घटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों, जैसा भी मामला हो में लागू होंगे।

(तीन) चिकित्सा संबंधी लाभ: अध्यापकों और पुस्तकालय संवर्ग के लिए समस्त चिकित्सा प्रसुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले लाभ के समान होंगे। अग्रतर अध्यापकों और पुस्तकालय संवर्ग को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन रखा जा सकता है या राज्य विश्वविद्यालयों हेतु राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जैसा भी मामला हो के तहत रखा जा सकता है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक	विद्यमान पदधारियों जो दिनांक 01.01.2016 के अनुसार सारणी में उपदर्शित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर थे, के वेतन नियतन के लिये फिटमेंट सारणी (एम एच आर डी अधिसूचना एम एच आर डी) पत्र संख्या- शुद्धि पत्र एफ0 संख्या- 1-7/2015 यू दो (1) दिनांक 08.11.2017	
परिशिष्ट दो	निर्धारण मानदण्ड एवं प्रविधि सारणी 1 से 3 -विश्वविद्यालय के लिये सारणी 4-सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष इत्यादि।	
	विद्यमान पदधारी जो दिनांक 01.01.2016 के अनुसार सारणी में उपदर्शित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर स्थित थे, उनके वेतन के नियतन के लिये फिटमेंट सारणी:	
सारणी-1 विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये निर्धारण मानदण्ड एवं प्रविधि		
क्र०	गतिविधि	ग्रेडिंग मानदण्ड
1	(पढ़ाई गई कक्षाएं/ कुल कक्षाएं) X 100 प्रतिशत (पढ़ाई गई कक्षाओं में ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला और अन्य शिक्षण संबंधी गतिविधियां सम्मिलित हैं)	80 प्रतिशत और अधिक उत्तम 80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक - संतोषजनक 70 प्रतिशत से कम- असंतोषजनक
2	विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्रों से संबंधित गतिविधियाँ अनुसंधान गतिविधियों में सम्मिलित:	उत्तम- कम से कम 3 गतिविधियाँ में सम्मिलित।
(क)	प्रशासनिक जिम्मेदारियों जैसे: प्रमुख अध्यक्ष /संकाय/ निदेशक/ समन्वयक, वार्डन आदि	संतोषजनक - 1 से 2 गतिविधियाँ।
(ख)	कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गयी परीक्षा और मूल्यांकन कर्तव्य या परीक्षा पेपर के मूल्यांकन में सम्मिलित होना।	असंतोषजनक-किसी भी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होना।
(ग)	छात्र संबंधी सह- पाठ्यचर्या, विस्तार और क्षेत्र आधारित गतिविधियाँ जैसे छात्र क्लब, कैरियर परामर्श, अध्ययन दौरे, छात्र सेमिनार और अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक खेल, एनसीसी, एनएसएस और सामुदायिक सेवाएं।	टिप्पणी - गतिविधियों की संख्या गतिविधियों की व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत या उससे अतिरिक्त हो सकती है।
(घ)	संगोष्ठी/सम्मेलन/ कार्यशालाएं, अन्य कॉलेज/ विश्वविद्यालय गतिविधियों का आयोजन कराना।	
(ङ.)	पी.एच.डी. छात्रों के मार्गदर्शन में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने का प्रमाण।	
(च)	राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित छोटी या बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करना। सहकर्मी में कम से कम एकल या संयुक्त प्रकाशन पत्रिकाओं की समीक्षा या यूजीसी सूची।	

समग्र ग्रेडिंग

समग्र ग्रेडिंग

अच्छा: शिक्षण में अच्छा है और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा है।

अथवा

संतोषजनक: शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक।

संतोषजनक नहीं है: यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो।

नोट: क्रम संख्या 1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु ऐसी समस्त अवधियाँ जो अध्यापकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। अध्यापक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और अध्यापक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों / प्रतिनियुक्ति के कारण अध्यापक को सीएस के अंतर्गत प्रोन्नति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा बशर्ते ऐसी छुट्टियों / प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

सारणी – 2

शैक्षणिक/अनुसंधान अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रविधि

(आंकलन अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे: प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र, इत्यादि।)

क्रम संख्या	शैक्षणिक/अनुसंधान क्रियाकलाप	भाषा/मानविकी/कला/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शिक्षा/शारीरिक शिक्षा/वाणिज्य/प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)	
	(क) लिखी गयी पुस्तकें जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया:	
	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10
	सम्पादित पुस्तक में अध्याय	05
	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य	
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03
	पुस्तक	08
3.	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान-अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास	

	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम
	(ग) एमओओसी	
	4 चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (04 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक/क्रेडिट)	20
	प्रति मॉड्यूल / व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05
	विषयवस्तु लेखक/एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02
	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (04 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक/क्रेडिट)	08
	(घ) ई-विषयवस्तु	
	पूर्ण पाठ्यक्रम/ई-पुस्तक हेतु चार 4 चतुर्थांशों में ई-विषयवस्तु का विकास	12
	प्रति मॉड्यूल ई-विषयवस्तु (चार चतुर्थांशों में विकसित)	05
	समग्र पाठ्यक्रम/पत्र/ई-पुस्तक में ई-विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/पत्र/ई-पुस्तक हेतु ई-विषयवस्तु का संपादन	10
4.	(क) शोध निर्देशन	
	पी0एच0डी0	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध
	एम0फिल0/स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि
	(ख) पूरी की गयी शोध परियोजनाएं	
	10 लाख से अधिक	10
	10 लाख से कम	05
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं	
	10 लाख से अधिक	05
	10 लाख से कम	02
	(घ) परामर्श सेवाएं	03
5.	(क) पेटेंट	
	अन्तर्राष्ट्रीय	10
	राष्ट्रीय	07
	(ख) नीति दस्तावेज (सं0रा0सं0/ यूनेस्को/ विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए)	
	अन्तर्राष्ट्रीय	10
	राष्ट्रीय	07
	राज्य	04
	(ग) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	
	अन्तर्राष्ट्रीय	07
	राष्ट्रीय	05

6.	अतिथि व्याख्यान / संसाधक / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुतीकरण/सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)	
	अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश)	07
	अन्तर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05
	राष्ट्रीय	03
	राज्य/विश्वविद्यालय	02

शोध पत्रों के लिए शोध के अंक निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

सहकर्मि द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार अवधारित किए जाने वाले प्रभाव कारक):

- (एक) प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र — 05 अंक
 (दो) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र — 10 अंक
 (तीन) 1 व 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र — 15 अंक
 (चार) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र — 20 अंक
 (पांच) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र — 25 अंक
 (छः) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र — 30 अंक

दो लेखक: प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत दो से अधिक लेखक: प्रथम/मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत संयुक्त परियोजनाएं: मुख्य अन्वेषक और सह-अन्वेषक में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा।

नोट:

- यदि संपादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों का भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षण और सह पर्यवेक्षण हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 प्राप्तांक मिलेंगे।
- अध्यापक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ 5 (ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध प्राप्तांक, आमंत्रित व्याख्याता / संसाधक/पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित अध्यापक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत के ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक छः श्रेणियों में से न्यूनतम तीन श्रेणियों से होंगे।

सारणी 3

विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड

क्रम संख्या	शैक्षणिक रिकॉर्ड	प्राप्तांक			
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक — 15	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम — 13	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम — 10	45 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत से कम — 05

2	स्नातकोत्तर	80 प्रतिशत और उससे अधिक-25	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम -23	55 प्रतिशत से लेकर [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 50 प्रतिशत (गैर क्रीमी लेयर) / शारीरिक रूप से निःशक्त] से 60 प्रतिशत से कम - 20
3	एम. फिल.	60 प्रतिशत और उससे अधिक -07	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम - 05	
4	पीएच. डी.			30
5	नेट सहित जे.आर. एफ.			07
	नेट			05
	एसएलईटी / एसईटी			03
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)			10
7	शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरेल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक)			10
8	पुरस्कार			
	अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार)			03
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार)			02

तथापि, यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट:-

- (क) (एक) एम. फिल. + पीएच.डी. अधिकतम = 30 अंक
 (दो) जे. आर. एफ./नेट/सेट अधिकतम = 07 अंक
 (तीन) पुरस्कार अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम = 03 अंक
 (ख) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
- | | | |
|-----|---------------------|------|
| (ग) | शैक्षणिक प्राप्तांक | -80 |
| | शोध प्रकाशन | -10 |
| | शिक्षण अनुभव | -10 |
| | कुल | -100 |
- (घ) यह अंक संबंधित राज्यों के एसएलईटी/सेट विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए वैध होंगे।

सारणी- 4

पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु निर्धारण मानदण्ड एवं प्रविधि

पुस्तकालयाध्यक्षों
 हेतु निर्धारण
 मानदण्ड और
 प्रविधि

क्रम संख्या	क्रिया कलाप	ग्रेडिंग मानदण्ड
1	पुस्तकालय में नियमित उपस्थिति (अपेक्षित उपस्थिति दिवसों के सापेक्ष उपस्थित होने वाले दिवसों के प्रतिशत की गणना) पुस्तकालय की उपस्थिति हेतु प्रत्येक से निम्नवत् कार्य की अपेक्षा होगी:- <ul style="list-style-type: none"> पुस्तकालय की पाठ्यसामग्री तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रतिवेदन का रखरखाव। शोधार्थियों के लिये साहित्य पुनर्प्राप्ति सेवाओं और रिपोर्टों के विश्लेषण जैसी पुस्तकालय में पाठकों को दी जाने वाली सेवाओं का उपबंध संस्थागत वेबसाइट को अद्यतन करने में सहयोग। 	90% और उससे अधिक- उत्तम 90% से कम किन्तु 80% और उससे अधिक-संतोषजनक 80% से कम- असंतोषजनक
2	पुस्तकालय की गतिविधियों अथवा विनिर्दिष्ट पुस्तकों या विद्या संबंधी संगोष्ठी /कार्यशाला का आयोजन।	उत्तम-1 राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी/ कार्यशाला + 1 राज्य/संस्थागत कार्यशाला/संगोष्ठी संतोषजनक- 1 राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी/कार्यशाला अथवा 1- राज्य स्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला + 1 संस्थागत संगोष्ठी/कार्यशाला अथवा 4-संस्थागत संगोष्ठी/कार्यशाला असंतोषजनक- उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में न आने वाला

3	<p>यदि पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस है अथवा</p> <p>यदि पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस नहीं है।</p>	<p>उत्तम- यदि पुस्तकों एवं पत्रिकायें भौतिक रूप 100% कम्प्यूटरीकृत है।</p> <p>संतोषजनक- यदि मूल पुस्तकें एवं पत्रिकाएं 99% कम्प्यूटरीकृत है।</p> <p>असंतोषजनक- उत्तम अथवा संतोषजनक श्रेणी में न होने पर अथवा</p> <p>उत्तम- 100% पुस्तक सूची का डाटाबेस अद्यावधिक होना।</p> <p>संतोषजनक - 90% डाटाबेस अद्यतन होना।</p> <p>असंतोषजनक- पुस्तक सूची डाटाबेस अद्यतन न होना। (सी.ए.एस. प्रोन्नति समिति द्वारा आकस्मिक रूप से सत्यापन किया गया)</p>
4	पुस्तकालय सामग्री और गुमशुदा पुस्तकों का मिलान	<p>उत्तम- जांच की गयी सूची और गायब पुस्तकें 0.5% से कम</p> <p>संतोषजनक- जांच की गयी सूची और गायब पुस्तकें 1% से कम</p> <p>असंतोषजनक- सूची की जांच न होना या जांच की गयी और गायब पुस्तकें 1% या अधिक</p>
5	<p>(एक) बिना कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस वाली संस्था में पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन</p> <p>(दो) पुस्तकालय नेटवर्क को बढ़ावा देना।</p> <p>(तीन) पुस्तकों एवं अन्य स्रोतों के सुलभ कराये जाने से संबंधित प्रक्रिया का व्यवस्थित होना।</p> <p>(चार) महाविद्यालय प्रशासन, शासन एवं अनुशासन से संबंधित कार्यों में सहयोग जिसमें प्रवेश, परीक्षाएं और शिक्षणेत्तर गतिविधियां शामिल हैं।</p> <p>(पांच) उपयोगकर्ताओं के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम तैयार करना एवं उपलब्ध कराना।</p> <p>(छः) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रिका में न्यूनतम एक शोध पत्र का प्रकाशन।</p>	<p>उत्तम- किन्हीं दो गतिविधियों में प्रतिभाग करना।</p> <p>संतोषजनक- कम से कम एक गतिविधि</p> <p>असंतोषजनक- किसी भी गतिविधि में प्रतिभाग/ वचनबद्ध न किया हो।</p>

समग्र ग्रेडिंग

समग्र ग्रेडिंग

उत्तम — आइटम 1 में अच्छा और आइटम 4 सहित किन्हीं दो अन्य आइटमों में संतोषजनक/उत्तम

संतोषजनक— आइटम 1 में संतोषजनक एवं आइटम 4 सहित किन्हीं दो आइटम में उत्तम/संतोषजनक होना।

असंतोषजनक— समग्र ग्रेडिंग में न तो उत्तम न ही संतोषजनक।

नोट:—(1) पुस्तकालय कर्मचारिवृंद की उपस्थिति एवं मूल्यांकन मानकों की गणना हेतु आईसीटी तकनीक के उपयोग को अनुमन्यता होगी।

(2) पुस्तकालय के अनिवार्य रूप से प्रकाशित प्रपत्रों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अथवा शोध पद्धति में प्रतिभाग किये जाने का प्रमाण—पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त पूर्णतः विषयक सफल शोध निर्देशन एवं परियोजना पूर्णता विषयक प्रमाण—पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

(3) सी.ए.एस. प्रोन्नति समिति के समक्ष उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनके दूर करने हेतु विस्तृत प्रणाली उपलब्ध करानी होगी।

अध्याय— दस

धारा 10(2)71

45—(क) महा महोपाध्याय मानद उपाधि के लिये डाक्टर आफ लेटर्स (डी०लिट०) की उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा संगीत, नृत्य एवं कला संकाय को समनुदेशित किये गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप में योगदान किया हो अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

(ख) कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जायें, मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति के अधीन पुष्टि के लिये प्रस्तुत कर सकती है:

परन्तु यह कि, किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो; ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

धारा 47 और 72

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र को वापस लेने के लिये धारा 72 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायेगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध विरचित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षित होगा कि वह आरोपों की प्राप्ति से अन्यून पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

धारा 47 और 72

(घ) मानद उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित होगी।

(ङ) किसी संस्थान को संबद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की सिफारिश के पश्चात् कार्य परिषद् द्वारा ऐसी संस्था के रूप में जहाँ अधिनियम की धारा 22 (1) (क) (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुसन्धान कार्य किया जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है। इस प्रकार की दी गयी मान्यता संबद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् द्वारा दी गयी सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा वापस ली जा सकती है।

(च) इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्धन इसमें निहित होगा:—

(एक) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद् को दी जायेगी; या

(दो) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त निदेशक।

उपाधियां, और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

(छ) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुसन्धान कार्य का मार्गदर्शन, संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें विश्वविद्यालय की अनुसन्धान की उपाधियों के लिए पर्यवेक्षक या सलाहकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(ज) संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे इस बात से सहमत हों, संबद्ध विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के अनुसन्धान छात्रों को उच्च कोटि की व्याख्यानमाला में व्याख्यान दे सकते हैं।

(झ) अपेक्षित अर्हतायें रखने वाला कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि के लिये संस्थान में अनुसन्धान कार्य करने का इच्छुक हो, संस्थान के निदेशक के माध्यम से कुल सचिव को आवेदन-पत्र देगा। इस प्रकार प्राप्त आवेदन-पत्रों की अध्यादेशों के अधीन गठित विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि समिति के समक्ष रखा जायेगा और यदि समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाय, तो आवेदक को ऐसी फीस का संदाय करने पर, जैसी विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाय, कार्य प्रारम्भ करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(ञ) संस्थान के लिए प्राप्त कोई विशिष्ट अनुदान या दान संस्थान के निमित्त रखा जायेगा और उसे संस्थान के लिये व्यय किया जायेगा। विश्वविद्यालय में किसी तत्समान शिक्षण विभाग के किसी अनुदान का कोई भाग किसी अन्य संस्थान के लिए व्यय नहीं किया जायेगा।

अध्याय- ग्यारह

क- भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता

विशेषाधिकार
युक्त
महाविद्यालयों का
विश्वविद्यालय में
प्रवेश और परीक्षा
केन्द्रों की मान्यता
तथा ऐसे
विशेषाधिकार और
मान्यता को वापस
लेने की प्रक्रिया

46-संक्षिप्त नाम लागू होना तथा प्रारंभ:

(1) परिनियम का यह अध्याय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता के संबंध में होगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

47-अस्थायी सम्बद्धता हेतु अर्हता मानदण्ड:

(1) सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अपेक्षाओं अथवा इनमें से किसी के भी संबंध में संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा केवल तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में विहित अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(2) त्वरित विद्या संबंधी तथा अन्य स्थान संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशासनिक, विद्या संबंधी तथा अन्य भवन पर्याप्त स्थान सुविधा के साथ महाविद्यालय में निर्मित प्रत्येक भवन निःशक्त के अनुकूल होने चाहिए।

(3) संकायों, व्याख्यान/संगोष्ठी कक्षों, पुस्तकालय के स्थान सुविधा के लिए पर्याप्त विद्या संबंधी भवन तथा प्रत्येक अभ्यास कक्ष में प्रति छात्र न्यूनतम 15 वर्ग फुट होना चाहिए। अन्य विशिष्ट व्यवहार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र की आवश्यकता पाठ्यक्रम कार्यक्रम की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

(4) विश्वविद्यालय मानक के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या होनी चाहिए।

(5) केन्द्र/राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जल, विद्युत, संवातन, शौचालय, सीवर आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त सिविल सुविधाएं हों;

(6) सुरक्षा, संरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि हेतु पर्याप्त उपाय हों;

(7) प्रत्येक विषय पर अलग-अलग शीर्षकों में कम से कम 1000 पुस्तकों वाला कोई पुस्तकालय, जो भी अधिक हो, यदि पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों, दोनों को सम्मिलित किया जाय, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक की सुविधा भी हो;

(8) विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित आवश्यक संगीत वाद्ययंत्र और उपकरण होने चाहिए;

(9) एक बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स / एक प्रेक्षागृह तथा खेल-कूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिश्चित बालक और बालिकाओं के लिए स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार पृथक कामन रूम तथा पृथक छात्रावास;

(10) व्याख्यान / संगोष्ठी कक्षों, पुस्तकालय, संकाय कक्षों, प्राचार्य सहित प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द के लिये कक्षों और प्रेक्षागृह, सामान्य कक्षों तथा छात्रावास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिए समुचित फर्नीचर हो;

(11) विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सम्यक् रूप से गठित प्रबंधन निकाय हो;

48—महाविद्यालय, यदि राज्य सरकार द्वारा न चलाया जा रहा हो तो:

(1) इसका प्रबंधन सम्यक् रूप से गठित और रजिस्ट्रीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा।

(2) यह विश्वविद्यालय को एक वचनबंध प्रदान करेगा कि उसके पास अपने सतत और कुशल संचालन के लिए स्वयं के संसाधनों से पर्याप्त आवर्ती आय है।

(3) रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरूप मामलों में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम के लिये इस शर्त के अधीन मौजूदा उपलब्ध भवन में महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियमावली के अधीन पूरा किया गया है और महाविद्यालय पैरा 50(6) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक महाविद्यालय को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने पर महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि महाविद्यालय स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

(4) किसी महाविद्यालय का प्रस्ताव करने वाली रजिस्ट्रीकृत सोसायटी/न्यास एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा।

49—केवल उन विषयों और उन्हीं संकायों में पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिये अनुदेश प्रदान करना होगा जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गयी हो तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धक की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के समुचित विद्या निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।

(1) इस संबंध में बनाए गए विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के समस्त उपबंधों का अनुपालन करना।

(2) समय-समय पर सांविधिक/विनियामक निकायों के द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करना।

(3) इस प्रभाव तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विहित अध्यापन पदों की संख्या, अध्यापन कर्मचारिवृन्द व शैक्षणिक अर्हता तथा भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवाशर्तें विश्वविद्यालय /राज्य सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिनियमों /अध्यादेश /विनियमों के अनुरूप होगी तथा महाविद्यालय द्वारा आरंभ किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम /कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा महाविद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानदण्डों के अनुसार होगा।

(4) इस प्रभाव तक कि अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द को नियमित रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /केन्द्र /राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय-समय पर चिह्नित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा,

(5) इस प्रभाव तक कि अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित अर्हता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(6) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए अध्यापकों पर अर्हता संबंधी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सभी परिवर्तनों तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जो कि विश्वविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।

(7) इस प्रभाव तक कि छात्रों पर प्रभारित किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।

(8) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षक से कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता हो।

(9) इस प्रभाव तक कि कोई भी महाविद्यालय किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक दाखिल नहीं करेगा।

(10) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम /कार्यक्रम को समाप्त नहीं करेगा।

(11) इस प्रभाव तक कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए विद्या तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर महाविद्यालय द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

(12) इस प्रभाव तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /विश्वविद्यालय / सरकार विनियामकों /आदेशों के अधीन रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित समस्त रजिस्ट्रों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(13) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /विश्वविद्यालयों /सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि विद्या स्तर को बनाए रखने के संबंध में महाविद्यालय के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय /सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर का बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /विश्वविद्यालय /सरकार द्वारा जो भी निदेश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए समस्त कार्यवाहियां करेगा।

50—अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

(1) नए महाविद्यालय को आरंभ करने के लिए तथा इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थाओं तथा रजिस्ट्रीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) यदि आवेदक एक सोसायटी/न्यास है, तो यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन या न्यास अधिनियम अथवा कोई भी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम के अधीन आवेदन के प्रस्तुतिकरण के दिनांक से पूर्व रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(3) सरकार/सोसायटी/न्यास, जिसका महाविद्यालय आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा जो अपने आपको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहता है और जिसके क्षेत्राधिकार में महाविद्यालय पड़ता है उसे नियत समय के भीतर विश्वविद्यालय को विहित प्रारूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट में विहित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए।

51-आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए:-

- (1) सोसायटी/न्यास का रजिस्ट्रीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित;
- (2) भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र;
- (3) संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र;
- (4) आवेदक के नाम में रजिस्ट्रीकृत भूमि /सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज;
- (5) सरकार द्वारा महाविद्यालय आरंभ करने के लिए सोसायटी /न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम /कार्यक्रम का ब्यौरा;
- (6) रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा;
- (7) प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए रजिस्ट्रीकृत सोसायटी /न्यास द्वारा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए भूमि को चिन्हित किया गया हो;
- (8) समग्र (कार्पस) निधि के साक्ष्य के साथ निधियों की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा तथा संगत बैंक खातों की छायाप्रति।

52-दिये गये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट:-

- (क) शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव सहित सोसायटी /न्यास की पृष्ठभूमि इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा इसके आरंभ होने से सामाजिक, धर्मार्थ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है;
 - (ख) समय-वार महाविद्यालय की विकास योजना, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों / अनुसंधान आरंभ किए जाने के संबंध में पहले 10 वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जिसमें छात्र सुविधाएं जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल हैं, के विकास के लिए स्तरवार समय अनुसूची;
 - (ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान;
 - (घ) संकाय नियुक्ति, उन्हें सेवा में बनाए रखने तथा विकास के संबंध में नीति;
 - (ङ) विद्या संबंधी तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा;
 - (च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के वित्तपोषण तथा प्रचालनात्मक व्यय का स्रोत; और
 - (छ) संसाधन संबंधी अनुमान तथा उनकी उपयोग अनुसूची।
- (1) विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा संतोषजनक पाए जाने पर और आवेदन प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर आशय का पत्र जारी करेगा ताकि अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सभी आवश्यकताओं के वास्तविक सत्यापन के लिए तीन माह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जा सके।
 - (2) कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण कराएगा जिसमें निम्नवत् समाविष्ट होंगे:-
 - (एक) प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ;
 - (दो) महाविद्यालय विकास परिषद् का संकायाध्यक्ष /विश्वविद्यालय का समकक्ष शिक्षाविद्;
 - (तीन) सरकार के संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक के स्तर से नीचे का न हो; और
 - (चार) लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से एक अभियन्ता जोकि अधिशासी अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो।
- कुलपति द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जो आचार्य स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।

नोटः—आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण बोर्ड के यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि जमा करनी होगी। निरीक्षण बोर्ड के सदस्यों को उनकी पात्रता के अनुसार टी0ए0 और डी0ए0 का लाभ मिलेगा।

(3) अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण समिति की रिपोर्ट सम्यक् रूप से भर कर तथा समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपने समुचित निकायों के माध्यम से रिपोर्ट संसाधित करेगा तथा महाविद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगा; तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

(4) महाविद्यालय में उपलब्ध अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लेगा।

(5) विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् सम्बद्धता प्रदान किए जाने या न किए जाने के निर्णय पर अंतिम प्राधिकारी होगी।

(6) महाविद्यालय के अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में अस्थायी सम्बद्धता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर इन विनियमों में उपबंधित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(7) यदि विश्वविद्यालय किसी कारण के चलते महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह सम्बद्धता प्राप्त करने के संबंध में शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता को लिखित में दर्ज करेगा, यदि पश्चातवर्ती महाविद्यालय शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, परन्तु यह पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने के दिनांक से छह माह तक आवेदन नहीं कर सकता है।

नोटः—संबद्धता शुल्क, वार्षिक निरंतरता शुल्क और सभी शुल्क जमा करने का विशिष्ट दिनांक विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जायेगा।

53—स्थायी सम्बद्धता के लिए पात्रता मानदण्ड

(1) महाविद्यालय को समय-समय पर विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित विद्या संबंधी तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किए हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए जाने चाहिए।

(2) महाविद्यालय द्वारा विनियमों में निर्धारित भवनों का निर्माण कार्य तथा सभी अवसंरचनात्मक/सुविधाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।

(3) समस्त अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारिवृन्द को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार (सरकारी महाविद्यालय के मामले में नियमित आधार) पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

(4) महाविद्यालय में मानदण्डों के अनुसार सम्यक् रूप से गठित महाविद्यालय परिषद् होनी चाहिए।

(5) महाविद्यालय का प्रत्यायन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य मान्यता एजेंसी द्वारा हुआ होना चाहिए।

54—स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

(1) जो महाविद्यालय स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता हो, उसे अस्थायी सम्बद्धता के पांच वर्ष पूरे करने पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क सहित प्ररूप में आवेदन करना चाहिए।

(2) स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, विनियमों में दी गई अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जैसी ही होगी।

(3) यदि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्रदान न किए जाने का निर्णय लेता है, तो इस प्रकार की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, तत्पश्चात् यदि महाविद्यालय शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो महाविद्यालय पूर्व में किए गए आवेदन की अस्वीकृति के दिनांक से छः माह पश्चात् पुनः आवेदन कर सकता है।

55—अध्ययन के नए कार्यक्रमों को जोड़ने हेतु आवेदन करने की पात्रता

(1) विश्वविद्यालय द्वारा नया कार्यक्रम जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव पर केवल उच्च शिक्षा हेतु सुविधाओं का समान वितरण सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा, ऐसा विशेष रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे क्षेत्र जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, अविकसित, ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के पश्चात् ही किया जाएगा।

(2) विद्यमान स्नातक पूर्व महाविद्यालय के स्तर को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पूर्व कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा किए जाने के पश्चात् तथा विनियम के अनुसार प्रस्तावित भवन, योग्य संकाय तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से सृजन किए जाने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

(3) नया कार्यक्रम जोड़ने के लिए अथवा विद्यमान कार्यक्रम का स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नयन करने के प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क भी साथ लगा होना चाहिए।

(4) अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने तथा महाविद्यालय में विद्यमान कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्रक्रिया, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विनियमों में विहित प्रक्रिया के समान ही होगी।

56—सम्बद्धता समाप्त करना

(1) यदि जांच करने पर महाविद्यालय, अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबंधों या नियमों और विनियमों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ विश्वविद्यालय/ सांविधिक/ संबंधित विनियामक निकाय के अन्य निदेशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्बद्धता की किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है या इस प्रकार आचरण करता है जोकि विश्वविद्यालय के विधा तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो सम्बद्धता के माध्यम से महाविद्यालय को प्रदान किए विशेषाधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है या उसमें उपांतर किया जा सकता है।

(2) यदि कोई सम्बद्ध महाविद्यालय कार्य करना बंद कर देता है अथवा किसी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के वह किसी भिन्न स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है तो महाविद्यालय को दी गयी सम्बद्धता इस प्रकार की अस्तित्वहीनता, स्थानांतरण या हस्तांतरण, जैसी भी स्थिति हो, स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया महाविद्यालय माना जाएगा। विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

(3) विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय की जांच करायी जा सकती है तथा महाविद्यालय को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) (4) के अधीन इस प्रकार के महाविद्यालय को इस प्रकार के विनिर्दिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उपाधि प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और महाविद्यालय की सम्बद्धता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) (5) के अधीन समाप्त मानी जाएगी।

(4) यदि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की सम्बद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय महाविद्यालय के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के अधीन कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय रजिस्ट्रीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय / सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वे समुचित रीति से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।

(ख) परीक्षा केंद्र

1—परीक्षा केन्द्र की मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के साथ स्वीकार किये जायेंगे।

2—यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर होने वाला वास्तविक व्यय संबंधित संस्था वहन करेगी। निरीक्षक मंडल में तीन सदस्य होंगे, जिनमें से दो विषय विशेषज्ञ होंगे और कुलपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व करेगा। समिति निरीक्षण के पश्चात् मान्यता के संबंध में केंद्र का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

3—आवेदन प्राप्त होने पर, कुलपति एक निरीक्षक बोर्ड नियुक्त करेगा जो संस्था का भ्रमण करेगा और निम्नलिखित के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा—

(क) कि संस्था एक विधिवत रजिस्ट्रीकृत निकाय है;

(ख) कि संस्था के पास व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के लिए आवास, फर्नीचर, संगीत वाद्ययंत्र आदि की व्यवस्था करने की क्षमता है;

(ग) संस्था के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं हुई है, जो इसे परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता से वंचित कर सकती है।

4—निरीक्षक मंडल की रिपोर्ट संस्था के दौरे के दो सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाएगी और उसे विचार के लिए कार्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

5—कार्य परिषद रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संस्था सशर्त, यदि कोई हो, के साथ आवश्यक मान्यता प्रदान करेगी या आवेदन को अस्वीकार कर देगी।

6—एक परीक्षा केंद्र में न्यूनतम पचास छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, ऐसा न करने पर कार्य परिषद की सहमति के अधीन परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यदि परिषद को परीक्षा केंद्र का पक्ष सही लगता है तो वह कुछ केंद्रों को विशेष मामले के रूप में एक या दो साल तक बहाल रखने पर विचार कर सकती है।

7—वार्षिक निरंतरता शुल्क और समस्त शुल्क जमा करने का विनिर्दिष्ट दिनांक विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जायेगा।

8—मान्यता प्राप्त केंद्रों के विशेषाधिकारों को वापस लेना।

(क) जब भी किसी प्रतिकूल प्रतिवेदन या विहित शर्तों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप, कार्य परिषद किसी संस्थान को दी गई मान्यता के लिए दिए गए सभी या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए कार्यवाही शुरू करना आवश्यक समझती है, कार्य परिषद स्वयं के निर्णय से संस्था को अवगत कराते हुए उस शासी निकाय या सरकार को, जैसी भी स्थिति हो, कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। अग्रतर यह कि एक संस्था जो मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र है को एक निश्चित अवधि के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए प्रवेश दिया जाता है और यदि मान्यता को बहाल नहीं रखा जाता है तो विशेषाधिकार स्वतः वापस ले लिया जायेगा।

(ख) उप- पैरा (क) के अधीन नोटिस में होगा कि,—

(क) कारण जिनके लिए आशयित कार्रवाई पर विचार किया गया है और

(ख) कारण बताओ नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय के कुलसचिव तक पहुंचने का विनिर्दिष्ट समय;

(ग) अभिलिखित कारणों के लिये कार्य परिषद उत्तर के लिए अवधि समय-समय पर बढ़ा सकती है किन्तु कुल अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी;

(घ) उप- पैरा (2) और (3) के अधीन नियत अवधि के भीतर महाविद्यालय को कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर, कार्य परिषद संबंधित मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र द्वारा दिये गये उत्तर और अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के आलोक में मामले पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् मामले पर विचार कर सकता है और किसी संस्था को दिए गए मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र को दिए गए समस्त या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के रूप में उचित समझे जाने वाला आदेश दे सकता है।

विश्वविद्यालय, अनुसंधान के लिए छात्रों को आंतरिक उम्मीदवारों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नियमित केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुसंधान केंद्र होंगे।

अनुसंधान केंद्र

अनुसंधान केंद्र

1-अनुसंधान केंद्र की संबद्धता के लिए पहली बार या अनुसंधान के लिए एक नया पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए सरकार के अधिकारी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसी संबद्धता चाहने वाली संस्थापक सोसायटी/शासी निकाय प्रासंगिक प्रस्ताव की एक प्रति के साथ केंद्र को सरकार द्वारा या संस्थापक सोसायटी/शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा बनाए रखा जाता है।

2-समस्त आवेदन विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव के पास पहुंचेंगे।

3-संबद्धता और/या विषय/पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्रपत्र पर संस्था का विवरण संलग्न किया जाएगा।

4-शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा।

नोट:-उपरोक्त विहित शुल्क के अतिरिक्त, संबंधित केंद्र यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का वास्तविक व्यय वहन करेंगे। कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया तीन निरीक्षकों का एक बोर्ड संबद्धता के लिए केंद्र के निरीक्षण के बाद अवसरचर्चात्मक ढांचे के विषय में विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन देगा।

5-सभी विवरणों और शुल्कों के साथ पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित आवेदन प्राप्त होने पर कुलपति, निरीक्षकों का एक बोर्ड नियुक्त करेगा, जिसमें शिक्षण संकायों के दो विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय प्रशासन का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा।

6-निरीक्षकों का बोर्ड केंद्रों का निरीक्षण करेगा और निर्धारित नियमानुसार विश्वविद्यालय को निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

7-केंद्र के पास उसके नाम से पाँच लाख रुपये मात्र की स्थायी निधि जमा होगी जिसका उपयोग विशेष रूप से केंद्र के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

8-केंद्र में एक अच्छे पुस्तकालय का उपबंध होगा।

9-फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, संगीत वाद्ययंत्र/उपकरण और दृश्य कला के लिए स्टूडियो उपकरण आदि जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं।

10-विश्वविद्यालय को संबंधित केंद्र के भ्रमण के दो सप्ताह के अन्दर सभी सदस्यों का सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट निरीक्षक बोर्ड को प्रस्तुत किया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे अनुमोदन के लिए विद्या परिषद और कार्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा। कार्य परिषद के अनुमोदन के पश्चात् अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् केंद्र को स्थायी संबद्ध केंद्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

संबद्ध केंद्रों के विशेषाधिकारों की वापसी :-

1-जब भी किसी प्रतिकूल रिपोर्ट या विहित शर्तों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप, कार्य परिषद किसी केन्द्र को दी गई मान्यता के लिए दिए गए समस्त या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए कार्यवाही आरम्भ करना आवश्यक समझती है, कार्य परिषद स्वयं के निर्णय से अवगत कराते हुए उस शासी निकाय या सरकार को, जैसा भी मामला हो, कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। इसके अतिरिक्त जब किसी केन्द्र को एक कतिपय अवधि के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए प्रवेश दिया जाता है और संबद्धता को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो विशेषाधिकार स्वतः वापस ले लिए गए माने जायेंगे।

2-उप-पैरा (1) के अंतर्गत नोटिस में होगा,—

(क) वे कारण, जिनके लिए अभीष्ट कार्यवाई पर विचार किया गया है; और
(ख) कारण बताओ नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय के कुलसचिव तक पहुंचने का विनिर्दिष्ट समय।

3-अभिलिखति कारणों से कार्य परिषद प्रतिउत्तर के लिए अवधि समय-समय पर बढ़ा सकती है किन्तु कुल अवधि तीन माह से अधिक की नहीं होगी।

4-उप- पैरा (2) और (3) के अधीन नियत अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर, कार्य परिषद संबंधित केंद्र द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर और अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के आलोक में मामले पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् मामले पर विचार कर सकता है और किसी केन्द्र या संस्था को दिए गए सभी या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के रूप में उचित समझे जाने वाला आदेश दे सकता है।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

महाविद्यालयों और परीक्षा केन्द्र की संबद्धता/मान्यता हेतु आवेदन-पत्र

इस प्ररूप का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजन के लिये किया जा सकता है:-

1-संस्थाओं की संबद्धता/मान्यता

2-अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/ विषयों के लिए संबद्धता / मान्यता

3-संबद्धता/मान्यता का विस्तार

भाग— एक

(सभी संस्थाओं द्वारा भरा जाना है)

1-महाविद्यालय का नाम :

2-पूरा पता :

दूरभाष संख्या :

कार्यालय :

निवास स्थान :

फैक्स नं० :

ईमेल :

3-प्राचार्य का नाम :

(जन्मतिथि और अर्हता के विवरण का उल्लेख करते हुये सम्पूर्ण बायोडाटा संलग्न करें)

4-(गैर सरकारी महाविद्यालय हेतु)

दिनांक

(क) महाविद्यालय/केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण संख्या

दिनांक

(ख) शासी निकाय/सोसायटी का नाम

दिनांक.....

(ग) शासी निकाय/सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण संख्या

दिनांक

(घ) शासी निकाय के सदस्यों का पदनाम सहित नाम व पता (सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित सूची पृथक रूप में संलग्न करें) एवं परिनियम की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।

5-क्या शासी निकाय कोई अन्य शैक्षणिक संस्था चलाता है।

यदि हां

(क) संस्था का नाम :

(ख)संबद्धता का विवरण :

(ग) अन्य :

6-महाविद्यालय की स्थापना का दिनांक:

भाग— दो

(मात्र उन महाविद्यालयों/केन्द्रों के लिए, जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं)

7-अपेक्षित सम्बद्धता संगीत

नृत्य

लोक संगीत

दृश्य कला

जो भी लागू हो उस पर सही का निशान लगायें।

8-सम्बद्धता/मान्यता के लिए पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण। (परिशिष्ट-एक देखें)

9-क्या महाविद्यालय किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, यदि हाँ उसका पूर्ण विवरण दें।

10-अध्यापन/गैर अध्यापन कर्मचारिवृंद का विवरण। (परिशिष्ट-दो देखें)

11-क्या शासी निकाय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के नियमानुसार वेतनमान स्वीकार करता है

हाँ

नहीं

12-क्रम सं० 10 पर अंकित अध्यापकों के वेतनमान का विवरण। (परिशिष्ट - दो देखें)

13-प्रस्तावित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित विवरण उपलब्ध करायें (पृथक से संलग्न करें)

(क) कक्षाओं का विवरण (कक्षाओं की संख्या व माप)

(ख) फर्नीचर

(ग) वाद्ययंत्र/उपकरण

(घ) पुस्तकें, जर्नल एवं पत्रिकाएं (पुस्तकों की संख्या और सब्सक्राइड जर्नल्स के नाम उल्लिखित करें)

14-महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति:

क-अचल सम्पत्तियां

(1) जमा धनराशि

(2) वाद्ययंत्रों की अनुमानित लागत

(3) भूमि व भवन की अनुमानित लागत (यदि लागू हो)

ख-वार्षिक आय (यदि आवश्यक हो तो पृथक से शीट संलग्न करें)

1-सरकार से या किसी अन्य अभिकरण से प्राप्त अनुदान

2-दान

3-शिक्षण शुल्क

4-अन्य शुल्क

5-अन्य स्रोत (यदि कोई हों)

ग-गत 03 वर्षों का ऋण करार, संपरीक्षित तुलन-पत्र सहित ऋण खाता का विवरण (यदि कोई हों)

15-भवन का विवरण: भवन नक्शा (ब्लू प्रिंट) संलग्न करना अनिवार्य है।

(क) कक्षाओं की संख्या व माप (पृथक सूची संलग्न करें)

शौचालयों की संख्या

पुरुष:

महिला:

(ख) प्रेक्षागृह का विवरण- माप

क्षमता

(ग) खेल के मैदान का विवरण (यदि उपलब्ध हो तो)

(घ) क्रीड़ा/खेलकूद की सामग्रियों की पृथक सूची संलग्न करें।

(ड.) क्या भवन स्वामित्व में है, किराये पर है या दान में प्राप्त है

स्वामित्व

किराये

दान

यदि स्वामित्व में है तो आवंटन रजिस्ट्रीकरण पत्र संलग्न करें।

यदि किराये पर है तो किराया उल्लिखित करें।

यदि दान में है तो निबंधन और शर्तें उल्लिखित करें। (दान व किराये विलेख की प्रति संलग्न करें)

(च) यदि शासकीय भवन में कक्षाएं संचालित होती हैं तो अनुमोदन की प्रति संलग्न करें।

(ज) यदि कोई अन्य व्यवस्था हो, तो विवरण दें।

16—महाविद्यालय/केन्द्र के बैंक खाता का विवरण:—

(क) बैंक का नाम

(ख) शाखा का नाम

(ग) खाते का प्रकार

(घ) खाते के संचालन हेतु प्राधिकृत अधिकारी का विवरण:

17—महाविद्यालय का समय।

भाग— तीन

केवल नये पाठ्यक्रमों/विषयों की सम्बद्धता/मान्यता के विस्तार की माँग करने वाले महाविद्यालय /केन्द्र द्वारा भरा जायेगा।

1—ऐसे पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण जिनके लिए सम्बद्धता/मान्यता पहले प्राप्त की गयी है: (परिशिष्ट तीन)

2—ऐसे पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण जिनके लिए सम्बद्धता मांगी गयी:

1— पाठ्यक्रम

2— विषय

3— पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या:

3—विश्वविद्यालय को देय बकाया राशि, यदि कोई हो, का विवरण :

4—प्रस्तावित सम्बद्धता / मान्यता के लिए सरकार / शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करें :

5—प्रस्तावित सम्बद्धता के लिए सरकार / शासी निकाय को देय बकाया राशि, यदि कोई हो, का विवरण:

6—नवीन पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:—

1— अतिरिक्त कक्षाएँ

2— वाद्ययंत्र/उपकरण

3— पुस्तकें

4— फर्नीचर

7—क्या महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही दी गई संबद्धता की समस्त निबन्धन और शर्तें पूरी कर ली हैं? यदि नहीं तो कारण बतायें:

पुनर्भुगतान शर्तों सहित ऋण खाते का विवरण (यदि कोई हो तो)

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यह भी आश्वासन देता हूँ कि महाविद्यालय/केन्द्र समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित निबन्धन और शर्तों का पालन करेगा।

शासी निकाय के अध्यक्ष

का हस्ताक्षर

(गैर राजकीय

महाविद्यालयों के लिए)

कानूनी अधिकारी

के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

मुहर

क: अध्यापन कर्मचारिवृन्द

सं०	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	अर्हता		नियुक्ति का दिनांक	वेतन (वेतनमान)
				शैक्षणिक	वृत्तिक		
1		प्राचार्य					
2							
3							
4							
5							
6							
7							

ख: गैर अध्यापन कर्मचारिवृन्द

सं०	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	अर्हता	नियुक्ति का दिनांक	वेतन (वेतनमान)
1		प्राचार्य				
2						
3						
4						
5						
6						
7						

धारा 45

अध्याय—बारह

57—(1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में अनधिक एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य परिषद् नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

धारा 45

58—इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा विनियम में दिया गया हो।

धारा 45

59—जहां विश्वविद्यालय को परिनियम के अनुसार दीक्षांत समारोह आयोजित करना सुविधाजनक नहीं लगता है, वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं संबंधित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं।

दीक्षांत समारोह प्रक्रिया—उपाधि प्रदान करने और पुरस्कार देने के प्रयोजनार्थ दीक्षांत समारोह साधारणतया प्रति वर्ष दिसम्बर माह में विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा और ऐसे समय पर आयोजित किया जाएगा जैसा कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा आवश्यक या सुविधाजनक पाया जाये—

दीक्षांत समारोह प्रक्रिया

1—विश्वविद्यालय अपने पात्र छात्रों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में नियमित रूप से उपाधि और अन्य पुरस्कार प्रदान करेगा।

2—रोजगार, उच्च अध्ययन और/या अन्य अवसरों के लिए जाने वाले पात्र छात्रों को बिना विलम्ब किए उनकी उपाधि और अन्य पुरस्कार देकर सहायता करेगा।

3—दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए कुलसचिव द्वारा साधारणतया अन्यून चार सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा तथापि, विशेष दीक्षांत समारोह के मामले में या किसी अन्य मामले में जहां कुलपति द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को समीचीन माना जाता है, इस अवधि को घटाकर 10 दिन किया जा सकता है।

4—व्यक्तिगत रूप से उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को दीक्षांत समारोह के लिए निर्धारित दिनांक से 15 कैलेंडर दिन पूर्व कुलसचिव के पास दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने के अपने आशय की संसूचना से विहित प्रपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। परन्तु यह कि कुलपति विशेष मामलों में दीक्षांत समारोह के दिनांक से सात दिन पूर्व तक देर से आवेदन प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं, यदि ऐसे आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित विलंब शुल्क लगाया जाता है।

5—ऐसे अभ्यर्थी जो दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, के अनुपस्थिति में दीक्षांत समारोह के दिनांक के एक माह पश्चात् अध्यक्षता प्रपत्र में शुल्क और डाक शुल्क के साथ अपनी उपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

6—प्रत्येक उपाधि पर कुलपति के हस्ताक्षर होंगे। उपाधि पर दिनांक चाहे दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाए या अन्यथा, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दिनांक के समान होगी। इसके अलावा, यदि किसी कारण से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है, तो उपाधि पर दिनांक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी।

7—कुलाधिपति, कुलपति, संकायाध्यक्ष, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सदस्य और कुलसचिव उस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पोशाक पहनेंगे जहां से वे स्नातक हैं या कार्य परिषद द्वारा विहित गाउन या कोई अन्य पोशाक पहनेंगे।

8—दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थियों को कार्य परिषद द्वारा विहित शैक्षणिक पोशाक पहननी होगी और किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा विहित शैक्षणिक वस्त्र के बिना दीक्षांत समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9—दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थियों को उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिश्चित दीक्षांत समारोह के पश्चात् अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान, समय और दिन पर वितरित की जाएगी।

10—विश्वविद्यालय पात्र छात्रों को उपाधि और अन्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्धारित तिथियों पर दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा या कोई अन्य विधि अपनाएगा।

11—यदि दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है, तो इसमें उनके लिए किए गए उपबंधों के अनुसार औपचारिक पहलू सम्मिलित होंगे।

12—यदि किसी कारण से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है, तो विश्वविद्यालय इस समय केवल पात्र आवेदकों को उपाधि और अन्य पुरस्कार प्रदान करेगा।

13—विश्वविद्यालय के पास समनुदेशित चयनित महाविद्यालय को अपनी ओर से निर्धारित दिनांक पर अपने छात्रों के लिए स्नातक समारोह आयोजित करने की शक्ति होगी।

14—ऐसे महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के निदेशों का पालन करना अपेक्षित होगा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्नातक समारोह आयोजित करना होगा।

15—कुलाधिपति, संकायाध्यक्ष, कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्य और कुलसचिव अधिसूचित स्थान पर इकट्ठा होंगे और निम्नलिखित क्रम में शोभा यात्रा के साथ दीक्षांत समारोह स्थल तक चलेंगे:—

1. कुलसचिव
2. विद्या परिषद् के सदस्य
3. कार्य परिषद के सदस्य
4. संकायाध्यक्ष
5. कुलपति
6. मुख्य अतिथि, यदि कोई हो
7. कुलाधिपति

16—कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, कुलपति, मुख्यमंत्री, संस्कृति मंत्री, संकायाध्यक्ष, कार्य परिषद के सदस्य, सचिव संस्कृति विभाग, कुलसचिव और कार्य परिषद द्वारा नामित ऐसे अन्य व्यक्ति डाइज पर और कार्य परिषद के सदस्यगण अपने लिए आरक्षित स्थानों पर डाइज के सामने अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

17—दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थियों को शोभा यात्रा के दीक्षांत समारोह पैनल में प्रवेश करने से पहले अपने लिए आरक्षित स्थानों पर अपना स्थान ग्रहण करना होगा। जब शोभा यात्रा दीक्षांत समारोह हॉल/पंडाल में प्रवेश करता है, तो उपस्थित समस्त जन खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि शोभा यात्रा के सदस्य क्रमशः अपना-अपना स्थान नहीं ग्रहण कर लेते हैं।

18—कुलसचिव, कुलाधिपति की अनुमति से या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति की अनुमति से दीक्षांत समारोह की शुरुआत की घोषणा करेगा। कुलाधिपति के अनुरोध पर और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। प्रस्तुतीकरण का क्रम निम्नलिखित होगा:—

1. मानद उपाधियाँ, यदि कोई हो
2. डी0लिट0
3. पी0एच0डी0
4. स्नातकोत्तर

निम्नलिखित संकायों में उपाधियाँ:-

1. संगीत संकाय
2. नृत्य संकाय
3. दृश्य-कला संकाय
4. कला एवं भाषा संकाय
5. लोक संगीत एवं कला संकाय

19-अपने-अपने संकायों के संकायाध्यक्ष संकाय के अधीन विभिन्न उपाधियों के लिए समस्त अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करेंगे और कुलपति संबंधित उपाधियों के लिये उनकी अनुपस्थिति में भी उपस्थित अभ्यर्थियों के रूप में स्वीकार करेगा। संकायाध्यक्ष और कुलपति के लिए प्रोद्घरण परिषद द्वारा यथाविहित किया जाएगा, उपाधि प्राप्तकर्ता संकायाध्यक्ष के साथ खड़े रहेंगे और कुलाधिपति उपाधि के लिये अभ्यर्थियों को अंगीकार करेगा।

20-मानद उपाधियाँ प्रदान करने के मामले में, प्राप्तकर्ता को उपाधि ग्रहण करने वाले प्रोद्घरण को कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त रीति से संशोधित किया जा सकता है। दीक्षांत समारोह में उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति में भी नियमित और व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदत्त की जायेगी।

21-कुलाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति पदक और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पदक और पुरस्कार प्रदान करेगा, जिन्हें पदक और पुरस्कार का मांगकर्ता कहा जाएगा, जिन्हें कुलसचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा और कुलाधिपति के समक्ष खड़ा होना होगा एवं कुलसचिव द्वारा घोषित किया जाएगा।

22-कुलाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति मुख्य अतिथि से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अनुरोध करेगा।

23-तत्पश्चात् दीक्षांत समारोह का संबोधन दिया जाएगा। कुलाधिपति की अनुमति से और उनकी अनुपस्थिति में कुलपति की अनुमति से कुलसचिव दीक्षांत समारोह की समाप्ति की घोषणा करेगा और शोभा यात्रा दीक्षांत समारोह से निकल जायेगी, जब तक शोभा यात्रा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक सभी लोग खड़े रहेंगे।

24-परिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कुलाधिपति, वार्षिक दीक्षांत समारोह या दीक्षांत समारोह के आयोजन का स्थगन कर सकता है। ऐसे मामले में अभ्यर्थियों को कुलपति द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित उपाधियाँ उनके पते पर प्रेषित की जाएंगी। कुलसचिव दीक्षांत समारोह के स्थगन की सूचना देगा और अभ्यर्थिकों से ऐसे आवेदन आमंत्रित करेगा जो उपाधि लेने का इच्छुक हैं और ऐसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक निर्धारित करेगा। उपाधि उन अभ्यर्थियों को प्रेषित की जाएगी जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर डाक शुल्क सहित विहित शुल्क के भुगतान पर उपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थी जो उपाधि प्राप्त करने के लिए सम्यक् दिनांक के भीतर आवेदन नहीं करते हैं उन्हें अनुपस्थिति की दशा में उपाधि दी जाएगी और अनुपस्थिति में उपाधि के लिए निर्धारित शुल्क दिया जाएगा। ऐसी उपाधि पर दिनांक विद्या परिषद की स्थायी समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा निर्धारित दिनांक होगा।

25-उपाधि प्रदान करने का दिनांक छात्रों के अर्हता प्राप्त करने और इसके लिए पात्र होने के अपेक्षित दिनांक से 180 दिनों के भीतर होगी। इसके अतिरिक्त, उपाधियों के समय पर वितरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अपने-अपने संबंधित महाविद्यालयों के माध्यम से अभ्यर्थियों की उपाधियाँ वितरित करने पर विचार कर सकता है।

26-पाठ्यक्रम और परीक्षाओं जैसी शैक्षणिक क्रियाकलापों के कार्यक्रम के अलावा, वार्षिक कैलेंडर में उपाधि प्रदान करने का दिनांक भी सम्मिलित होगा।

27-यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय एक वर्ष में एक से अधिक बार उपाधि प्रदान करने का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है और इसे अपने शैक्षणिक कैलेंडर में भी सम्मिलित करेगा।

अध्याय तेरह

प्रकीर्ण

अध्यापन पदों का
सृजन और इसे
भरा जाना**60—अध्यापन पदों का सृजन और इसे भरा जाना—**

(1) विश्वविद्यालयों में अध्यापन पद, जहां तक संभाव्य हो, पिरामिड क्रम में अधिनियम की धारा 29 (1)(क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सृजित किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए, आचार्य के एक पद के लिए, प्रति विभाग सह-आचार्य के दो पद और सहायक आचार्य के चार पद होंगे।

(2) विश्वविद्यालय प्रणाली में समस्त स्वीकृत/अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

वर्क—लोड

61—वर्क—लोड—

(1) शिक्षकों का वर्क— लोड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा।

अन्य उपबंध

62—अन्य उपबंध

इस परिनियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्य उपबंध, जो इस परिनियमावली द्वारा आच्छादित नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता) के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

अध्याय चौदह

विश्वविद्यालय के
मृतक कर्मचारियों
के आश्रित का
नियोजन**63—विश्वविद्यालय के मृतक कर्मचारियों के आश्रित का नियोजन**

यदि सेवा में रहते हुए किसी स्थायी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और यथास्थित पत्नी या पति, जो पहले से ही केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी बोर्ड या निगम के अधीन नियोजित नहीं है या राज्य सरकार (जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित है) उसके परिवार के किसी सदस्य, जो पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार (जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित है) के अधीन नियोजित नहीं है, को श्रेणी तृतीय या श्रेणी चतुर्थ की सीधी भर्ती के रिक्त गैर-अध्यापन पद के लिए चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु-सीमा, में छूट के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर सकता है, परन्तु यह कि वह कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर आवेदन करता हो और ऐसे रिक्त गैर-अध्यापन पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित करता हो।

(1) 'आश्रित' का तात्पर्य मृतक का पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, विधवा या विधुर से है;

(2) कर्मचारी के अन्तर्गत संस्था में नियोजित अध्यापक/गैर अध्यापन कर्मचारिवृंद में सम्मिलित है।

परिभाषाएं

अध्याय पन्द्रह

64—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, उप परिनियमावली में,—

(1) 'परीक्षक' का तात्पर्य परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से है।

(2) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) 'विश्वविद्यालय के अधिकारी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग) से (ज) तक में किसी उल्लिखित अधिकारी से है।

65-(1) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अबचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिये कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर, ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसे अध्यापेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा:

परन्तु यह कि कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी :—(1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और दिखाया जायेगा।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है:—

(क) जहाँ व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है;

(ख) जहाँ हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेंडर स्वीकार करने से हुयी हो;

(ग) जहाँ विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(घ) जहाँ विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुयी हो; जहाँ विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति को अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुयी हो।

(3) उस अधिकारी को जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यापेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये अध्यापक सुविधाएं देगा। परीक्षक, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण: अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति करने का अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति की वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन को हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

विहित अवधि को समाप्ति के पश्चात और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, अवचार करने के पश्चात, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है:

परन्तु यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयवन और प्रथक्तः देनदार होगा:

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात, इसमें जो पश्चातवर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

अधिभार आदेश
के विरुद्ध अपील

66—परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यक्ति अधिकारी, उस मंडल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विखंडित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

अधिभार का
भुगतान

67—(1) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रसर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा:

परन्तु यह कि यदि परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाये।

(2) यदि अधिभार को धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो व भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

अधिभार आदेश
के विरुद्ध वाद

68—जहाँ अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद, संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परोक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रातिवाद करने में उपगत समस्त खर्च का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब से करें।

69—विश्वविद्यालय के ऐसे समस्त विद्यमान परिनियम और ऐसे समस्त अध्यादेश जो इस परिनियमावली से असंगत हों ऐसी असंगति की सीमा तक विखंडित किये जाते हैं और तत्काल प्रभावहीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बंध में, जो ऐसे निरस्तीकरण के पूर्व की गई हो या की जाने से छूट गई हों।

परिशिष्ट 'क'
अध्याय- नौ
विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृंद के सदस्यों के साथ
करार-प्रपत्र

विश्वविद्यालय के
अध्यापन
कर्मचारिवृंद के
सदस्यों के साथ
करार-प्रपत्र

यह करार आज दिनांक को श्री..... प्रथम पक्ष तथाविश्वविद्यालय (जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया:

एतद्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है:-

1-विश्वविद्यालय, एतद्वारा, श्री/श्रीमती/कुमारी को दिनांक से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्य भार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्वारा नियुक्त स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिनकी उससे उपेक्षा की जाये, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्चा या नैवासिक कार्य-कलाप के सम्बन्ध में छात्र-कल्याण को प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जाये तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता हूँ जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्सम रखा जाये और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाये, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा:

परन्तु अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद स्वविवेकानुसार परीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है।

2-प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3-अध्यापक के पद का, जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान..... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जब वे अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान..... में रूपया प्रतिमास की दर से वेतनमान दिया जायेगा और वह, जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा:

परन्तु जहां समयमान में कोई दक्षता रोक विहित है, वहां दक्षता रोक के ऊपर अगली वेतन वृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को वेतन वृद्धि रोकने के लिये सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायेगी।

4-प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकार, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निदेशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

5-प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाये, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6-किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुएं जो उसके कब्जे में हों, विश्वविद्यालय को दे देगा।

7-समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा उन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2022 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों में प्रथम उपरलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगायी।

अध्यापक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व
करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1.....

2.....

परिशिष्ट 'ख'
अध्यापकों के लिये आचरण संहिता

चूंकि जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के संबंध में जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरुक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओत-प्रोत रहकर उपदेश की उपेक्षा आचरण द्वारा आधिक कर सकता है;

अतएव, अब उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनायी जाती है कि इसका पालन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाये:-

- (1) प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।
- (2) कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।
- (3) कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध अपने साथ या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।
- (4) कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता व भाषा के आधार पर शिष्यों में भेदभाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिये उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।
- (5) कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने में इन्कार नहीं करेगा।
- (6) कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बंध में प्राधिकृत न हो।
- (7) कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार अंशकालिक गृहशिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षाएँ नहीं चलायेगा।
- (8) कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।
- (9) शैक्षिक कार्यक्रम पूरा कराने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक जहाँ तक सम्भव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।
- (10) निरन्तर अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।
- (11) यथास्थिति विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के शैक्षिक उत्तरदायित्व यथा प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण, परिप्रेक्ष्य, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेगा।
- (12) लोकतंत्र देश भक्ति और शान्ति के आदर्शों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करेगा।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1281/IV-2025-4095-2023, dated April 15, 2025:

No. 1281/IV-2025-4095-2023

Dated Lucknow, April 15, 2025

IN exercise of the powers under section 46 read with section 45 of the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2022 (U.P. Act no. 2 of 2022), the Governor is pleased to make the following First Statutes for the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya.

The Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya First Statutes, 2025

CHAPTER I

	1.(1) These Statutes may be called the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya First Statutes, 2025.	Short Title and Commencement
	(2) They shall be deemed to have come into force with effect from April 15, 2025.	
Section 45	2. (1) In these Statutes, unless the context otherwise requires, -	Definitions
	(a) 'Act' means the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2022 (Act no. 2 of 2022);	
	(b) "affiliation" together with its grammatical variations, includes, in relation to a college with, and admission of such college to the privileges of Bhatkhande Sanskriti University;	
	(c) 'clause' means a clause of the statute in which that expression occurs;	
	(d) "college" means any institution, whether known as such or by any other name which provides for a programme of study beyond 12 year of schooling for obtaining any qualification from the university and which in accordance with the rules and regulations of the university, is recognized by the university as competent to provide for such programme of study;	
	(e) "course" means one of the units which comprise a programme of study;	
	(f) "grant-in-aid college" means a 'college' receiving grants from the Government for payment of salary of its employees;	
	(g) "programme"/programme of study means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under Section 22 (3) of the UGC Act;	
	(h) "Statutory /Regulatory body" means a body so constituted by a Central/State Government Act for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education;	
	(i) "student" means a person admitted to and pursuing a specified programme of study;	
	(j) 'Section' means a section of the Act;	
	(k) 'University' means the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya.	
	(2) Words and expression used in the Act but not defined in these Statutes shall have the meaning assigned to them in the Act.	
Section 45	(3) In these Statutes, all references to the age of teachers, shall be construed to be references to the date of birth of the teachers concerned as mentioned in his High School Certificate or that of any other examination recognized as equivalent thereto.	

Officers and other functionaries of the University**CHAPTER II**

The Chancellor	Section 10 (4)	<p>3. (1) The Chancellor may, while considering any matter referred to him under Section 68, call for such document or information from the University or parties concerned, as he may deem necessary and may, in any other case, call for any documents or information from the University.</p> <p>(2) Where the Chancellor calls for any documents or information from the University under clause (1), it shall be the duty of the Registrar to ensure that such documents or information are promptly supplied to him.</p>
The Vice Chancellor	Section 12 & 45 (C)	<p>4. The Vice-Chancellor shall have power to call for such documents and information from an associated college in respects of any matter connected, with teaching, examination, research, finance or any matter affecting the discipline or efficiency of teaching in the college, as he thinks fit.</p>
The Registrar	Sections 14(3), 20(1) VII, 20(8) 45(C) & (e)	<p>5. (1) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, the Registrar shall have disciplinary control over all employees of the University, other than the following namely -</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Officers of the University; (b) teachers of the University, whether in relation to their work as teachers or while holding any remunerative officer or in any other capacity, such as examiner or invigilator; (c) the Librarian; (d) other employees referred to in Section 17; (e) Employees in the University in the Accounts and Audit Section. <p>(2) The Power to take disciplinary action under clause (1) shall include the power to order dismissal, removal, reduction in rank, reversion termination or compulsory retirement of an employee referred to in the said clause, and shall also include the power to suspend such employee during pending inquiry, if any.</p> <p>(3) No order shall be made under clause (2) except after an inquiry in which the employee has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and where it is proposed after such inquiry, to impose on him any such penalty, until he has been given a reasonable opportunity of making representation on the penalty proposed, but only on the basis of the evidence adduced during such inquiry:-</p> <p>Provided that this clause shall not apply in the following cases, notwithstanding that the order is based on any charge (including a charge of misconduct or inefficiency), if such order does not disclose on its face that it was passed on such basis -</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) An order of reversion of an officiating promote to his substantive rank. (b) An order of termination of service of a temporary employee. (c) An order of compulsory retirement of an employee after he attains the age of fifty years. (d) An order of suspension.

Sections 20 & 45	(4) An employee of the University aggrieved by an order referred to in statute 6 (1) may prefer an appeal (through the Registrar) to the Disciplinary Committee Constituted under Statute 20 (1) within fifteen days from the date of service of such order on him. The decision of the Committee on such appeal shall be final.
Section 14	(5) Subject to the provisions of the Act, it shall be the duty of the registrar: - <ul style="list-style-type: none"> (a) to be the custodian of all properties of the University unless otherwise provided for by the Executive Council; (b) to issue all notices convening meetings of the various authorities referred to in Section 14(4) with the approval of the competent authority concerned and to keep the minutes of all such meetings; (c) to conduct the official correspondence of the Executive and the Academic Council; (d) to exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellors, Vice-Chancellor or various authorities or bodies of the University of which he acts as Secretary; (e) to represent the University in suit or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings.
Section 9 (D)	6. (1) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance officer is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by one of the Deans of the Faculties nominated by the Vice-Chancellor and if for any reason the same is not feasible, then by the Registrar or by such officer as may be nominated by the Vice-Chancellor.
Section 15 (7)	(2) (a) shall exercise general supervision over the funds of the University; <ul style="list-style-type: none"> (b) may advise in any financial matter either <i>Suo moto</i> or on his advice being sought; (c) shall keep a constant watch on the state of the cash and bank balances, and on the state of investments; (d) shall collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University; (e) shall ensure that the registers of building, land furniture's and equipment are maintained up-to-date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the University; (f) shall probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest the competent authority, disciplinary action against persons at fault; (g) may call for any information or return form any department or unit of the University that he may consider necessary for the performance of his duties; (h) shall arrange for the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf; (i) shall perform such other functions in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor; (j) shall, subject to the provisions of the Act and the Statutes, exercise disciplinary control in terms of clauses (2) and (3) of Statute 6 (1) over all the employees in the Audit and Accounts Section of the University below the rank of the Assistant Registrar (Accounts) and shall supervise the work of the Deputy/Assistant Registrar (Accounts) and the Accounts Officer.

The Finance
Officer

Deans of Faculties	Sections 12 (9), 15 (7)	(3) If any difference of opinion arises between the Vice-Chancellor and the Finance Officer on any matter concerning the performance of the functions of the Finance Officer, the question shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding on both the officers.
	Sections 27 (3) & 45	7. (1) if a casual vacancy occurs in the office of the Dean of a Faculty, the senior most professor and if there is no Professor in the Faculty, the office of Dean shall be held by Associate Professors and if there are no Associate Professors, then by other teachers in that Faculty, in order of seniority. (2) no person shall continue to be Dean after he has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of Dean.
	Sections 27 (4)	(3) A teacher who on the date of commencement of these Statutes has and:- (a) held the office of Dean for a period of three years or more, shall be deemed to have had his turn and the teachers next eligible in order of seniority shall assume office as Dean with effect from the commencement of these Statutes; (b) Not completed three years as Dean shall continue to hold the office of Dean till the completion of the period of three years and on such completion the teacher next eligible in order of seniority shall assume office as Dean. (4) For the purpose of computing the period during which a teacher has held the office of Dean and:- (a) any period during which such teacher was office of Dean by an order of any Officer of the University or of any court, shall be excluded; (b) any period during which any teacher has, under an order of any officer of the University or of any court, been allowed to hold the office of Dean, it being ultimately found that he was not legally entitled to hold such office during that period, shall count towards his term of office of Dean when he next gets his turn.
	Section- 18	(5) The Dean of the Faculty shall have the following duties and powers: (i) He shall preside at all meeting of the Board of Faculty and shall see that the various decisions of the Board are implemented. (ii) He shall be responsible for bringing the financial and other needs of the faculty to the notice of the Vice-Chancellor. (iii) He shall take necessary measures for the proper custody assets of the departments comprised in the faculty. (iv) He shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies pertaining to his faculty but shall have no right to vote thereat unless he is a member thereof.
The Dean of Students Welfare	Sections 18 (4)	8. (1) The Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, who possess teaching experience of not less than 10 years and who are not below the rank of a Associate Officer, by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.
	Sections 45	(2) The teacher who is appointed as Dean of Students' Welfare shall perform his duties as Dean in addition to his own duties as teacher.
	Sections 45	(3) The term of office of the Dean of Students' Welfare shall be three years unless terminated earlier by the Executive Council: Provided that the Dean of Students' Welfare holding office as such on the date immediately preceding the date of commencement of these statutes shall be deemed to have been appointed under Statute 8(1).

(4) The Dean of Students' Welfare shall be assisted by a set of teachers (to be selected in the manner laid down in the Statute), who shall perform their duties in addition to their normal duties of teacher. The teachers so selected shall be called Assistant Deans of Students' Welfare.

(5) One of the Assistant Deans of Students' Welfare shall be appointed from amongst the lady teachers of the University who shall look after the welfare of the girl students.

(6) It Shall be the duty of the Dean of Students' Welfare and the Assistant Deans of Students' Welfare to assist generally the students in matters requiring help and guidance and, in particular, to help and advice students and prospective students in and:-

- (a) obtaining admission to the University and its courses.
- (b) the choice of suitable courses and hobbies.
- (c) finding living accommodation.
- (d) making messing arrangements.
- (e) obtaining medical advice and assistance.
- (f) securing scholarship, stipends, part-time employments and other pecuniary assistance.
- (g) obtaining travel facilities for holidays and educational excursions.
- (h) securing facilities for further studies abroad and;
- (i) so conducting themselves in proper pursuit of academic studies as to maintain the traditions of the University.

(7) The Dean of Students' Welfare may communicate with the guardian of a student in respect of any matter requiring his assistance when necessary.

(8) The Dean of Students' Welfare shall exercise general control over the Superintendent or Assistant Superintendent of Physical Education, if any, and the University Medical Officer. He shall perform such other duties as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(9) The Vice-Chancellor may consult with the Dean of Students' Welfare before taking any action against a student on disciplinary grounds.

(10) The Dean of Student's Welfare may be paid such honorarium out of the funds of the University as the Vice-Chancellor may fix with prior approval of the State Government.

9. (1) The appointment of the Head of department shall be made by the Vice-Chancellor in pursuance to the principle of rotation to the possible extent. Such appointment shall be intimated to the Executive Council.

Head of
Department

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), if a senior teacher who under existent rotation is senior to those who have served as heads of the department or those junior teachers, who have been serving in the same capacity, could not be appointed on the post of the Head of department for some reason or other, it shall be upon the Vice-Chancellor that he appoints the senior teacher as Head of the department in the department concerned as and when the post of Head of the department falls vacant, provided that he is eligible to be appointed as such.

(3) The tenure of the Head of department shall be of three years' duration normally, a person shall not be appointed as the Head of the department for second consecutive term:

(4) Notwithstanding anything contained in clause (1) and (2), in the event of pendency in the appointment of the Head of the department or in case of absence due to leave, the Vice- Chancellor after assessing the situation prevalent, may direct a Professor or a Associate Professor of the department concerned, either to respond the duties of the Head of the department or to perform as the Head of the department, as the case may be purely on *ad hoc* basis.

Note: The principle of rotation shall be applicable in order of seniority. A teacher who has earlier served or has been serving as Head of the department, the teacher who is the next senior, shall be entitled to the post of the Head of the department.

(5) The Head of each department shall exclusively be the Professor of the department concerned. In case, there is only one Professor in a department or a Professor does not possess eligibility to be appointed as Head of the department, an Associated Professor may be appointed as Head of the department and in case, no Professor or Associate Professor in a department eligible to be appointed as Head of the department, the senior most teacher shall perform the duties of the Head of the department concerned.

(6) The Heads of the department who have completed their tenure of three years shall be replaced immediately and who have not yet completed their tenure of three years, shall be placed after they complete residue tenure.

The Librarian

Section
29.1(e)

10. (1) The University may, with the prior approval of the State Government, appoint a whole time Librarian. The Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee, consisting of the following namely:-

(a) the Vice-Chancellor.

(b) two experts in Library Science to be nominated by the Chancellor.

(2) Until the Librarian appointed under clause (1) assumes charge of his office, the Executive Council may appoint an honorary Librarian from amongst the Professors of the University for such Terms as it thinks fit.

(3) The qualifications of the Librarian shall be such as may be provided for in the Statutes.

(4) The emoluments of the Librarian shall be such as may be approved by the State Government.

(5) It shall be the duty of the Librarian to maintain the Library of the University and to organize its service in the manner most conducive to the interest of teaching and research.

(6) The Librarian shall be under the disciplinary control of the Vice-Chancellor:

Provided that he shall have a right of appeal to the Executive Council against any order of the Vice-chancellor passed in the disciplinary proceedings against him.

Sections
17 & 45

11. (1) The Proctor shall be appointed from amongst the teachers of the University by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. The Proctor shall assist Vice-Chancellor in the exercise of his disciplinary authority in respect of students of the University and shall exercise such power and perform such duties in respect of discipline as may be assigned to him by the Vice-Chancellor in this behalf.

(2) The proctor shall be assisted by Assistant proctor whose number shall be fixed by the Executive Council from time to time.

(3) The Assistant Proctors shall be appointed by the Vice-Chancellor in consultation with the proctor.

(4) The Proctor and the Assistant Proctor shall hold office for one year and shall be eligible for re-appointment:

Provided that for so long as his successor is not appointed every Proctor or Assistant Proctor shall continue in office:

Provided further that the Executive Council may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, remove the Proctor before the expiry of the said period:

Provided also that the Vice-chancellor may remove an assistant Proctor before the expiry of the said period.

(5) The Proctor and the Assistant Proctors may be paid such honorarium out of the funds of the University, as may be fixed by the Vice-Chancellor with prior approval of the State Government.

12. (1) There shall be a Proctor in the University, who shall be in-charge of the discipline in the University Campus.

(2) The appointment of the Proctor shall be on such terms as may be prescribed by the Executive Council from time to time in this behalf.

(3) Subject to the control of the Vice-Chancellor, the Proctor shall be responsible for maintenance of discipline among the students of the University in the premises of the University.

(4) All cases of breach of discipline on the part of any student or students shall be reported by the Proctor to the Vice-Chancellor for such action as may be deemed appropriate in the matter. He shall have powers to question any student as also to make enquiries from any one present in the University Campus so as to enable him to maintain discipline.

(5) The Proctor shall give all help to the University in organizing its functions as may be required of him from time to time.

(6) Whenever required by the Proctor, students shall produce forth-with his Identity Card before him. He shall also be in-charge of issue of Identity Cards to the students. He shall have powers to recommend fines to the Vice-Chancellor.

(7) The Proctor may advise the Vice-Chancellor on any matter connected, directly or indirectly, with the maintenance of the discipline in the University Campus.

(8) (a) Cases of breach of discipline occurring under the Jurisdiction of Hostel Wardens, Librarian and Class Teachers shall be reported directly to the Vice-Chancellor by the Officer concerned.

(b) The provisions of this Statute do not preclude the Librarian or Hostel Wardens or Class Teachers in maintaining discipline amongst students under their jurisdiction.

(9) The Proctor shall have powers to recommend to the Vice-Chancellor to fine any student who, in his opinion, has been found guilty of in disciplinary act.

The Proctor

Powers and
Functions of the
Proctor

CHAPTER III

The Executive Council	Sections 19	13. (1) The Deans of Faculties who shall be members of the Executive Council under section-19 shall be chosen in the order in which the names of various Faculties are enumerated in statue 16(1).
	Section 19	(2) Representation of members of the University under clause (i) of Section 19 shall be according to the Act.
	Section 45	(3) No person shall be or continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and whenever a person so becomes a member of the Executive Council in more than one capacity, he shall within two weeks thereof choose the capacity in which he desires to be member of the Executive Council and shall vacate the other seat. Where he does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks.
	Section- 21	(4) The Executive Council may, be resolution passed by a majority of its total membership delegate such of its powers as it deems fit to an officer or authority of the University subject to such conditions as may be specified in the resolution.
	Section- 20 & 45	(5) The meetings of the Executive Council shall be called under the directions of the Vice-Chancellor.
	Section 20 & 45	(6) The Executive Council shall obtain the opinion of the Finance Officer before considering any proposal involving financial implications
		(7) The member of the Executive Council shall be the officers of the University.

CHAPTER-IV

Academic Council	Sections 22	14. (1) Representation of members of the University under clause (iii) of Section 22 shall be according to the Act.
		(2) The Vice-Chancellor shall convene to the Registrar a meeting of the Academic Council at any time on his own initiative or on receipt of a requisition signed by not less than 5 members of the Academic Council.
		(3) Not less than 3 week's notice shall be given of the time and place of meeting.
		(4) 6 members inclusive of the Chairman shall form a quorum.
		(5) In absence of the Vice-Chancellor the meeting shall elect a member to preside at the meeting.
		(6) At all meetings of the Academic Council Chairman shall have a vote and the casting vote.
		(7) Notice of a motion or resolution to be moved at a meeting of the Academic Council must be in the hands of the Registrar not less than 14 days before the meeting.
		(8) Notice of an amendment to a motion or resolution, of which notice has been given must be in the hands of the Registrar at least 7 days before the meeting of the Academic Council at which the motion or resolution is to be moved.
		(9) Notwithstanding anything contained in paras 14 (3) and 14 (6) the Chairman may allow a motion of which the required time limit, has not been given to be moved or discussed when the motion is one to accept or to act. Upon any recommendation or report of any authority, Board, Council, Committee or Sub-Committee of the University or of a Committee or Sub-Committee of any such body and where it would have been impossible to

give the notice required by paras 6 and 7 of this chapter, provided that the Chairman is satisfied that for the purpose of carrying on the work of the University it is necessary to obtain an immediate decision upon the motion.

(10) The regulation relating to notice a business and discussion at meetings of the Executive Council Academic Council shall be applied so far as may be at meetings of the Academic Council.

(11) There shall be a meeting of the Academic Council every year to be called the annual meeting.

(12) The following procedure shall be followed in respect of propositions for the conferment of Honorary Degrees, viz:-

(a) Every proposition for the conferment of an honorary degree shall be referred for consideration to a committee consisting of the Vice-Chancellor, before it is included on the agenda paper of a meeting of the Academic Council.

(b) The committee shall consider if the person proposed.

(i) is distinguished for his learning/art; or

(ii) has rendered eminent services to the cause of education/art; or

(iii) has, by his munificence promoted the cause of education/art; or

(iv) has rendered outstanding public service in other ways, and is otherwise fit in all respects for the conferment of the degree.

If, after such consideration, it commends the proposition to the acceptance of the Academic Council its report shall be placed before Academic Council along with the proposition.

(c) If the committee is of opinion that it is advisable to drop all further proceedings relating to the proposition the opinion shall be communicated to member giving notice of the proposition and no further action shall be taken in the matter unless the confirms in writing his intention to move the proposition in which case the proposition shall be placed before the Academic Council along with the proceedings of the committee on the subject.

(d) All propositions for the conferment of the honorary degree shall be put to vote (i) without discussion and (ii) by ballot.

(e) No propositions for the conferment of an Honorary Degree shall be declared to have been passed by the Academic Council, unless a majority of not less than 2/3rd of the members present at the meeting vote in its favour.

CHAPTER-V

Sections
24, 25, 26
& 45

15. (1) Items of new expenditure not already included in the financial estimates, shall be referred to the Finance Committee:

The Finance
Committee

(i) In the case of non-recurring expenditure, if it involves an expenditure of ten thousand rupees or above; and

(ii) In the case of recurring expenditure if it involves an expenditure of three thousand rupees or above:

Provided that it shall not be permissible for any officer or authority of the University to treat an item which has been split into several parts falling under a budget head as several items of smaller amount and withhold it from the Finance Committee.

Section 24, 25, 26 & 45 (2) The Financial Committee shall, on or before such date as may be provided for in this behalf by the Statute consider all items of expenditure referred to it under Statute 15 (1), or Statute 15 (3), and shall make and communicate to the Executive Council as soon as may be, its recommendations thereon.

(3) If the Executive Council, at any time after the consideration of the annual financial estimates (i.e. the budget) proposes any revision thereof involving recurring or non-recurring expenditure of the amounts referred to in Statute 15(1), the Executive Council shall refer the proposal to the Finance Committee.

(4) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

(5) A member of the Finance Committee shall have the right to record a minute of dissent, if he does not agree with any decision of the Finance Committee.

(6) The meetings of the Finance Committee shall be convened under the directions of the Vice-Chancellor and all notices for convening such meetings shall be issued by the Finance Officer who shall keep the minutes of all such meetings.

CHAPTER VI

The Faculties/
Department of
Studies

Section
27 (1)

16. (1) The University shall have the following faculties namely:-

- (i) Music
- (ii) Dance
- (iii) Visual Arts
- (iv) Arts and Languages
- (v) Folk Music and Arts

Department of
Studies

(2) Department of Studies

(i) The following shall be the departments of Studies in the faculties as shown below against the names of the faculties:-

1. FACULTY OF MUSIC

- i. Department of Vocal Music (Hindustani)
- ii. Department of Instrumental Music
- iii. Department of Percussion Instruments.

2. FACULTY OF DANCE

- i. Department of Kathak Dance.
- ii. Department of Bharatnatyam Dance.
- iii. Department of Manipuri Dance.

3. FACULTY OF VISUAL ARTS

- i. Department of Painting.
- ii. Department of Sculpture.
- iii. Department of Graphics.
- iv. Department Applied Art.
- v. Department of History of Art and Aesthetics.
- vi. Department of Craft & Design.

4. FACULTY OF ARTS AND LANGUAGES

- i. Department of Hindi.
- ii. Department of English.
- iii. Department of Sanskrit.
- iv. Department of Ancient Indian History. Culture & Archaeology.
- v. Department of Lifelong Learning .
- vi. Department of Theatre.
- vii. Centre of Yoga.
- viii. Department of Philosophy.

5. FACULTY OF FOLK MUSIC AND ARTS

- i. Department of Folk Music.
- ii. Department of Folk Dance.

17. (1) Each Faculty shall consist of the following members: -

Constitution and
Functions of the
Faculties

- (i) Dean of the Faculty.
- (ii) All Head of the department of the studies in the faculty.
- (iii) All professor in the faculty.
- (iv) One Associate Professor and one Assistant Professor by rotation according to seniority from each department of study in the faculty.
- (v) Two Associate Professor from among the colleges any providing courses of the studies upto under graduation or equivalent course by rotation according to seniority.
- (vi) Three teacher from among the colleges any providing postgraduate courses by rotation according to seniority.
- (vii) One person from each department of Faculty not connected with the university and having expert knowledge of the subject and co-opted by the Faculty.
- (viii) Two external members elected by the Academic council for their special knowledge of any subject of the faculty.

(2) Subject to the provisions of the Act, the Faculty shall have following powers: -

1. Subject to the control of the Academic Council to organize curriculum and research work of the University in the subjects assigned to the Faculty.
2. To recommend to the Academic Council the courses of studies for the different examinations after consulting the departments of studies.
3. Subject to the control of the Academic Council to regulate the conditions for the award of degrees, diplomas and other distinctions.
4. To deal with any matter referred to it by the Academic Council or assigned by Ordinances and Regulations.

(3) One third of the total number of the faculty as provided in the above constitution shall constitute a quorum.

18. The Board of Studies will be constituted as follows-

Board of Studies

- a. The concerned Dean will be the Chairman of the Board of Studies.
- b. The Heads of the University Departments of the subjects for which the Board has been constituted.
- c. One Professor and one Associate Professor from the University Departments who teaches the said subjects, who will be nominated by the Vice-Chancellor in turn according to seniority.
- d. Not more than two Assistant Professors of the subjects who will be nominated by the Vice-Chancellor.
- e. One member to be co-opted by the Board, who shall be an external subject expert.
- f. The term of the Board of Studies shall be three years.
- g. A quorum can be made from 3 members, in which it is mandatory to have an external subject expert.

CHAPTER VII
(Section-76)

Standing
Committees

19. Subject to the provisions of the Act and the Statutes, any authority of the University may from time to time, appoint such and so many standing committees or sub-committees or boards as it may deem fit and may if it deems fit appoint to them. Persons who are not members of such authorities. Such committees or boards may deal with any subject delegated to them subject to subsequent confirmation by the authority appointing them.

Disciplinary
Committee

Section
45

20. (1) The Executive Council shall constitute for such time as it thinks fit a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice- Chancellor, or the Pro Vice-Chancellor nominated by him, and two persons nominated by it:

Provided that if the Executive Council considers it expedient, it may constitute more than one such Committee to consider different cases or classes of cases.

(2) No teacher against whom any case involving disciplinary action is pending shall serve as member of the Disciplinary Committee dealing with the case.

(3) The Executive Council may at any stage transfer any case from one Disciplinary Committee to another Disciplinary Committee.

Section
45

(4) (1) The functions of the Disciplinary Committee shall be as follows:

(a) to decide any appeal preferred by an employee of the University under Statute.

(b) to hold inquiry into cases involving disciplinary action against a teacher or the Librarian of the University.

(c) to recommend suspension of any employee referred to in sub-clause (b) above pending or in contemplation of inquiry against such employee.

(d) to exercise such other powers and perform such other functions as may, from time to time, be entrusted to it by the Executive Council.

(2) In case of difference of opinion among the members of the Committee, the decision of the majority shall prevail.

(3) The decision or the report of the Disciplinary Committee shall be laid before the Executive Council as early as possible, to enable the Executive Council to take its decision in the matter.

Departmental
Committees

Section
45

(4) There shall be a Departmental Committee in each Department of teaching in the University to assist the Head of the Department appointed under Statute 9(1).

Section
45

(5) The Departmental Committee shall consist of:

(i) The Head of the Department, who shall be the Chairman.

(ii) All Professors in the Department, and if there is no Professor, then all Associate Professors in the Department.

(iii) In a department which has no Professors as well as Associate Professor then two Assistant Professor by rotation according to seniority for a period of three years:

Provided that for any matter specifically, concerning any subject or specifically, the senior-most teacher of that subject or specialty if not already included in the foregoing heads, shall be specially invited for the matter.

(6) The following shall be the functions of the departmental committee:

(i) to make recommendations regarding distribution of teaching work among the teachers of the departments.

(ii) to make suggestions regarding co-ordination of the research and other activities in the Department.

(iii) to make recommendations regarding appointment of staff in the Department for which the Head of Department is the appointing authority.

(iv) to consider matters of general and academic interest to the department.

Section
45

(7) The Committee shall meet at least once in a quarter. The minutes of its meeting shall be submitted to the Vice-Chancellor.

Section
45

21. The Examination Committee may, on the recommendation of the person or persons or the sub-committee referred to in section- 29, debar an examinee from appearing in any future examination for a period of three years, if in the opinion of the Committee, such examinee was guilty of misbehavior or using of unfair means at any examination conducted by the University.

Examination
Committee

CHAPTER-VIII

Section
29 & 46

22. (1) In the Faculties of Arts and Language, Music, Dance, Visual Arts and Folk Music and Arts, there shall be following classes of teachers:

Classification of
Teachers

(1) Professor

(2) Associate Professor

(3) Assistant Professor

(2) Teachers of the University shall be appointed in the subjects on whole time basis in the scales of pay approved by the State Government:

Section
29 & 46

Persons working as Research fellows or as Research Assistants may be called upon to act as part- time teachers.

Section
29

(3) The Executive Council may on the recommendations of the Academic Council appoint.

(4) Professors of academic eminence and outstanding merit on special contract in accordance with the Statute/Ordinances in that behalf.

(5) Honorary Emeritus Professors who shall:

(a) deliver lectures on special subject;

(b) guide research;

(c) be entitled to be present in meetings of the Board of Faculty concerned and to take part in its discussions but will not have the right of vote;

(d) be provided with facilities for study and research in the libraries and laboratories of University as far as possible; and

(e) be entitled to attend all convocations:

Provided that a person shall not, merely by virtue of holding the post of a Professor in the Department as an Honorary Emeritus Professor be eligible to hold an office in the University or in any Authority or Body thereof.

(6) (a) Instructors or Teaching Research Assistants may be appointed by the Executive Council on such terms and conditions as may be provided for in the Statute/Ordinances.

Appointment of
Honorary
Professor and
Terms and
Conditions
therefore

23. An Honorary Professor or Associate Professor, appointed by the Executive Council for their scholarship and high intellectual attainments on the recommendations of the Academic Council shall have the following functions and privileges, viz :-

Functions

(A) FUNCTIONS -

1. To deliver a course of atleast 6 lectures in an Academic year on some topics of his subject either by way of new interpretation or by way of fresh orientation or on new trends in his subject.

2. To guide the students in their practical classes.

3. To guide the research workers in the capacity of recognised Professor and also to deliver a special course of lectures in his subject as a recognised Professor or Associate Professor.

Privileges

(B) PRIVILEGES -

i. An Honorary Professor shall be a member of the University Library but he shall in no way be connected with the University administration and shall have no representation on anybody of the University.

ii. He shall be provided with residential facilities available during the period of his visit to the University and shall be entitled to an honorium decided by the University from time to time.

iii. An Honorary Professor or Associate Professor shall be paid T.A. and D.A. in accordance with the rules prescribed by the state govt. from time to time.

CHAPTER – IX

PART-I

Minimum
Qualification of
teachers

24. Minimum qualifications for the posts of Senior Professors, Professors and Teachers, and other Academic Staff in University and Colleges and revision of pay scales and other Service Conditions pertaining to such posts.

Coverage

(1) Coverage

Minimum qualifications for appointment and other service conditions of University teachers and cadres of Librarians, for maintenance of standards in higher education and revision of pay-scales.

(2) For the purposes of direct recruitment to teaching posts in disciplines relating to University Teachers.

i. Provided that where no such norms and standards have been laid down by the statute, UGC Regulations herein shall be applicable till such time as any norms or standards are prescribed by the appropriate regulatory authority.

ii. Provided further that for appointment to the post of Assistant Professor and equivalent positions pertaining to disciplines in which the National Eligibility Test (NET), conducted by the University Grants Commission or State level Eligibility Test (SLET) or the State Eligibility Test (SET), conducted by bodies accredited by the UGC for the said purpose, qualifying in NET/SLET/SET shall be an additional requirement.

25. Pay Scales and Pay FixationPay Scales and
pay Fixation

(1) The date of implementation of the revision of pay shall be 1st January, 2016.

26. Recruitment and Qualifications.Recruitment and
Qualifications

(1) The direct recruitment to the posts of Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the University and Senior Professor in the University, shall be on the basis of merit through an all-India advertisement, followed by selection by a duly-constituted Selection Committee as per the provisions made under this Statute.

(2) The minimum qualifications required for the post of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor, Assistant Librarian, Deputy Librarian, Librarian, in this Statute.

(3) I. The National Eligibility Test (NET) or an accredited test (State Level Eligibility Test SLET/SET) shall remain the minimum eligibility for appointment of Assistant Professor and equivalent positions wherever provided in this Statute. Further, SLET/SET shall be valid as the minimum eligibility for direct recruitment:

Provided that candidates who have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009, or the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016, and their subsequent amendments from time to time, as the case may be, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or any equivalent position in the University:

Provided further that the award of degree to candidates registered for the M.Phil./Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree. All such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in the University subject to the fulfillment of the following conditions:

- a. The Ph. D. degree of the candidate has been awarded in regular mode only;
- b. The Ph. D. thesis has been awarded by at least two external examiners;
- c. An open Ph. D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d. The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;
- e. The candidate has presented at least two papers, based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ ICSSR/CSIR or any similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

II. The clearing of NET/SLET/SET shall not be required for candidates in such disciplines for which NET/SLET/SET has not been conducted.

(4) A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed) at the Master's level shall be the essential qualification for direct recruitment of teachers and other equivalent cadres at any level.

I. A relaxation of 5% shall be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes (OBC)(Non-creamy Layer)/Differently-abled [(a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness] for the purpose of eligibility and assessing good academic record for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure.

(5) A relaxation of 5% shall be provided, (from 55% to 50% of the marks) to the Ph.D. Degree holders who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.

(6) A relevant grade which is regarded as equivalent of 55%, wherever the grading system is followed by a recognized university, at the Master's level shall also be considered valid.

(7) The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for appointment and promotion to the post of Professor.

(8) The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for appointment and promotion to the post of Associate Professor.

(9) The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for promotion to the post of Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12) in the University.

(10) The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of Assistant Professor in University with effect from 01.07.2021.

(11) The time taken by candidates to acquire M.Phil. and / or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions. Further the period of active service spent on pursuing Research Degree simultaneously with teaching assignment without taking any kind of leave, shall be counted as teaching experience for the purpose of direct recruitment/ promotion. Regular faculty members upto twenty per cent of the total faculty strength (excluding faculty on medical / maternity leave) shall be allowed by their respective institutions to take study leave for pursuing Ph.D. degree.

Qualifications

27. Qualifications:

No person shall be appointed to the post of University and College teacher, Librarian, in the university or its affiliated colleges recognised under clause (f) of Section 2 of the University Grants commission Act, 1956, if such person does not fulfil the requirements as to the qualifications for the appropriate post as provided in this Statute.

28. Direct RecruitmentDirect
Recruitment**(1) For the Disciplines of Arts, Humanities and Languages****I. Assistant Professor:****Eligibility (A or B) :**

A. (i) A Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

(ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET :

Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in University/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions :-

- a. The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in a regular mode;
- b. The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c. An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d. The Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal;
- e. The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC / ICSSR/ CSIR or any similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.

OR

B. The Ph. D. degree has been obtained from a foreign university/ institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following: (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) the Times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World University (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).

Note: The Academic score as specified in Appendix II, shall be considered for short-listing of the candidates for interview only, and the selections shall be based only on the performance in the interview.

Associate
Professor**II. Associate Professor:****Eligibility:**

- i. A good academic record, with a Ph.D. Degree in the concerned/allied/relevant disciplines.
- ii. A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed).
- iii. A minimum of eight years of experience of teaching and / or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/industry with a minimum of seven publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and a total research score of Seventy five (75) as per the criteria given in Appendix II, Table 2.

Professor

III. Professor:**Eligibility (A or B) :**

A.i. An eminent scholar having a Ph.D. degree in the concerned/allied/relevant discipline, and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with, a minimum of 10 research publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and a total research score of 120 as per the criteria given in Appendix II.

ii. A minimum of ten years of teaching experience in university/college as Assistant Professor/Associate Professor/Professor, and / or research experience at equivalent level at the University/National Level Institutions with evidence of having successfully guided doctoral candidate.

OR

B. An outstanding professional, having a Ph.D. degree in the relevant/allied/applied disciplines, from any academic institutions (not included in A above) / industry, who has made significant contribution to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, supported by documentary evidence provided he/she has ten years' experience.

Senior Professor
in University**IV. Senior Professor in University**

Up to 10 percent of the existing sanctioned strength of Professors in the university may be appointed as Senior Professor in the University, through direct recruitment.

Eligibility

V. Eligibility:

i. An eminent scholar with good track record of high-quality research publications in Peer-reviewed or UGC-listed journals, significant research contribution to the discipline, and engaged in research supervision.

ii. A minimum of ten years of teaching/research experience as Professor or an equivalent grade in a University, College or an institute of national level.

iii. The selection shall be based on academic achievements, favourable review from three eminent subject experts who are not less than the rank of Senior Professor or a Professor of at least ten years experience.

iv. The selection shall be based on ten best publications in the Peer-reviewed or UGC -listed journals and award of Ph.D. degrees to at least two candidates under his/her supervision during the last 10 years and interaction with the Selection Committee constituted as per the UGC Regulations.

29. Music, Performing Arts, Visual Arts and Other Traditional Indian Art Forms like Sculpture, etc.

I. Assistant Professor: Eligibility (A or B): A.

Assistant
Professor:
Eligibility

i. Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/foreign University.

ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be:

Provided further, candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in University/Colleges /Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:

- Ph.D. degree has been awarded to the candidate in a regular mode;
- The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- An open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted;
- candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which, at least one is in a refereed journal;
- The candidate has presented at least two research papers based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars supported/ funded/sponsored by the UGC/AICTE/ICSSR or any other similar agency.

Note 1: The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affair) of the University concerned.

Note 2: The clearance of NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC (like SLET/SET).

OR

B. A traditional or a professional artist with highly commendable professional achievement in the subject concerned having a Bachelor's degree, who has:

- studied under a noted/reputed traditional Master(s)/ Artist(s);
- Has been 'A' grade artist of AIR/Doordarshan;
- Has the ability to explain, with logical reasoning the subject concerned; and
- Has adequate knowledge to teach theory with illustrations in the discipline concerned.

Associate
Professor**II. Associate Professor: Eligibility (A or B):**

- A. i. Good academic record, with a doctoral degree.
 ii. Performing ability of a high professional standard.
 iii. Eight year's experience of teaching in a University or College and / or of research in a University/national level institution, equal to that of Assistant Professor in a University/College.
 iv. Has made a significant contribution to knowledge in the subject concerned, as evidenced by quality publications.

OR

B. A traditional or a professional artist with highly-commendable professional achievement having Master's degree in the subject concerned, who has:

- i. been 'A'-grade artist of AIR/Doordarshan;
 ii. eight years' experience of outstanding performing achievement in the field of specialisation;
 iii. experience in designing of new courses and /or curricula;
 iv. participated in National level Seminars/Conferences/Concerts in reputed institutions, and
 v. ability to explain, with logical reasoning, the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in the said discipline.

Professor
Eligibility**III. Professor: Eligibility (A or B):**

- A. i. An eminent scholar having a doctoral degree.
 ii. Have been actively engaged in research with at least ten years of experience in teaching in University/College and / or research at the University/National level institutions.
 iii. Minimum of 6 research publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals.
 iv. Has a total research score of 120, as per Appendix II.

OR

B. A traditional or a professional artist, with highly-commendable professional achievement, in the subject concerned,

- i. Having Masters degree, in the relevant subject.
 ii. Has been 'A'-grade artist of AIR/Doordarshan.
 iii. Has Ten years of outstanding performing achievements in the field of specialization.
 iv. Has made significant contributions in the field of specializations and ability to guide research.
 v. Has participated in National/International Seminars/Conferences/Workshops/Concerts and/ or recipient of National/International Awards/Fellowships.
 vi. Has the ability to explain with logical reasoning the subject concerned, and
 vii. Has adequate knowledge to teach theory with illustrations in the said discipline.

Drama
Discipline
Assistant
Professor**30. Drama Discipline:****I. Assistant Professor Eligibility (A or B)**

A. (i) Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/foreign University.

(ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009, or 2016, and their amendments from time to time as the case may be:

Provided further, candidates registered for the Ph.D. programme, prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in University/Colleges/Institutions, subject to the fulfillment of the following conditions:-

- (a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode;
- (b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- (c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- (d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal;
- (e) The candidate has presented at least two research papers based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars supported/funded/ sponsored by the UGC/CSIR/ICSSR or any other similar agency.

Note: 1. The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

2. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which the NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.

OR

B. A traditional or a professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who has,-

- (i) been a professional artist with three years' Bachelor degree/Post Graduate Diploma, with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed), from the National School of Drama, or any other such Institution in India or abroad;
- (ii) five years of regular acclaimed performance at regional/ national/ international stage, supported by evidence; and
- (iii) the ability to explain, with logical reasoning, the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in the discipline concerned.

II. Associate Professor:

Associate
Professor

Eligibility (A or B) :

A. (i) A good academic record, having a Ph.D degree with performing ability of high professional standard as certified by an Expert Committee constituted by the University concerned for the said purpose.

(ii) Eight years experience of teaching in a University/College and/ or research in a University/national-level institutions equal to that of Assistant Professor in a University/College.

(iii) A significant contribution to knowledge in the subject concerned, as evidenced by the quality publications.

OR

B. A traditional or a professional artist, having highly commendable professional achievement in the subject concerned, has a Master's degree, who has:

- (i) Been recognised artist of Stage/ Radio/TV;
- (ii) Eight years of outstanding performance in the field of specialisation;
- (iii) Experience of designing new courses and /or curricula;
- (iv) Participated in Seminars/Conferences in reputed institutions; and
- (v) The ability to explain with logical reasoning the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in the said discipline.

Professor
Eligibility

III. Professor Eligibility (A or B):

A. An eminent scholar, having a doctoral degree, actively engaged in research with ten years of experience in teaching and /or research at a University/National-level institution, including experience of guiding research at the doctoral level, with outstanding performing achievement in the field of specialisation, with a minimum of 6 research publications in the peer-reviewed or UGC listed journals, and a total research score of 120, as per Appendix II, Table 2.

OR

B. A traditional and a professional artist, having highly commendable professional achievement in the subject concerned, who has,-

- (i) Master's degree, in the relevant subject;
- (ii) Ten years of outstanding performing achievements in the field of specialisation;
- (iii) Made significant contribution in the field of specialization;
- (iv) Guided research;
- (v) Participated in National/International Seminars/ Conferences/ Workshops and/or recipient of National/ International Awards/ Fellowships;
- (vi) Ability to explain with logical reasoning the subject concerned;
- (vii) Adequate knowledge to teach theory, with illustrations in the said discipline.

Yoga Discipline

31. Yoga Discipline

Assistant
Professor

I. ASSISTANT PROFESSOR: Eligibility (A or B) :

A. Good academic record, with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) at the Master's degree in Yoga or any other relevant subject, or an equivalent degree from an Indian/foreign University.

Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time.

OR

B. A Master's degree in any discipline with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) and a Ph.D. Degree in Yoga* in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be.

***Note:** Considering the paucity of teachers in the newly-emerging field of Yoga, this alternative has been provided and shall be valid only for five years from the date of notification of this Statute.

II. ASSOCIATE PROFESSOR

Associate
Professor

(i) A good academic record, with a Ph.D. degree in the subject concerned or in a relevant discipline.

(ii) A Master's degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed).

(iii) A minimum of eight years' experience of teaching and/or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institutions/Industry with evidence of published work and a minimum of 7 publications as books and / or research/policy papers in peer-reviewed or UGC listed journals and a total research score of at least Seventy five (75), as per the criteria given in Appendix II

III. PROFESSOR Eligibility (A or B) :

Professor
Eligibility

A. (i) An eminent scholar with Ph.D. degree in the subject concerned or in an allied/relevant subject and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work, with a minimum of 10 publications as books and/ or research/policy papers in the peer-reviewed or UGC listed journals and a total research score of at least 120 as per the criteria given in Appendix II, Table 2.

(ii) A minimum of ten years of teaching experience in a University/College and / or experience in research at the university/National level institution/Industries, with evidence of having successfully guided doctoral candidate.

OR

B. An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contribution to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, to be substantiated by credentials.

32. MINIMUM QUALIFICATIONS FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POSTS OF UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN, UNIVERSITY DEPUTY LIBRARIAN AND UNIVERSITY LIBRARIAN

I. UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN

University
Assistant
Librarian

(i) A Master's Degree in Library Science, Information Science or Documentation Science or an equivalent professional degree, with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed)

(ii) A consistently good academic record, with knowledge of computerization of a library.

(iii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be:

Provided that the, candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institution awarding the degree, and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-

(a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode

(b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;

(c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;

(d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;

(e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored /funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.

Note: (i) The fulfillment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

(ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

University
Deputy
Librarian

II. UNIVERSITY DEPUTY LIBRARIAN

(i) A Master's Degree in library science/information science/documentation science, with at least 55% marks or an equivalent grade in a point –scale, wherever grading system is followed.

(ii) Eight years experience as an Assistant University Librarian/College Librarian.

(iii) Evidence of innovative library services including integration of ICT in library.

(iv) A Ph.D. Degree in library science/ Information science / Documentation Science/Archives and manuscript keeping/ computerization of library.

University
Librarian

III. UNIVERSITY LIBRARIAN

(i) A Master's Degree in Library Science/Information Science/Documentation Science with at least 55% marks or an equivalent grade in a point -scale wherever the grading system is followed.

(ii) At least ten years as a Librarian at any level in University Library or ten years of teaching as Assistant/Associate Professor in Library Science or ten years' experience as a College Librarian.

(iii) Evidence of innovative library services, including the integration of ICT in a library.

(iv) A Ph.D. Degree in library science/information science/ documentation /archives and manuscript-keeping.

PART-II**SELECTION COMMITTEE AND SELECTION PROCEDURE****33. CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEES AND GUIDELINES ON SELECTION PROCEDURE:**Selection
Committee and
Selection
Procedure**(1) Selection Committee Composition****I. Assistant Professor in the University:**

(a) The Selection Committee for the post of Assistant Professor in the University shall consist of the following persons:-

(i) The Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Committee.

(ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Chancellor

(iii) Three experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the Executive Council.

(iv) Dean of the Faculty concerned.

(v) Head of the Department concerned.

(vi) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates from any of these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

(b) Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

II. Associate Professor in the University:

(a) The Selection Committee for the post of Associate Professor in the University shall have the following composition:-

(i) The Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Committee.

(ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Chancellor.

(iii) Three experts in the subject/field concerned nominated by the Vice-Chancellor, out of the panel of names approved by the Executive Council.

(iv) Dean of the faculty concerned

(v) Head Department concerned.

(vi) An academician representing SC/ST/OBC/ Minority / Women/Differently-abled categories, if any of candidates belonging to any of these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

(b) At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

III. Professor in the UniversityProfessor in the
University

(a) The Selection Committee for the post of Professor in the University shall consist of the following persons:-

(i) Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Committee.

(ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Chancellor.

(iii) Three experts in the subject/field concerned to be nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Executive Council.

(iv) Dean of the faculty concerned.

(v) Head of the Department concerned.

(vi) An academician belonging to the SC/ST/OBC/ Minority / Women / Differently-abled categories, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

(b) At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

Senior Professor

IV. Senior Professor

a. The Selection Committee for the post of Senior Professor in the University shall consist of the following persons:

i. Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Committee.

ii. An academician not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience who is the nominee of the Chancellor.

iii. Three experts not below the rank of a Senior Professor/Professor with a minimum of ten years' experience in the subject/field concerned nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Executive Council.

iv. Dean (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) of the faculty concerned.

v. Head (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) or Senior-most Professor (not below the rank of Senior Professor/Professor, with a minimum of ten years' experience) of the Department concerned.

vi. An academician (not below the rank of a Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) representing SC/ST/OBC/ Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

b. Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

V. Selection Committees for the posts of Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians shall be the same as that of Professor, Associate Professor and Assistant Professor, respectively, except that in Library practicing, Librarian shall be associated with the Selection Committee as one of the subject experts.

VI. The "Screening-cum-Evaluation Committee" for CAS promotion of Assistant Professors/equivalent cadres in Librarians from one level to the other higher level shall consist of.

University
teachers

A. For University teachers:

i. the Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Committee;

ii. The Dean of the Faculty concerned;

iii. The Head of the Department concerned; and

iv. One subject expert in the subject concerned nominated by the Vice-Chancellor from the University panel of experts.

B. For University Assistant Librarian:University
Assistant
Librarian

- i. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Committee;
- ii. The Dean of the Faculty;
- iii. The Librarian, University Library; and
- iv. One expert who is a working Librarian nominated by the Vice-Chancellor from the University panel of experts.

Note: The quorum for these committees in all categories shall be three which will include one subject expert/university nominee.

(2) The Screening-cum-Evaluation Committee on verification/evaluation of grades secured by the candidate through the Assessment Criteria and Methodology Proforma designed by the university based on this Statute and as per the minimum requirement specified;

(a) In Appendix II, Table 1 for each of the cadre of Assistant Professor; and

(b) In Appendix II, Table 4 for each of the cadre of Librarian;

shall recommend to the Executive Council about the suitability for the promotion of the candidate (s) under CAS for implementation.

(3) The selection process shall be completed on the day/last day of the selection committee meeting, wherein the minutes are recorded and recommendation made on the basis of the performance of the interview are duly signed by all members of the selection committee.

(4) For all Selection Committees specified in these Regulations, Head of Department should be either in the same or higher rank/ position than the rank/position for which the interview is to be held.

34. SELECTION PROCEDURE:Selection
Procedure

I. The overall selection procedure shall incorporate transparent, objective and credible methodology of analysis of the merits and credentials of the applicants based on the weightage given to the performance of the candidate in different relevant parameters and his/her performance on a grading system proforma, based on Appendix II Table 1,2,3 and 4.

In order to make the system more credible, universities may assess the ability for teaching and / or research aptitude through a seminar or lecture in a classroom situation or discussion on the capacity to use the latest technology in teaching and research at the interview stage. These procedures can be followed for both the direct recruitment and the CAS promotions, wherever selection committees are prescribed in this Statute.

II. The universities shall adopt this Statute selection committees and selection procedure through their respective statutory bodies incorporating Appendix II Table 1,2,3 and 4 for University Departments. The universities may devise its own self-assessment-cum-performance appraisal forms for teachers in strict adherence to the Appendix II Table 1,2,3 and 4 specified in this Statute.

III. In all the Selection Committees of direct recruitment of teachers and other academic staff in the university provided herein, an academician belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of candidates belonging to these categories is the applicant and if any of the members of the selection committee does not belong to that category, shall be nominated by the Vice-Chancellor of the University. The academician, so nominated for this purpose, shall be one level above the cadre level of the applicant, and such nominee shall ensure that the norms of the State Government, in relation to the categories mentioned above, are strictly followed during the selection process.

IV. The process of selection of a Professor shall involve the inviting of the application developed by the University, based on the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in this Chapter in Appendix II Table 1 and 2 and reprints of all significant publications of the candidates:

Provided that the publications submitted by the candidate shall have been published during the qualifying period.

Provided further that such publications shall be made available to the subject experts for assessment before holding the interview. The evaluation of the publications by the experts shall be taken into consideration while finalizing the outcome of selection.

V. In the case of selection of faculty members who are from outside the academic field and are considered under Clause 4.1 (III.B), 4.2 (I.B, II.B, III.B), 4.3 (I.B, II.B, III.B) and 4.4 (III.B) of this Chapter, ensuring that only outstanding professionals who can contribute substantially to the university knowledge system are selected.

VI. In the selection process for the posts involving different nature of responsibilities in certain disciplines/areas, such as Music and Fine Arts, Visual Arts and Performing Arts, and Library, greater emphasis may be laid on the nature of deliverables indicated against each of the posts in this Chapter which need to be taken up by the University while developing the Proforma for both the direct recruitment and the CAS promotion.

VII. The Internal Quality Assurance Cell (IQAC) shall be established in all Universities as per the UGC/ National Assessment Accreditation Council (NAAC) guidelines with the Vice-Chancellor, as Chairperson. The IQAC shall act as the documentation and record-keeping Cell for the University, including assistance in the development of Assessment Criteria and Methodology Proforma based on this Chapter. The IQAC may also introduce, wherever feasible, the student feedback system as per the NAAC guidelines on institutional parameters without incorporating the component of the students' assessment of individual teachers in the Assessment Criteria and Methodology Proforma.

A. The Assessment of the performance of the University teachers for the CAS promotion is based on the following criteria:

i. **Teaching-Learning and Evaluation:** The commitment to teaching based on observable indicators such as being regular to class, punctuality to class, remedial teaching and clarifying doubts within and outside the class hours, counselling and mentoring, additional teaching to support the college/university as and when the need arises, etc. Examination and evaluation activities like performing of examination supervision duties, question-papers setting for university/college examinations, participation in the evaluation of examination answer scripts, conducting examinations for internal assessment as per the schedule to be announced by the university.

ii. **Personal Development Related to Teaching and Research Activities:** Attending orientation/refresher/methodology courses, development of e-contents and MOOC's, organising seminar/ conference/ workshop / presentation of papers and chairing of sessions/guiding and carrying out research projects and publishing the research output in national and international journals etc.

iii. **Administrative Support and Participation in Students' Co-curricular and Extra-curricular Activities.**

B. Assessment Process-

The following three-step process is recommended for carrying out assessment for promotion under the CAS at all levels:

Step 1: The university teachers shall submit to university an annual self-appraisal report in the prescribed Proforma to be designed based on **Tables 1 to 4 of Appendix II**. The report should be submitted at the end of every academic year, within the stipulated time. The teacher will provide documentary evidence for the claims made in the annual self-appraisal report, which is to be verified by the HOD. The submission should be through the Head of the Department (HOD).

Step 2: After completion of the required years of experience for promotion under CAS and fulfilment of other requirements indicated below, the teacher shall submit an application for promotion under CAS.

Step 3: A CAS Promotion shall be granted as mentioned in Clauses 6.4 of this Chapter.

(1) Assessment Criteria and Methodology:

Assessment
Criteria and
Methodology

(a) **Tables 1 to 3 of Appendix II** are applicable to the selection of Assistant Professors/ Associate Professors/ Professors/Senior Professor in University; and

(b) **Table 4 of Appendix II** is applicable to Assistant Librarians and Deputy Librarians for promotion under Career Advancement Scheme.

(2) The constitution of the Selection Committees and Selection Procedure as well as the Assessment Criteria and Methodology for the above cadres, either through direct recruitment or through Career Advancement Scheme, shall be in accordance with this Chapter.

(3) The criteria for promotions under Career Advancement Scheme laid down under this Chapter shall be effective as per UGC Regulations, 2018 published in UGC *Gazette* notification dated 18.07.2018. However, to avoid hardship to those faculty members who have already qualified or are likely to qualify shortly, a choice may be given to them, for being considered for , this option can be exercised only within three years from the date of notification of UGC Regulations, 2018 published in UGC *Gazette* notification dated 18.07.2018.

I. A teacher who wishes to be considered for promotion under the CAS may submit in writing to the university, within three months in advance of the due date, that he/she fulfils all the requirements under the CAS and submit to the university the Assessment Criteria and Methodology Proforma as evolved by the university supported by all credentials as per the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in this Ordinance. In order to avoid any delay in holding the Selection Committee meetings for various positions under the CAS, the University may initiate the process of screening/selection, and complete the process within six months from the receipt of application. Further, in order to avoid any hardship, the candidates who fulfill all other criteria mentioned in this Chapter, as on and till the date on which this Chapter is notified, can be considered for promotion from the date, on or after the date, on which they fulfill these eligibility conditions.

II. The Selection Committee specifications as contained in Clauses 4.1 to 4.4 shall be applicable to all direct recruitments of faculty positions and equivalent cadres and Career Advancement promotions from Assistant Professor to Associate Professor, from Associate Professor to Professor, Professor to Senior Professor (in University) and for equivalent cadres.

III. The CAS promotion from a lower stage to a higher stage of Assistant Professor shall be conducted through a "Screening-cum-Evaluation Committee", following the criteria laid down in **Table1 of Appendix II**.

IV. The promotion under the CAS being a personal promotion to a teacher holding a substantive sanctioned post, on his/her superannuation, the said post shall revert back to its original cadre.

V. For the promotion under the CAS, the applicant teacher must be on the role and in active service of the University on the date of consideration by the Selection Committee.

VI. The candidate shall offer himself/herself for assessment for promotion, if he/she fulfils the minimum grading specified in the relevant Assessment Criteria and Methodology Tables, by submitting an application and the required Assessment Criteria and Methodology Proforma. He/she can do so three months before the due date. The university shall send a general circular twice a year, inviting applications for the CAS promotions from the eligible candidates.

(i) If a candidate applies for promotion on completion of the minimum eligibility period and is successful, the date of promotion shall be from that of minimum period of eligibility.

(ii) If, however, the candidate finds that he/she would fulfils the CAS promotion criteria, as defined in **Tables 1, 2 and 4 of Appendix II** at a later date and applies on that date and is successful, his/her promotion shall be effected from that date of the candidate fulfilling the eligibility criteria.

(iii) The candidate who does not succeed in the first assessment, he/she shall have to be re-assessed only after one year. When such a candidate succeeds in the eventual assessment, his/her promotion shall be deemed to be one year from the date of rejection.

VII. Regarding the cases pending for promotions from one Academic Level/Grade Pay to another Academic Level/Grade Pay under the Career Advancement Scheme provided on the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education 2010 and its subsequent amendments, the teachers shall be given the option to be considered for the promotion from one Academic Level/Grade Pay to another Academic Level/Grade Pay as per the following:-

(a) The teachers shall be considered for promotion from one Academic Level/Grade Pay to another as per the CAS under this Chapter.

OR

(b) The faculty members shall be considered for the promotion from one Academic Level/Grade Pay to another as per the CAS provided based on the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in University and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education 2010 and its amendments with relaxation in the requirements of Academic Performance Indicators (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) upto the date of notification of this Chapter.

TABLE-A
(Minimum API requirement for the promotion of teachers under CAS in university departments)

S.No.		Assistant Professor (Stage 1/ AGP Rs.6000/- to Stage 2/AGP Rs.7000/-)	Assistant Professor (Stage 2/ AGP Rs.7000/- to Stage 3/AGP Rs.8000/-)	Assistant Professor (Stage 3/ AGP Rs.8000/-) to Associate Professor (Stage 4/AGP Rs.9000/-)	Associate Professor (Stage 4/ AGP Rs.9000/- to Professor (Stage 5/AGP Rs.10000/-)
1	Research and Academic contribution (Category III)	40/assessment period	100/ assessment period	90/assessment period	120/ assessment period
2	Expert assessment system	Screening Committee	Screening Committee	Selection Committee	Selection Committee

Table-B
(Minimum API requirement for the promotion of Library staff under CAS in Universities)

S.N		Assistant Librarian (Stage 1/ AGP Rs.6000/- to Stage 2/AGP Rs.7000/-)	Assistant Librarian (Stage 2/ AGP Rs.7000/- to Stage 3/AGP Rs.8000/-)	Assistant Librarian (Selection Grade/ Deputy Librarian) (Stage 3/ AGP Rs.8000/-) to Deputy Librarian (Stage 4/AGP Rs.9000/-)	Deputy Librarian (Stage 4/AGP Rs.9000/-) to Deputy Librarian (Stage 5 AGP Rs.10,000/-)
1	Research and Academic contribution (Category III)	40/ assessment period	100/ assessment period	90/assessment period	120 per assessment period
2	Expert assessment system	Screening Committee	Screening Committee	Selection Committee	Selection Committee

VIII. The requirement for Orientation course and Refresher course for promotions due under the CAS shall not be mandatory upto 31st December, 2018.

PART III

35. STAGES OF PROMOTION UNDER THE CAREER ADVANCEMENT SCHEME OF INCUMBENT AND NEWLY-APPOINTED ASSISTANT PROFESSORS/ ASSOCIATE PROFESSORS/ PROFESSORS

A. The entry-level Assistant Professors (Level 10) shall be eligible for promotion under the Career Advancement Scheme (CAS) through two successive levels (Level 11 and Level 12), provided they are assessed to fulfill the eligibility and performance criteria as laid down in Clause 6.3 of this Chapter.

B. Career Advancement Scheme (CAS) for University teachers-

I. Assistant Professor (Academic Level 10) to Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11)

C. Eligibility:

(i) An Assistant Professor who has completed four years of service with a Ph.D. degree or five years of service with a M.Phil. / PG Degree in Professional Courses, such as LLM, M.Tech, M.V.Sc. and M.D., or six years of service in case of those without a Ph.D./M.Phil./ PG Degree in a Professional course and satisfies the following conditions;

(ii) Attended one Orientation course of 21 days duration on teaching methodology;

(iii) Any one of the following: Completed Refresher/ Research Methodology Course/ Workshop/ Syllabus Up-gradation Workshop/ Training Teaching-Learning-Evaluation, Technology Programmes/ Faculty Development Programmes of at least one week (5 days) duration, or taken one MOOCs course (with e-certification) or development of e-contents in four-quadrants / MOOC's course during the assessment period; and

(iv) Published one research publication in the peer-reviewed journals or UGC-listed journals during assessment period.

D. CAS Promotion Criteria:

A teacher shall be promoted if,-

(i) He/she gets a 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least three/four/five of the last four/five/six years of the assessment period as the case may be (as provided in Appendix II, Table 1), and;

(ii) The promotion is recommended by the screening-cum evaluation committee.

II. Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11) to Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12)

Eligibility:

(i) Assistant Professors who has completed five years of service in Academic Level 11/Senior Scale;

(ii) A Ph.D. Degree in the subject relevant/allied/relevant discipline;

Promotion
Under CAS

Eligibility

CAS Promotion
Criteria

Eligibility

(iii) Has done any two of the following in the last five years of Academic Level 11/Senior Scale: Completed a course / programme from amongst the categories of Refresher Courses/Research Methodology/ Workshops/ Syllabus Up-gradation Workshop/ Teaching-Learning-Evaluation/ Technology Programmes / Faculty Development Programme of at least two weeks (ten days) duration (or completed two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration), or, completed one MOOCs course in the relevant subject (with e-certification); or contribution towards the development of e-content in 4-quadrant (at least one quadrant) minimum of 10 modules of a course/contribution towards the development of at least 10 modules of MOOCs course/ contribution towards conduct of a MOOCs course during the period of assessment;

(iv) Published three research papers in the peer-reviewed journals or UGC-listed journals during assessment period.

E. CAS Promotion Criteria:

CAS Promotion
Criteria

A teacher shall be promoted if;

(i) The teacher gets a 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least four of the last five years of the assessment period, (as prescribed in Appendix II, Table 1) and;

(ii) The promotion is recommended by the Screening-cum-evaluation committee.

III. Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12) to Associate Professor (Academic Level 13A)

Eligibility Criteria:

Eligibility Criteria

(i) Assistant Professor who has completed three years of service in Academic Level 12/ Selection grade;

(ii) A Ph.D Degree in the subject concerned/allied/relevant discipline;

(iii) Any one of the following during last three years: completed one course / programme from amongst the categories of Refresher Courses/ Research Methodology Workshops/Syllabus Up-gradation Workshop/ Teaching-Learning-Evaluation Technology Programme/ Faculty Development Programme of at least two weeks (ten days) duration (or completed two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration); or completed one MOOCs course (with e-certification); or contribution towards the development of e-content in 4-quadrant (at least one quadrant) minimum of 10 modules of a course/contribution towards development of at least 10 modules of MOOCs course/ contribution towards conduct of a MOOCs course during the period of assessment;

(iv) A minimum of seven publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals out of which three research papers should have been published during the assessment period;

(v) Evidence of having guided at least one Ph.D. candidate.

CAS Promotion
Criteria

F. CAS Promotion Criteria:

A teacher shall be promoted if;

(i) He/she gets a 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least two of the last three years of the assessment period as specified in Appendix II, Table 1, and has a research score of at least 70 as per Appendix II, Table 2;

(ii) The promotion is recommended by a selection committee constituted in accordance with this Chapter.

IV. Associate Professor (Academic Level 13A) to Professor (Academic Level 14)

Eligibility:

(i) An Associate Professor who has completed three years of service in Academic Level 13 A;

(ii) A Ph.D degree in the subject concerned/allied/relevant discipline;

(iii) A minimum of ten research publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals out of which three research papers should have been published during the assessment period;

(iv) Evidence of having successfully guided doctoral candidate. A minimum of 110 Research Score as per Appendix II, Table 2.

CAS Promotion
Criteria

G. CAS Promotion Criteria:

A teacher shall be promoted if;

(i) He/she gets 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least two of the last three years of the assessment period, as per Appendix II, Table 1, and at least 110 research score, as per Appendix II, Table 2.

(ii) The promotion is recommended by a selection committee constituted in accordance with this Chapter.

V. Professor (Academic Level 14) to Senior Professor (Academic Level 15)

A Professor can be promoted to the post of Senior Professor under the CAS. The promotion shall be based on academic achievement, favourable review from three eminent subject -experts who are not of the rank lower than the rank of a Senior Professor or a Professor having at least ten years' of experience. The selection shall be based on 10 best publications during the last 10 years and interaction with a Selection Committee constituted in accordance with this Chapter.

Eligibility:

(i) Ten years' experience as a Professor;

(ii) A minimum of ten publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and Ph.D. degree has been successfully awarded to two candidates under his/her supervision during the assessment period.

H. Career Advancement Scheme (CAS) for Librarians

Note:

(i) The following provisions apply only to those persons who are not involved in the teaching of Library Science. Teachers in institutions where Library Science is a teaching department shall be covered by the provisions given under sections 6.4 (B), of this Chapter for Universities, respectively;

(ii) The Deputy Librarian in Universities shall have two levels i.e. Academic Level 13A and Academic Level 14.

I. From University Assistant Librarian (Academic level 10) to University Assistant Librarian (Senior Scale/Academic level 11):

Eligibility:

An Assistant Librarian who is in Academic Level 10 and has completed four years of service having a Ph.D. degree in Library Science/ Information Science/ Documentation Science or an equivalent degree or five years' of experience, having at least a M.Phil.degree, or six years of service for those without a M.Phil. or a Ph.D. degree.

(i) He/she has attended at least one Orientation course of 21 days' duration; and

(ii) Training, Seminar or Workshop on automation and digitalisation, maintenance and related activities, of at least 5 days, as per **Appendix II, Table 4.**

I. CAS Promotion Criteria:

CAS Promotion
Criteria

An Assistant Librarian may be promoted if:

(i) He/she gets a 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least three/four/five out of the last four/five/six years of the assessment period as the case may be as specified in Appendix II, Table 4; and

(ii) The promotion is recommended by a screening-cum-evaluation committee.

II. From University Assistant Librarian (Senior Scale/Academic level 11) to University Assistant Librarian (Selection Grade/ Academic level 12)**Eligibility:**

1. He/she has completed five years of service in that grade.

2. He/she has done any two of the following in the last five years :-

(i) Training/Seminar/Workshop/Course on automation and digitalisation;

(ii) Maintenance and other activities as per Appendix II, Table 4 of at least two weeks (ten days) duration (or completed two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration);

(iii) Taken/developed one MOOCs course in the relevant subject (with e-certification); or

(iv) Library up-gradation course.

J. CAS Promotion Criteria:

CAS Promotion
Criteria

An individual shall be promoted if:

(i) He/she gets a 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least four out of the last five years of the assessment period, as specified in Appendix II, Table 4; and

(ii) The promotion is recommended by a screening-cum-evaluation committee.

III. From University Assistant Librarian (Selection Grade/Academic level 12) to University Deputy Librarian (Academic Level 13A):**Eligibility:**

1. He/she has completed three years of service in that grade.

2. He/she has done any one of the following in the last three years:-

(i) Training/Seminar/Workshop/Course on automation and digitalization;

(ii) Maintenance and related activities as per Appendix II, Table 4 of at least two weeks' (ten days) duration;

(iii) Completed two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration;

(iv) Taken/developed one MOOCs course in the relevant subject (with e-certification); and

CAS Promotion
Criteria

(v) Library up-gradation course.

K. CAS Promotion Criteria:

An individual shall be promoted if:

(i) He/she gets a 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least two out of the last three years of the assessment period, as specified in Appendix II, Table 4; and

(ii) The promotion is recommended by a Selection Committee constituted as per these Regulations on the basis of the interview performance.

IV. The criteria for CAS Promotions from University Deputy Librarian (Academic Level 13A) to University Deputy Librarian (Academic Level 14) shall be the following:

Eligibility:

(1) He/she has completed three years of service in that grade.

(2) He/she has done any one of the following in the last three years:-

(i) Training/Seminar/Workshop/Course on automation and digitalization;

(ii) Maintenance and related activities as per Appendix II, Table 4 of at least two weeks' (ten days) duration;

(iii) Completed two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration;

(iv) Taken/developed one MOOCs course in the relevant subject (with e-certification); and

(v) Library up-gradation course.

(3) Evidence of innovative library services, including the integration of ICT in a library.

(4) A Ph.D. Degree in Library Science/Information Science/Documentation /archives and Manuscript-Keeping.

L. CAS Promotion Criteria:

An individual shall be promoted if:

(i) He/she gets a 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least two out of the last three years of the assessment period, as specified in Appendix II, Table 4; and

(ii) The promotion is recommended by a Selection Committee constituted as per this Chapter on the basis of the interview performance.

(5) Discretionary award of advance increments for those who enter the profession as Associate Professor or Professor with higher merit, high number of research publications of high quality and experience at the appropriate level, shall be within the competence of the appropriate authority of the University concerned or recruiting institution based on the recommendations of a selection committee while considering the case of individual candidates in the context of the merits of each case, taking into account the pay structure of other teachers in the faculty and other merit-specific factors. Discretionary award of advance increments is not applicable to those entering the profession as Assistant Professor/Assistant Librarian and to those who are entitled for grant of advance increments for having acquired a Ph.D., M.Phil.. However, those entering the service as Assistant Professor/Assistant Librarian having a post-doctoral teaching/research experience, after obtaining a Ph.D. degree and proven credentials, may be eligible for discretionary award of advanced increments to be given to the person, as decided and recorded by the Selection Committee in the minutes of its meeting.

(6) Counting of Past Services for Direct Recruitment and Promotion under CAS.

CAS Promotion
Criteria

Previous regular service, whether national or international, as Assistant Professor, Associate Professor or Professor or equivalent in a University, College, National Laboratories or other scientific/professional organisations such as the CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR, ICMR and DBT, should count for the direct recruitment and promotion under the CAS of a teacher as Assistant Professor, Associate Professor, Professor or any other nomenclature, provided that:

(a) The essential qualifications of the post held were not lower than the qualifications prescribed by the UGC for Assistant Professor, Associate Professor and Professor, as the case may be.

(b) The post is/was in an equivalent grade or of the pre-revised scale of pay as the post of Assistant Professor (Lecturer) Associate Professor (Reader) and Professor.

(c) The concerned Assistant Professor, Associate Professor and Professor should possess the same minimum qualifications as prescribed by the UGC for appointment to the post of Assistant Professor, Associate Professor and Professor, as the case may be.

(d) The post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down in the Regulations of the University/State Government/Central Government/ Institutions concerned, for such appointments.

(e) the previous appointment was not as guest lecturer for any duration.

(f) The previous *Ad-hoc* or Temporary or contractual service (by whatever nomenclature it may be called) shall be counted for direct recruitment and for promotion, provided that,-

(i) the essential qualifications of the post held were not lower than the qualifications prescribed by the UGC for Assistant Professor, Associate Professor and Professor, as the case may be;

(ii) the incumbent was appointed on the recommendation of a duly constituted Selection Committee/Selection Committee constituted as per the rules of the respective university;

(iii) the incumbent was drawing total gross emoluments not less than the monthly gross salary of a regularly appointed Assistant Professor, Associate Professor and Professor, as the case may be; and

(g) No distinctions shall be made with reference to the nature of management of the institution where previous service was rendered (private/local body/Government), while counting the past service under this clause.

36. (1) Period of Probation and Confirmation

Period of
Probation and
Confirmation

(a) The minimum period of probation of a teacher shall be one year, extendable by a maximum period of one more year in case of unsatisfactory performance.

(b) The teacher on probation shall be confirmed at the end of one year, unless extended by another year through a specific order, before expiry of the first year.

(c) Subject to Clause 11 of this Chapter, it is obligatory on the part of the university/the concerned institution to issue an order of confirmation to the incumbents within 45 days of completion of the probation period after following the due process of verification of satisfactory performance.

(d) The probation and confirmation rules shall be applicable only at the initial stage of recruitment, issued from time to time, by the University.

(e) All other State Government rules on probation and confirmation shall be applicable *mutatis mutandis*.

(2) Creation and Filling-up of teaching Posts-

(a) Teaching posts in university, as far as feasible, may be created in a pyramidal order, for instance, for one post of Professor, there shall be two posts of Associate Professors and four posts of Assistant Professor, per department.

(b) All the sanctioned/approved posts in the university system shall be filled up on an urgent basis.

Appointments
on Contract
Basis

37. Appointments on Contract Basis

The teachers should be appointed on contract basis only when it is absolutely necessary and when the student-teacher ratio does not satisfy the laid-down norms. In any case, the number of such appointments should not exceed 10% of the total number of faculty positions in a College/University. The qualifications and selection procedure for appointing them should be the same as those applicable to a regularly-appointed teacher. The fixed emoluments paid to such contract teachers should not be less than the monthly gross salary of a regularly-appointed Assistant Professor. Such appointments should not be made initially for more than one academic session, and the performance of any such entrant teacher should be reviewed for academic performance before reappointing him/her on contract basis for another session. Such appointments on contract basis may also be resorted to when absolutely necessary to fill vacancies arising due to maternity leave, child-care leave, etc.

PART IV

Selection of
Vice-Chancellor

38. SELECTION OF VICE - CHANCELLOR OF THE UNIVERSITY

(i) A person possessing the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment is to be appointed as Vice-Chancellor. The person to be appointed as a Vice-Chancellor should be a distinguished academician, with a minimum of ten years' of experience as Professor in a University or ten years' of experience in a reputed research and / or academic administrative organisation with proof of having demonstrated academic leadership;

(ii) The selection for the post of Vice-Chancellor should be through proper identification by a Panel of 3-5 persons by a Search-cum-Selection-Committee, through a public notification or nomination or a talent search process or a combination thereof. The members of such Search-cum-Selection Committee shall be persons' of eminence in the sphere of higher education and shall not be connected in any manner with the University concerned or its colleges. While preparing the panel, the Search cum-Selection Committee shall give proper weightage to the academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance, to be given in writing along with the panel to be submitted to the Chancellor. One member of the Search cum-Selection Committee shall be nominated by the Chairman, University Grants Commission, for selection of Vice Chancellor;

(iii) The Chancellor shall appoint the Vice Chancellor out of the Panel of names recommended by the Search-cum-Selection Committee;

(iv) The term of office of the Vice-Chancellor shall form part of the service period of the incumbent making him/her eligible for all service related benefits.

PART V**39. Teaching Days**

Teaching Days

(1) The Universities must have at least 180 teaching, *i.e.*, there should be a minimum of 30 weeks of actual teaching in a 6-day week. Of the remaining period, 12 weeks may be devoted to admission and examination activities, and non-instructional days for co-curricular, sports, college day, *etc.*, 8 weeks for vacations and 2 weeks may be attributed to various public holidays. If the University adopts a 5 day week pattern, then the number of weeks should be increased correspondingly to ensure the equivalent of 30 weeks of actual teaching, with a 6-day week.

The above provision is summarised as follows:-

	Number of weeks : 6-days a week pattern		Number of weeks : 5-days a week pattern	
Categorisation	University	College	University	College
Teaching and Learning Process	30 (180 days) weeks	30 (180 days)weeks	36 (180 days) weeks	36 (180 days) weeks
Admissions, Examinations, and preparation for Examination	12	10	8	8
Vacations	8	10	6	6
Public Holidays (to increase and adjust teaching days accordingly)	2	2	2	2
Total	52	52	52	52

(2) In-lieu of the curtailment of vacation by 2 weeks, the university teachers may be credited with 1/3rd of the period of their earned leave. However, colleges may have an option of a total vacation of 10 weeks in a year and no earned leave except when required to work during the vacations for which, as in the case of University teachers, 1/3rd of the period shall be credited as Earned Leave.

40. (1) Workload

Workload

(a) The workload of the teachers in full employment should not be less than Forty hours a week for Thirty working weeks (One Hundred and Eighty teaching days) in an academic year. It should be necessary for the teacher to be available for at least Five hours daily in the University. Teachers shall devote at least Two hours per day for mentoring of students (minimum Fifteen students per coordinator) for Community Development/Extra-Curricular Activities/library consultation/research in case of Under-Graduate Courses and/or at least Two hours per day for research in case of Post-Graduate courses, for which the necessary space and infrastructure shall be

provided by the University. The direct teaching-learning work load should be as follows:-

Assistant Professor	-	16 hours per week
Associate Professor/Professor	-	14 hours per week

(b) Professors/ Associate Professors/ Assistant Professors involved in administration/ extension work can devote two hours per week from the teaching and learning hours.

(2) Service Agreement and Fixing of Seniority

(a) At the time of recruitment in University, a service agreement should be executed between the University and the teacher concerned and a copy thereof shall be deposited with the Registrar. Such service agreement shall be duly stamped as per the Government rates applicable.

(b) The self-appraisal methodology, as per Clause 6.0 and its sub-clauses and Clauses 6.1 to 6.4 and all the sub-clauses contained therein and as per **Tables 1 to 4 of Appendix II**, as per eligibility, shall form part of the service agreement.

(3) Inter-se seniority between the direct recruited and teachers promoted under CAS,—

The inter-se seniority of a direct recruit shall be determined with reference to the date of joining and for the teachers promoted under the CAS with reference to the date of eligibility as indicated in the recommendations of the selection committee of the respective candidates. The rules and regulations of the respective Central/State Government shall apply, for all other matters of seniority.

PART VI

Code of Professional Ethics

Code of
Professional
Ethics

41. Teachers and their Responsibilities:

Whoever adopts teaching as a profession assumes the obligation to conduct himself / herself in accordance with the ideal of the profession. A teacher is constantly under the scrutiny of his students and the society at large. Therefore, every teacher should see that there is no incompatibility between his precepts and practice. The national ideals of education which have already been set forth and which he/she should seek to inculcate among students must be his/her own ideals. The profession further requires that the teacher should be calm, patient and communicative by temperament and amiable in disposition.

Teacher should:

- (i) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community;
- (ii) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;
- (iii) Seek to make professional growth continuous through study and research;
- (iv) Express free and frank opinion by participation at professional meetings, seminars, conferences *etc.*, towards the contribution of knowledge;
- (v) Maintain active membership of professional organisations and strive to improve education and profession through them;
- (vi) Perform their duties in the form of teaching, tutorials, practicals, seminars and research work, conscientiously and with dedication;

(vii) Discourage and not indulge in plagiarism and other non ethicalbehaviour in teaching and research;

(viii) Abide by the Act, Statute and Ordinance of the University and to respect its ideals, vision, mission, cultural practices and tradition;

(ix) Co-operate and assist in carrying out the functions relating to the educational responsibilities of the college and the university, such as: assisting in appraising applications for admission, advising and counselling students as well as assisting the conduct of university and college examinations, including supervision, invigilation and evaluation; and

(x) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the community service.

II. Teachers and Students

Teachers and
Students

Teachers should:

(i) Respect the rights and dignity of the student in expressing his/her opinion;

(ii) Deal justly and impartially with students regardless of their religion, caste, gender, political, economic, social and physical characteristics;

(iii) Recognise the difference in aptitude and capabilities among students and strive to meet their individual needs;

(iv) Encourage students to improve their attainments, develop their personalities and at the same time contribute to community welfare;

(v) Inculcate among students scientific temper, spirit of inquiry and ideals of democracy, patriotism, social justice, environmental protection and peace;

(vi) treat the students with dignity and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason;

(vii) Pay attention to only the attainment of the student in the assessment of merit;

(viii) Make themselves available to the students even beyond their class hours and help and guide students without any remuneration or reward;

(ix) Aid students to develop an understanding of our national heritage and national goals; and

(x) Refrain from inciting students against other students, colleagues or administration.

III. Teachers and Colleagues Teachers should:

Teachers and
Colleagues
Teachers should

(i) Treat other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be treated;

(ii) Speak respectfully of other teachers and render assistance for professional betterment;

(iii) Refrain from making unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities; and

(iv) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race or sex in their professional endeavour.

Teachers and
Authorities

IV. Teachers and Authorities:

Teachers should:

- (i) Discharge their professional responsibilities according to the existing rules and adhere to procedures and methods consistent with their profession in initiating steps through their own institutional bodies and / or professional organisations for change of any such rule detrimental to the professional interest;
- (ii) Refrain from undertaking any other employment and commitment, including private tuitions and coaching classes which are likely to interfere with their professional responsibilities;
- (iii) Co-operate in the formulation of policies of the institution by accepting various offices and discharge responsibilities which such offices may demand;
- (iv) Co-operate through their organisations in the formulation of policies of the other institutions and accept offices;
- (v) Co-operate with the authorities for the betterment of the institutions keeping in view the interest and in conformity with the dignity of the profession;
- (vi) Adhere to the terms of contract;
- (vii) Give and expect due notice before a change of position takes place; and
- (viii) Refrain from availing themselves of leave except on unavoidable grounds and as far as practicable with prior intimation, keeping in view their particular responsibility for completion of academic schedule.

Teachers and
Non-
Teaching Staff

V. Teachers and Non-Teaching Staff:

Teachers should:

- (i) Treat the non-teaching staff as colleagues and equal partners in a cooperative undertaking, within every educational institution;
- (ii) Help in the functioning of joint-staff councils covering both the teachers and the non-teaching staff.

Teachers and
Guardians

VI. Teachers and Guardians:

Teachers should:

Try to see through teachers' bodies and organisations, that institutions maintain contact with the guardians, their students, send reports of their performance to the guardians whenever necessary and meet the guardians in meetings convened for the purpose for mutual exchange of ideas and for the benefit of the institution.

Teachers and
Society

VII. Teachers and Society:

Teachers should:

- (i) Recognize that education is a public service and strive to keep the public informed of the educational programmes which are being provided;
- (ii) Work to improve education in the community and strengthen the community's moral and intellectual life ;
- (iii) Be aware of social problems and take part in such activities as would be conducive to the progress of society and hence the country as a whole;
- (iv) Perform the duties of citizenship, participate in community activities and shoulder responsibilities of public offices;
- (v) Refrain from taking part in or subscribing to or assisting in any way activities, which tend to promote feeling of hatred or enmity among different communities, religions or linguistic groups but actively work for national integration.

VIII . The Vice-Chancellor:The Vice-
Chancellor**The Vice-Chancellor should:**

- (i) Provide inspirational and motivational value-based academic and executive leadership to the university through policy formation, operational management, optimization of human resources and concern for environment and sustainability;
- (ii) Conduct himself/herself with transparency, fairness, honesty, highest degree of ethics and decision making that is in the best interest of the university;
- (iii) Act as steward of the university's assets in managing the resources responsibly, optimally, effectively and efficiently for providing a conducive working and learning environment;
- (iv) Promote the collaborative, shared and consultative work culture in the university, paving way for innovative thinking and ideas;
- (v) Endeavour to promote a work culture and ethics that brings about quality, professionalism, satisfaction and service to the nation and society;
- (vi) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

IX. Librarian should:

Librarian

- (a) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community;
- (b) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;
- (c) Discourage and not indulge in plagiarism and other non ethical behaviour in teaching and research;
- (d) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the community service;
- (e) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

42. Maintenance of Standards in Higher-Education Institutions:

In order to maintain the academic standards in higher education, the following recommendations shall be adopted by the respective Universities/Colleges/Institutions:

- (i) The process of evaluation for Ph.D shall be uniform in all the universities in accordance with the respective UGC Regulations and their amendments from time to time, in this regard. The Universities shall adopt these Regulations within six months of their notification;
- (ii) There shall be special provision of supernumerary Ph.D seats not exceeding 10% of the total seats available in the department, if there is no vacant seat available with the eligible Supervisors in that department, to the in-service teachers for encouraging the faculty members of colleges and universities for getting a Ph.D. degree;
- (iii) In order to encourage research and increase country's research output, Universities shall accord permission and provide need-based facility for college teachers to supervise Ph.D./M.Phil. scholars. Universities shall amend their Statutes and Ordinances accordingly;
- (iv) All newly-recruited faculty members shall be provided one-time seed money/start up grant/research grant for establishing a basic research/computational facility as per the provisions laid down in these regulations.

(v) The Ph.D. degree shall be made a mandatory requirement for recruitment and promotions in accordance with the provisions laid down in these Regulations.

(vi) Research clusters shall be created amongst the universities/colleges/research institutions within the State for sharing research facilities, human resources, skills and infrastructure to ensure optimal utilisation of resources and to create synergies among higher education institutions.

(vii) An induction programme of one month shall be introduced for all newly-recruited Assistant Professors in the universities /colleges/institutions ideally before the starting of their teaching work, but definitely within one year of the recruitment of the new faculty member. In addition to the Human Resource Development Centres of the UGC, Universities/Institutions with the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNTT) scheme shall also organize such induction programmes as per their mandate.

(viii) These induction programmes shall be treated at par with the Orientation Programmes already being run by the Human Resource Development Centres of the UGC for the purpose of the CAS requirements. University shall send the faculty members to such programmes in a phased manner so that the teaching work does not suffer.

All short-term and long-duration capacity-building programmes for teachers/faculty ranging from one week to one month as well as seminars, workshops in different pedagogic and discipline-specific areas being conducted by centres such as Schools of Education (SoEs), Teaching Learning Centres (TLCs), Faculty Development Centres (FDCs), Centres for Academic Leadership and Education Management (CALEMs) under the PMMMNTT scheme shall be taken into consideration for fulfilment of the requirements as laid down in Career Advancement Scheme of these Regulations.

Other Terms and
Conditions

PART VII

43. Other Terms and Conditions

(1) Incentives for Ph.D./M.Phil. and other Higher Qualification

(i) Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment as Assistant Professor to persons possessing the degrees of Ph.D. awarded in a relevant discipline by the University following the process of admission, registration, course work and external evaluation as prescribed by the UGC.

(ii) M.Phil degree holders at the time of recruitment to the post of Assistant Professor shall be entitled to two non-compounded advance increments.

(iii) a. Teachers who complete their Ph.D. degree while in service shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the discipline of employment and has been awarded by a University complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course work, evaluation, *etc.*

b. However, teachers in service who have already been awarded Ph.D. by the time of coming into force of these Regulations or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awarded, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only, even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission.

(iv) In respect of every other case, a teacher who is already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both, as the case may be.

(v) Teachers in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. , while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process including that of enrolment as prescribed by the UGC.

(vi) Teachers who acquire M.Phil. Degree, while in service, shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.

(vii) Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Librarian / who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Library Science.

(viii) (a) Assistant Librarian acquiring the degree of Ph.D. at any time while in service, in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments fixed at increment applicable at entry level only.

(b) However, persons in posts of Assistant Librarian on higher positions who have already been awarded Ph.D. in library science at the time of coming into force of these Regulations or having already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only.

(ix) In respect of every other case of persons in the post of Assistant Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both as the case may be.

(x) Assistant Librarian and others in higher library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.

(xi) Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian with M.Phil. degree in Library Science at the entry level. Assistant Librarian and those in higher positions acquiring M.Phil degree in library science at any time during the course of their service shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.

(xii) Notwithstanding anything in the forgoing clauses, those who have already availed the benefit of advance increments for possessing Ph.D./M.Phil at the entry level or in service once either under this regulation or under the earlier schemes/regulations shall not be entitled to the benefit of advance increments under this Chapter.

(xiii) Teachers, library who have already availed the benefits of increments as per the then existing policy for acquiring Ph.D./M.Phil. while in service shall not be entitled to advance increments under these regulations this Chapter.

(xiv) For posts at the entry level where no such advance increments were admissible for possessing Ph.D./M.Phil. under the earlier schemes/regulations, the benefit of advance of increments for possessing Ph.D./M.Phil shall be available to only those appointments which have been made on or after the coming into force of this Chapter.

Promotion,
Allowance and
Benefits

PART VIII

44. Promotion

When an individual gets a promotion, his new pay on promotion would be fixed in the Pay Matrix as follows:-

On promotion, the teacher or equivalent position would be given a notional increment in his/her existing Academic Level of Pay, by moving him/her to the next higher Cell at that Level; and the pay shown in this Cell would now be located in the new Academic Level corresponding to the post to which he/she has been promoted. If a Cell identical with that pay is available in the new Level, that Cell shall be the new pay, otherwise the next higher Cell in that Level shall be the new pay of the teacher or equivalent position. If the pay arrived at in this manner is less than the first Cell in the new Level, then the pay shall be fixed at the first Cell of the new Level.

Allowances and
Benefits

(1) Allowances and Benefits

I. Other allowances and benefits, such as Hometown Travel Concession, Leave Travel Concession, Special Compensatory Allowances, Children's Education Allowance, Transport Allowance, House Rent Allowance, House Building Allowance, Deputation Allowance, Travelling Allowance, Dearness Allowance, Area-based Special Compensatory Allowance etc. for teachers and Library shall be as applicable to the State Government employees and be governed by the relevant rules as notified by the State Government from time to time.

II. Pension, Gratuity, ex-gratia compensation *etc.* as applicable to State Government employees shall also be applicable to teachers and Library cadre of State University.

III. Medical Benefits: All medical benefits for teachers and Library Cadres, shall be as applicable to the State Government employees. Further, the Teachers and Library Cadres may be placed under State Government Health Scheme or Health Scheme of State Government, as the case may be, for State Universities:

APPENDICES

Appendix I	Fitment Tables for fixation of pay of the existing incumbents, who were in position as on 01.01.2016, in various categories of posts indicated in the tables (MHRD Notification MHRD letters No. Corrigendum F.No.1-7/2015-U.II(1) dated 08.11.2017)
Appendix II	Assessment Criteria and Methodology Table 1 to 3 - For University Table 4 - For Assistant Librarian, Deputy Librarian, Librarian etc.

Fitment Tables for fixation of pay of the existing incumbents, who were in position as on 01.01.2016, in various categories of posts indicated in the tables:

F.No.1-7/2015-U.II(1)

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Higher Education

New Delhi

Shashi Prasad, New Delhi

Dated: 8 November, 2017

Corrigendum

Subject: Scheme of revision of pay of teachers and equivalent cadres in universities and colleges following the revision of pay scales of Central Government employees on the recommendations of the 7th Central Pay Commission (CPC).

In the order of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) no. 4-7/2015-U.II(1) dated 2.11.2017 in the Annexure Page 2, it appeared to be read as "1,02,700" instead of "1,02,700".

(a) Cell 15, Annexure 11, Row 4 may be read as "1,02,700" instead of "1,02,700".

(b) Cell 15, Annexure 11, Row 5 may be read as "1,02,700" instead of "1,02,700".

(c) Cell 15, Annexure 11, Row 6 may be read as "1,02,700" instead of "1,02,700".

Corrigendum

The order of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) no. 4-7/2015-U.II(1) dated 2.11.2017 in the Annexure Page 2, it appeared to be read as "1,02,700" instead of "1,02,700".

Dr. K.K. Saxena, New Delhi

Director

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.

2. The Secretary, Central Board of Secondary Education, New Delhi - 110002.

3. The Secretary, National Council for Technical Education, New Delhi - 110002.

4. The Secretary, Ministry of Human Resource Development, New Delhi - 110002.

5. The Secretary, Ministry of Education, Government of India, New Delhi - 110002.

6. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

7. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

8. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

9. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

10. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

11. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

12. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

13. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

14. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

15. The Secretary, Ministry of Higher Education, Government of India, New Delhi - 110002.

Appendix I

Fitment Table for Fixation of Pay

Annexure-I

Pay Matrix

Pay Band (Rs.)	15,600-39,100			37,400-67,000		67,000-79,000
Grade Pay (Rs.)	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	0
Index of Rationalization	2.67	2.67	2.67	2.67	2.72	2.72
Entry Pay (Rs.)	21,600	25,790	29,900	49,200	53,000	67,000
Academic Level	10	11	12	13A	14	15
Rationalised Entry Pay (Rs.)	57,700	68,900	79,800	1,31,400	1,44,200	1,82,200
2	59,400	71,000	82,200	1,35,900	1,48,500	1,87,700
3	61,200	73,100	84,700	1,39,400	1,52,000	1,92,200
4	63,000	75,200	87,200	1,43,000	1,57,000	1,99,100
5	64,900	77,600	89,800	1,47,900	1,62,300	2,05,100
6	66,800	79,900	92,500	1,52,300	1,67,200	2,11,300
7	68,800	82,300	95,300	1,56,900	1,72,200	2,17,600
8	70,900	84,800	98,200	1,61,800	1,77,400	2,24,100
9	73,000	87,300	1,01,100	1,66,400	1,82,700	
10	75,200	89,900	1,04,100	1,71,400	1,88,200	
11	77,600	92,600	1,07,200	1,76,500	1,93,900	
12	79,800	95,400	1,10,400	1,81,600	1,99,800	
13	82,200	98,300	1,13,700	1,87,300	2,05,800	
14	84,700	1,01,200	1,17,100	1,92,900	2,11,800	
15	87,200	1,04,200	1,20,600	1,98,700	2,18,200	
16	89,800	1,07,300	1,24,200	2,04,700		
17	92,500	1,10,600	1,27,900	2,10,900		

K.K. Tripathi
21/10

Pay Band (Rs.)	15,600-39,100			37,400-67,000		67,000-79,000
18	95,300	1,13,800	1,31,700	2,17,100		
19	98,200	1,17,200	1,35,700			
20	1,01,100	1,20,700	1,39,800			
21	1,04,100	1,24,300	1,44,000			
22	1,07,200	1,28,000	1,48,300			
23	1,10,400	1,31,800	1,52,700			
24	1,13,700	1,35,500	1,57,300			
25	1,17,100	1,39,900	1,62,000			
26	1,20,600	1,44,100	1,66,900			
27	1,24,200	1,48,400	1,71,900			
28	1,27,900	1,52,900	1,77,100			
29	1,31,700	1,57,500	1,82,400			
30	1,35,700	1,62,200	1,87,900			
31	1,39,800	1,67,100	1,93,500			
32	1,44,000	1,72,100	1,99,300			
33	1,48,300	1,77,300	2,05,300			
34	1,52,700	1,82,600	2,11,500			
35	1,57,300	1,88,100				
36	1,62,000	1,93,700				
37	1,66,900	1,99,500				
38	1,71,900	2,05,500				
39	1,77,100					
40	1,82,400					

K.K. Tripathi
21/11

Appendix-II**Table-1****Assessment Criteria and Methodology for University Teachers**

S.No.	Activity	Grading Criteria
1	Teaching: (Number of classes taught/total classes assigned)x100% (Classes taught includes sessions on tutorials, lab and other teaching related activities)	80% & above - Good Below 80% but 70% & above-Satisfactory Less than 70% - Not satisfactory
2	Involvement in the University/ College students related activities/ research activities: (a) Administrative responsibilities such as Head, Chairperson/ Dean/ Director/ Co-ordinator, Warden etc. (b) Examination and evaluation duties assigned by the college / university or attending the examination paper evaluation. (c) Student related co-curricular, extension and field based activities such as student clubs, career counselling, study visits, student seminars and other events, cultural, sports, NCC, NSS and community services. (d) Organising seminars/ conferences/ workshops, other college/university activities. (e) Evidence of actively involved in guiding Ph.D students. (f) Conducting minor or major research project sponsored by national or international agencies. (g) At least one single or joint publication in peer- reviewed or UGC list of Journals.	Good - Involved in at least 3 activities Satisfactory - 1-2 activities Not-satisfactory - Not involved / undertaken any of the activities Note: Number of activities can be within or across the broad categories of activities

Overall Grading:**Good:** Good in teaching and satisfactory or good in activity at Sl.No.2.

Or

Satisfactory: Satisfactory in teaching and good or satisfactory in activity at Sl.No.2.**Not Satisfactory:** If neither good nor satisfactory in overall grading

Note: For the purpose of assessing the grading of Activity at Serial No. 1 and Serial No. 2, all such periods of duration which have been spent by the teacher on different kinds of paid leaves such as Maternity Leave, Child Care Leave, Study Leave, Medical Leave, Extraordinary Leave and Deputation shall be excluded from the grading assessment. The teacher shall be assessed for the remaining period of duration and the same shall be extrapolated for the entire period of assessment to arrive at the grading of the teacher. The teacher on such leaves or deputation as mentioned above shall not be put to any disadvantage for promotion under CAS due to his/her absence from his/her teaching responsibilities subject to the condition that such leave/deputation was undertaken with the prior approval of the competent authority following all procedures laid down in these regulations and as per the acts, statutes and ordinances of the parent institution.

Table- 2**Methodology for University Teachers for calculating Academic/Research Score**

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.,)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Languages/ Humanities / Arts / Social Sciences/ Music, Performing Arts, Visual Arts and Other Traditional Indian Art Forms like Sculpture, Drama, Yoga and other related disciplines
1.	Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals	10 per paper
2.	Publications (other than Research papers) (a) Books authored which are published by ; International publishers National Publishers Chapter in Edited Book Editor of Book by International Publisher Editor of Book by National Publisher (b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties Chapter or Research paper Book	12 10 05 10 08 03 08
3.	Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula (a) Development of Innovative pedagogy (b) Design of new curricula and courses (c) MOOCs Development of complete MOOCs in 4 quadrants (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit) MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant) Course Coordinator for MOOCs (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit) (d) E-Content Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book e-Content (developed in 4 quadrants) per module Contribution to development of e-content module in complete course/paper/e-book (at least one quadrant) Editor of e-content for complete course/ paper / e-book	05 02 per curricula/course 20 05 02 08 12 05 02 10

4.	(a) Research guidance Ph.D. M.Phil./P.G dissertation (b) Research Projects Completed More than 10 lakhs Less than 10 lakhs (c) Research Projects Ongoing : More than 10 lakhs Less than 10 lakhs (d) Consultancy	10 per degree awarded 05 per thesis submitted 02 per degree awarded 10 05 05 02 03
5.	(a) Patents International National (b) *Policy Document (Submitted to an International body/organisation like UNO/UNESCO/World Bank/ International Monetary Fund etc. or Central Government or State Government) International National State (c) Awards/Fellowship International National	 10 07 10 07 04 07 05
6.	*Invited lectures / Resource Person/ paper presentation in Seminars/ Conferences/ Performance/ Exhibition/ Choreography/ Catalogue/ Workshop/ Direction/full paper in Conference Proceedings (Paper presented in Seminars/Conferences and also published as full paper in Conference Proceedings will be counted only once) International (Abroad) International (within country) National State/University	 07 05 03 02

The Research score for research papers would be augmented as follows :

Peer-Reviewed or UGC-listed Journals (Impact factor to be determined as per Thomson Reuters list) :

- | | | | |
|-------|--|---|-----------|
| (i) | Paper in refereed journals without impact factor | - | 5 Points |
| (ii) | Paper with impact factor less than 1 | - | 10 Points |
| (iii) | Paper with impact factor between 1 and 2 | - | 15 Points |
| (iv) | Paper with impact factor between 2 and 5 | - | 20 Points |
| (v) | Paper with impact factor between 5 and 10 | - | 25 Points |
| (vi) | Paper with impact factor >10 | - | 30 Points |

Two authors: 70% of total value of publication for each author.

More than two authors: 70% of total value of publication for the First/Principal/Corresponding author and 30% of total value of publication for each of the joint authors.

Joint Projects: Principal Investigator and Co-investigator would get 50% each.

Note:

- Paper presented if part of edited book or proceeding then it can be claimed only once.
- For joint supervision of research students, the formula shall be 70% of the total score for Supervisor and Co-supervisor. Supervisor and Co-supervisor, both shall get 7 marks each.
- *For the purpose of calculating research score of the teacher, the combined research score from the categories of 5(b). Policy Document and 6. Invited lectures/Resource Person/Paper presentation shall have an upper capping of thirty percent of the total research score of the teacher concerned.
- The research score shall be from the minimum of three categories out of six categories.

Table-3**Criteria for Short-listing of Candidates for Interview for the Post of Assistant Professors in Universities**

S.N.	Academic Record	Score			
1.	Graduation	80% & Above = 15	60% to less than 80% = 13	55% to less than 60% = 10	45% to less than 55%=05
2.	Post-Graduation	80% & Above = 25	60% to less than 80% = 23	55% (50% in case of SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ PWD) to less than 60% = 20	
3.	M.Phil.	60% & above = 07	55% to less than 60% = 05		
4.	Ph.D.	30			
5.	NET with JRF	07			
	NET	05			
	SLET/SET	03			
6.	Research Publications (2 marks for each research publications published in Peer-Reviewed or UGC-listed Journals	10			
7.	Teaching / Post Doctoral Experience (2 marks for one year each)#	10			
8.	Awards				
	International / National Level Awards given by International Organisations/ Government of India / Government of India / India recognised National Level Bodies)	03			
	State-Level (Awards given by State Government)	02			

#However, if the period of teaching/Post-doctoral experience is less than one year then the marks shall be reduced proportionately.

Note:

- (A) (i) M.Phil + Ph.D Maximum - 30 Marks
(ii) JRF/NET/SET Maximum - 07 Marks
(iii) In awards category Maximum - 03 Marks
- (B) Number of candidates to be called for interview shall be decided by the concerned universities.
- (C) Academic Score - 80
Research
Publications - 10
Teaching Experience - 10

Total	-	100
--------------	----------	------------

(D) Score shall be valid for appointment in respective State SLET/SET University only.

Table-4
Assessment Criteria and Methodology for Librarians

S.No.	Activity	Grading Criteria	Assessment Criteria and Methodology for Librarians
1	<p>Regularity of attending library (calculated in terms of percentage of days attended to the total number of days he/she is expected to attend)</p> <p>While attending in the library, the individual is expected to undertake, <i>inter alia</i>, following items of work:</p> <ul style="list-style-type: none"> Library Resource and Organization and maintenance of books, journals and reports. Provision of Library reader services such as literature retrieval services to researchers and analysis of report. Assistance towards updating institutional website 	<p>90% and above – Good</p> <p>Below 90% but 80% and above – Satisfactory</p> <p>Less than 80% - Not satisfactory</p>	

S.No.	Activity	Grading Criteria
2	Conduct of seminars/workshops related to library activity or on specific books or genre of books.	Good – 1 National level seminar/ workshop + 1 State/institution level workshop/ Seminar Satisfactory - 1 National level seminar/ workshop or 1 state level seminar/ workshop + 1 institution level seminar/ workshop or 4 institution seminar / workshop Unsatisfactory – Not falling in above two categories
3	If library has a computerized database then OR If library does not have a computerized Database	Good – 100% of physical books and journals in computerized database. Satisfactory – At least 99% of physical books and journals in computerized database. Unsatisfactory – Not falling under good or satisfactory. OR Good – 100% Catalogue database made up to date Satisfactory- 90% catalogue database made up to date Unsatisfactory - Catalogue database not upto mark. (To be verified in random by the CAS Promotion Committee)
4	Checking inventory and extent of missing Books	Good : Checked inventory and missing book less than 0.5% Satisfactory - Checked inventory and missing book less than 1% Unsatisfactory - Did not check inventory Or Checked inventory and missing books 1% or more.
5	(i) Digitisation of books database in institution having no computerized database. (ii) Promotion of library network. (iii) Systems in place for dissemination of information relating to books and other resources. (iv) Assistance in college administration and governance related work including work done during admissions, examinations and extracurricular activities.	Good : Involved in any two activities Satisfactory : At least one activity Not Satisfactory : Not involved/ undertaken any of the activities.

S.No.	Activity	Grading Criteria
	(v) Design and offer short-term courses for users. (vi) Publications of at least one research paper in UGC approved journals.	
Overall Grading	<p>Good : Good in Item 1 and satisfactory/good in any two other items including Item 4.</p> <p>Satisfactory : Satisfactory in Item 1 and satisfactory /good in any other two items including Item 4.</p> <p>Not satisfactory : If neither good nor satisfactory in overall grading.</p>	
Note:	<p>(1) It is recommended to use ICT technology to monitor the attendance of library staff and compute the criteria of assessment.</p> <p>(2) The Librarian must submit evidence of published paper, participation certificate for refresher or methodology course, successful research guidance from Head of Department of the concerned department, project completion.</p> <p>(3) The system of tracking user grievances and the extent of grievances redressal details may also be made available to the CAS promotion committee.</p>	

CHAPTER-X

Section
10(2)
71

45. (a) The Degree of Doctor of letters (D.Litt.) for Mahamahopadhyaya, Honoris causa may be conferred upon such persons as have contributed substantially to the advancement of Literature, Philosophy, Arts, Music, Painting or any other subject assigned to the faculty of Music, Dance or Arts, or for conspicuous services rendered by them to the cause of education.

Conferment and
Withdrawal of
Degree and
Diplomas

(b) The Executive Council may, *suo moto* or on the recommendation of Academic Council by a resolution passed by a majority of its total membership and also of not less than two third of the members present and voting, submit a proposal for conferment of honorary degree to the Chancellor for confirmation:

Provided that no such proposal shall be submitted in respect of a person who is a member of any authority or body of the University.

Section
47 & 72

(c) Before taking any action under Section 72 for the withdrawal of any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University, the person concerned shall be given an opportunity to explain the charges against him. The charges framed against him shall be communicated by the Registrar by a registered post and the person concerned shall be required to submit his explanation within a period of not less than fifteen days of the charges.

Section
47 & 72

(d) Every proposal for the withdrawal of an honorary degree shall require previous sanction of the Chancellor.

(e) An Institute may be recognized by the Executive Council as an institution where research may be carried on in the fulfilment of the requirements of section 22 (1) (a) & (b) of the Act after it has been recommended by the Academic Council with the concurrence of the Board of the Faculty concerned. The recognition so granted may be withdrawn by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council made with the concurrence of the Board of the Faculty concerned.

- (f) The Management of the Institute so recognized shall vest in: -
- (i) A Committee of Management or other equivalent body, appointed by the person or the body maintaining the Institute, the constitution of which shall be reported to the Executive Council, or
- (ii) A Director appointed by the person or the body maintaining the Institute.
- (g) Research work in a recognized Institute may be guided by the Director and other teachers of the Institute who may be recognized as supervisors or advisers for the research degrees of the University.
- (h) The Director and other teachers of the Institute, if they so agree, may deliver a course of advance lectures to research students of the University with the consent of the Head of the Department concerned.
- (i) Any person having requisite qualifications desirous carrying on research work at the Institute for research degrees of the University shall make an application to the Registrar through the Director of the Institute. The applications so received shall be placed before the Research Degree Committee of the University constituted under Ordinances and, if approved by the Committee, the applicant shall be permitted to start work on payment of such fees as may be decided by University from time to time.
- (j) Any specific grant or donation received for any Institute shall be earmarked for the institute and spent on the Institute. No part of the grant of corresponding department of teaching in the University shall be spent for any other Institute.

CHAPTER-XI

A: Affiliation of Colleges by Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya-

Procedure for Admission of Colleges to the Privileges of the University And For The Recongnition of Examination Centres and withdrawal of such privileges and Recognition

46. Short Title, Application and Commencement :

- (1) This chapter of statute will be regarding Affiliation of Colleges by Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya.
- (2) They shall come into force with immediate effect.

47. Eligibility Criteria for Temporary Affiliation:

(1) The proposed college seeking affiliation, at the time of inspection by the university, shall satisfy the following requirements, or the requirements in respect of any of them prescribed by the Statutory/Regulatory body Concerned in the case of technical/professional courses only.

(2) Administrative, academic and other buildings with sufficient accommodation to meet the immediate academic and other space requirements for each buildings constructed in the college should be disabled friendly.

(3) Academic building sufficient to accommodate the faculties, lecture/seminar rooms, library and a minimum of 15 sq. ft. per student in each of the practice room. For other specific practical oriented courses the requirement for per student will depend on the requirement of the course program.

(4) Number of teaching and non-teaching staff as per University norms.

(5) Adequate civic facilities for essentials like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, *etc.* in conformity with the norms laid down by the Central/State P.W.D.

(6) Adequate measure for safety, security, pollution control, *etc.*

(7) A library with at least 1000 books in different titles on each subject, whichever is more, if the proposed programmes to include both text books and reference books, besides two journals per subject, along with a book bank facility for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other sections as specified by the University.

(8) Necessary musical instruments and equipments as prescribed by the University.

(9) A multi-purpose complex auditorium and facilities for sports canteen, health care, separate common rooms and separate hostels for boys and girls as per the local requirements as decided by the University.

(10) Appropriate furniture for lecture/seminar rooms, library, faculty rooms, rooms for administrative staff including the Principal, auditorium, common rooms and hostel rooms, and for other facilities.

(11) A duly constituted managing body as specified by the University.

48. The college, if not run by the state government:-

(1) shall be managed by a duly constituted and registered society or trust.

(2) Provide an undertaking to the University that it has adequate recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

(3) The Registered Society/Trust in justified exceptional cases may be allowed to start the college for the first year of the programmes in a readily available building, with the condition that all other academic and administrative requirements are satisfied under the Regulations and the college shall complete the buildings per para 50(6) and other requirements cited in the detailed project report by the end of the second year and the college is moved completely to the proposed permanent building by the beginning of the third year, failing which the college shall not be granted renewal of temporary affiliation until the college moves to the permanent buildings. Under no circumstances, extension of time for this movement to the permanent building shall be granted by the University beyond five years.

(4) The Registered Society/Trust proposing the college shall execute a bond.

49. To impart instruction only in the subject and for the courses/programmes in the faculties for which affiliation has been granted by the University and shall not seek retrospective affiliation. All such courses/programmes shall follow the syllabi approved by the appropriate academic bodies of the University:-

(1) to comply with all the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, Rules and Regulations of the University framed in this regard;

(2) to follow the Rules, Regulations and Guidelines of the Statutory/Regulatory bodies issued from time to time;

(3) to the effect that the number of teaching posts, the qualification of teaching staff and their recruitments/promotion procedures as prescribed by the UGC and conditions of service shall be in accordance with the Statutes/Ordinance/Regulations of the University/State Government/UGC, and shall ensure imparting of adequate instruction to the students in the courses/programmes of studies to be undertaken by the college and that the Student-Teacher Ratio in the college shall be as per the UGC norms;

(4) to the effect that the members of the teaching and non-teaching staff shall be regularly and fully paid in the pay scales along with applicable allowances as per the pay scales prescribed by the UGC/Central/State Govt., as the case may be, from time to time;

(5) to the effect that appointment of members of the teaching and the non-teaching staff shall be made only on considerations of merit based on qualifications and experience prescribed for them and not by demanding or accepting any donation or other consideration;

(6) to the effect that the college shall obtain the eligibility approval of the appointed teaching staff from the University within three months of affiliation and shall report all changes in the teaching staff and all other changes that may affect the fulfillment of the conditions for affiliation to the University within a fortnight of changes coming into effect.

(7) to the effect that all fees to be charged from the students shall be as per the fee structure approved by the University;

(8) to the effect that the college shall not collect any capitation fee or donation in any form amounting to corrupt practices from or on behalf of any of its students or their parents/guardians except the prescribed fee and other charges as approved by the University;

(9) to the effect that no student shall be admitted to any programme of study by the college in anticipation of grant of affiliation or in excess of the number of seats sanctioned per programme of study by the University;

(10) to the effect that the college shall not, without the previous permission of the University, suspend offering an already approved course/programme of study;

(11) To the effect that the academic and welfare activities of the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups, including minorities, wherever applicable, shall be properly taken care of by the college;

(12) to the effect that all registers and records, including audited statement of accounts, as required to be maintained under the Orders of the UGC/University/Government shall be maintained and made available as and when required for inspection;

(13) to the effect that the college shall furnish all such returns and other information as the UGC/University/Government may require to enable it to monitor and judge the performance of the college with regard to maintenance of academic standards and shall take such action as the UGC/University/Government may direct to maintain the same;

50. Procedure for granting Temporary Affiliation:

(1) The application to start a new college and to get it affiliated to a University can be submitted by Central/State Government institutions and Registered Society/Trust.

(2) If the applicant is a Society/Trust, it shall have been registered under Registration of Societies Act, the Trusts Act or any other Act of the Central/State Government on or before the date of submission of the application.

(4) The Government/Society/Trust which proposes to start the college and wishes to get it affiliated to the University in whose jurisdiction the location or college falls shall make an application within the stipulated time to the University in the prescribed proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.

51. The application shall be submitted with certified copies of the following documents:-

(1) Registration of the Society/Trust along with details of Constitution and Memorandum of Association;

(2) Letter from the Competent Authority designated by the Government concerned for classification of land and its location as Metropolitan for other areas;

(3) Land Use Certificate from the Competent Authority designated by the Government concerned;

(4) Registered land/Govt. leased land documents in the name of the applicant;

(5) Appropriate order from the Govt. permitting the Society/Trust to start the college with details of the courses/programmes intended to be offered;

(6) Building Plan of the proposed college prepared by a registered Architect and approved by the Competent Authority designated by the Govt. concerned;

(7) Registered documents by the registered Society/Trust earmarking land and buildings for the proposed college;

(8) Details of the latest fund positions along with photocopies of relevant bank accounts, including the evidence of the Corpus Fund.

52. Detailed Project Report giving

(a) background of the Society/Trust with reference to its experience in promoting, managing and operation educational institutional; details of the its promoters including their background; its activities in the social, charitable and educational spheres since its inception and its Vision and Mission;

(b) development plan for the college with timeline, spelling out its growth plan over the first 10 year period in terms of phasing of academic programmes, increase in students' intake and introduction of postgraduate programmes/research, and the time schedule for stage-wise development of the academic infrastructure, like recruitment of faculty, and other support facilities, including student amenities, such as hostels, sports and recreational facilities.

(c) architectural master plan indication the land use pattern including those for the future;

(d) policy with regard to faculty recruitment, retention and development;

(e) structure of academic and administrative governance;

(f) sources of financing of capital and operating expenditure, besides funds to be generated through students' fees; and

(g) resource projections and their utilization schedule.

(1) The University shall make a preliminary scrutiny of the application, and if found satisfactory, issue a letter of intent, within two weeks from the date of receipt of the application by the university, to cause an inspection within a period of three months for physical verification of all requirements for the grant of temporary affiliation.

(2) The college shall be subjected to an inspection by the University through a committee of experts nominated by the Vice chancellor consisting of.

(3) One Expert for each of the subject areas proposed.

(4) Dean, College Development Council/an equivalent academician of the university.

(5) A representative of the culture department of the Government not below the rank of Deputy Director, and

(6) An Engineer from P.W.D./C.P.W.D. or the University (or his representative) not below the rank of Executive Engineer.

One of the subject experts at the level of Professor, as nominated by the Vice Chancellor, shall be the Chairperson of the Committee.

Note: The applicant shall deposit adequate amount for travel expenses of the inspection board constituted by the university. The members of the inspection board shall avail the T.A. and D.A. as per their entitlement.

(7) The report of the inspection committee shall be submitted by the Chairperson to the University duly filled in and signed by all the members. The University shall process the report through its appropriate Bodies and decide to grant, or not to grant, temporary affiliation to the colleges, recording the reasons in writing for its decision within three months of inspection.

(8) On the basis of the infrastructure and other facilities available at the college, the University shall decide the number of Seats for each programme in the college.

(9) The Executive Council of the University shall be the ultimate authority to decide granting, or not granting, affiliation.

(10) Continuation of temporary affiliation of the programmes of study and the college itself shall be granted by the University on a year to year basis through inspection process prescribed in these Regulations.

(11) If the University decides not to grant affiliation to the college for reason, recorded in writing, of its failure to meet the conditions/requirements for getting affiliation the college may apply again if it fulfils the conditions /requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.

Note: the affiliation fee, annual continuation fee and the specific dates for remittance of all fees shall be decided by the university from time to time.

53. Eligibility Criteria for Permanent Affiliation:

(1) The college shall have completed at least five year of satisfactory performance after getting temporary affiliation and attained the academic and administrative standards as prescribed by the University/UGC/Statutory/Regulatory Body concerned from time to time.

(2) The college shall have completed construction of buildings and all infrastructure/facilities as stipulated in the Statute/Ordinance.

(3) All the teaching and non teaching staff are appointed on permanent (appointed on regular basis, in case of a Government college) on the UGC/Government scales of pay.

(4) The college shall have a duly constituted College Council as per the norms.

(5) The college shall be accredited by NAAC or any other accreditation agency by State/Central Government.

54. Procedure for granting Permanent Affiliation:

(1) A college which wishes to get permanent affiliation shall apply to the University any time after completing five years of temporary affiliation in the proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.

(2) The procedure for according permanent affiliation shall be the same as for granting temporary affiliation given in Statute.

(3) If University decides not to grant permanent affiliation to the college for reasons, to be recorded in writing, of its failure to meet the conditions/requirements for getting such affiliation, the college may apply again if it fulfills the conditions/requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.

55. Eligibility to apply for addition of new programmes of study:

(1) Any proposal for adding new programmes shall be considered by the University only after ensuring equitable distribution of facilities for higher education having due regard in particular to the needs of the unserved underdeveloped, rural, hilly, tribal and backward areas within its jurisdiction.

(2) Any proposal for raising the existing under-graduate college to postgraduate studies level shall be considered by the University only after satisfactory completion of two years of the under-graduate programme and the proposed buildings qualified faculty and other infrastructure facilities are fully created as per the statute.

(3) Each application for addition of a new programme or for upgrading the existing programme to post graduate level shall be accompanied by the prescribed fee in the form of Demand drawn in favour of the Registrar of the University.

(4) The procedure for according temporary affiliation to additional programmes of study or for upgrading the existing programmes in the college shall be the same as prescribed under the Regulations for temporary affiliation.

56. Withdrawal of affiliation

(1) The privileges conferred on a college by affiliation may be withdrawn in part or in full suspended or modified if the college on due enquiry is found to have failed to comply with any of the provisions of the Act the Statutes the Ordinances the Rules and Regulations or any other direction or instruction of the UGC/University body university conducted or failed to observe any of the conditions of affiliation or has conducted itself in a manner prejudicial to the academic and administrative standards and interests of the University.

(2) If an affiliated college ceases to function or is shifted to a different location or is transferred to a different Society, Thust individual or a group of individuals without the prior approval of the University the affiliation granted to the college shall lapse automatically on such ceaser shifting or transfer as the case may be, and it shall be treated as a new college for the purposes of future affiliation. The University/ Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.

(3) Without prejudice to the statute on its own, or on the basis of any complaint or any other information or report from any other source, can cause an enquiry by the University in respect of a college and after giving the college a reasonable opportunity of being heard may pass an order under Section (12A) (4) of the UGC Act prohibiting such college from presenting any student then university for the award of the qualification concerned and the affiliation of the college shall stand terminated as per Section (12A) (5) of the UGC Act.

Examination
Centers

(4) If the University decides to withdraw the affiliation of the college, or the affiliation stands terminated by the order of the University temporarily or permanently, such decision shall not affect the interests of the students of the college who were on its rolls at the time of issue of the order till they pass out the normal duration of programmes to which they are registered at that time. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of affected students in an appropriate manner as per its decision.

(B) Examination Centers:

1. Application for recognition of Examination Centre shall be accepted in the prescribed form along with the fees prescribed by the university from time to time.

2. The institution concerned shall bear the actual expenditure on T. A. /D. A. of the Board of Inspectors consisting of three members, out of whom two shall be subject experts and one shall represent the administration appointed by the Vice-Chancellor. The Committee after an inspection shall submit the detailed report of the centre regarding the recognition.

3. On receipt of an application, the Vice-Chancellor shall appoint a Board of Inspector who shall visit the institution and satisfy itself with regard to the following:-

(a) That the institution is a duly Registered Body.

(b) That the institution has the capacity to make arrangements for examinations of the private candidates *viz:* accommodation, furniture, musical instruments *etc.*

(c) That there is not legal proceeding against the Institution, which may debar it from recognition as an Examination Centre.

4. The report of the Board of Inspectors shall be submitted to the University within two weeks of its visit to the Institution and the same shall be placed before the Executive Council for consideration.

5. The Executive Council shall after considering the report, accord the necessary recognition with conditions, if any, to be fulfilled by the Institution within a specified period or reject the application.

6. An Examination Centre shall have at least fifty students to appear in the examinations failing which the centre shall be liable to be de-recognised subject to the approval of the Executive Council. The Council may consider some of the centres to continue for one or two years as a special case if it finds justification of the centre is valid.

7. The annual continuation fee and the specific dates for remittance of all fees shall be decided by the university from time to time.

8. Withdrawal of privileges of Recognised Centres,-

(a) Whenever, as a result of an adverse report or failure in fulfillment of the conditions prescribed, the Executive Council consider it necessary to initiate action for the withdrawal of all or any of the privileges granted to recognition given to an Institution, the Executive Council shall issue a show cause notice to the Governing Body or the Government as the case may be apprising the decision of the Executive Council. Further an institution of recognised examination centres is admitted for the privileges of the University for a certain period and the recognition is not extended further the privileges shall be withdrawn automatically.

(b) The notice under sub-para (a) shall state that—

(a) The reasons for which the intended action is contemplated, and

(b) The specified time of the reply of show cause notice to be reached to the Registrar of the University.

(c) The Executive Council, for reasons recorded, may extend the period for reply from time to time but the total period shall not exceed three months.

(d) On receipt of the reply of the show cause notice to the college within the stipulated period, under sub-para (2) and (3), the Executive Council may consider the matter in the light of the reply and representation made, if any, by the recognised examination centre concerned. If no such reply is received, it may consider the matter after expiry of the said period and make such order as deemed fit as withdrawal of all or any of the privileges granted to the recognised examination centre accorded to an Institution.

Research Centre affiliated to the University as regular Centre for presenting students as Internal Candidates to the University research.

Procedure For
Admission of
Research Centre
To The
Privileges of the
University

Research Centre:

1. An application for affiliation of Research Centre either for the first time or for addition of a new course for research shall be submitted by the officer of the Government if the centre is maintained by the Government or by the President of the Founding Society/Governing Body with a copy of relevant resolution of the Founding Society/ Governing Body seeking such affiliation.

Research Centre

2. All applications shall reach to the Vice-Chancellor/Registrar of the University.

3. The application for affiliation and/or addition of subject/course shall be accompanied with the details of the institution on the form prescribed by the University along with the following fees:-

4. The fee will be decided by the University

Note: In addition of the above prescribed fees, the Centres concerned shall bear the actual expenditure on the T. A. /D. A. of a board of three Inspectors which shall be appointed by the Vice-Chancellor to report the University about the infrastructure after the inspection of the Centre for the affiliation.

5. On receipt of an application mentioned in the preceding paragraph along with all details and fees, the Vice-Chancellor shall appoint a Board of Inspectors, which includes two experts from the Teaching Faculties and one representative of University administration.

6. The Board of Inspectors shall inspect the Centres and submit the report to the University as per the rule laid down as under.

7. The Centre shall have Endowment funds of Rs. 5,00,000/- (Rs. five lacs only) deposited in the name of the centre, to be utilized exclusively for the purpose of the Centre.

8. The centre shall have provision for a good Library.

9. Adequate facilities such as furniture, teaching materials, musical instruments /equipments and studio equipments for Visual Arts *etc.* are mandatory.

10. The report of the Board of Inspectors shall be submitted to the University within two weeks of their visit to the centre concerned duly signed by all the members of the Board. On receipt of the report, the same shall be placed before the Academic Council and Executive Council for approval. After the approval of Executive Council the same shall be forwarded to the State Government for its approval. After the receipt of the approval of the State Government. The Centre shall be notified as permanent affiliation Centre.

Withdrawal of privileges of Affiliated Centres:

1. Whenever as a result of an adverse report submitted by the University regarding the failure in fulfillment of the conditions prescribed by the Executive Council and to consider to initiate action for withdrawal of all or any of the privileges granted to a centre, the Executive Council shall issue a show cause notice to the Governing Body of the Government as the case may be apprising of the decision of the Executive Council. Further when a centre is admitted for the privileges of the University for a certain period and the affiliation is not extended further, the privileges shall be considered automatically withdrawn.

2. The notice sub-para (1) shall state that:

(a) The reasons for which the intended action is contemplated and

(b) The specified time of the reply of show cause notice to be reached to the Registrar of the University.

3. The Executive Council for reasons recorded, may extend the period for reply from time to time but the total period shall not exceed more than three months.

4. On receipt of the reply of the show cause notice to the Centre within the stipulated period, under sub-para (2) and (3), the Executive Council may consider the matter in the light of the reply and representation made, if any, by the Centre concerned. If no such reply is received, it may consider the matter after expiry of the said period and make such order as deemed fit as a withdrawal of all or any of the privileges granted to the Centre or Institution.

Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya**Lucknow (U.P.)****APPLICATION FORM FOR AFFILIATION OF
COLLEGES/RECOGNITION OF EXAM CENTERS**

This form can be used for the following purposes:

1. Affiliation/Recognition of the Institutions
2. Affiliation/Recognition for the Additional Courses/Subjects
3. Extension of Affiliation/Recognition

PART-I**(TO BE FILLED BY ALL INSTITUTES)**

1. Name of the college :

2. Full Postal address :

Telephone No. Office :

Residence :

Fax No. :

E-Mail :

3. Name of Principal

(Enclose complete bio- data mentioning Date of Birth and details of qualification)

4. For Non-Government college

a. Registration No. of College/Center -----

Date -----

b. Name of Governing body/Society -----

c. Registration No. of governing body/society -----

Date -----

d. Name and address of the members of the governing body with designation (Attach a separate list attested by the registrar of society) and also enclose attested copy of the statue.

5. Whether the governing body runs any other educational institutions.

If yes

- a. Name of the Institution :
- b. Details of Affiliation :
- c. Others :

6. Date of foundation of the college :

PART - II

(ONLY FOR THOSE COLLEGES/CENTERS, APPLYING FOR THE FIRST TIME)

7. Affiliation required in
- | | |
|-------------|----------------------|
| Music | <input type="text"/> |
| Dance | <input type="text"/> |
| Folk Music | <input type="text"/> |
| Visual Arts | <input type="text"/> |

Mark (✓) whichever is applicable.

8. Details of the Courses/subjects for affiliation/recognition (See Annexure - I)

9. Whether the college has been affiliated with any other Board/University? If yes, please give details:

10. Details of the Teaching/Non-Teaching Staff (See Annexure - II)

11. Whether the governing body/college accepts pay scales as per college code of the University. Yes ☐ No ☐

12. Details of salary of the teachers listed in column: 10 (See Annexure - II)

13. Furnish the following details for starting the proposed courses. (Attach a separate list)

- a. Class room (No. of rooms with size)
- b. Furniture
- c. Musical instruments/ Equipments
- d. Books, Journals and periodicals (Mention number of Books and Name of Journals subscribed)

14. Financial position of the college:

- a. Fixed assets:
 - 1. Cash Deposit:
 - 2. Estimated cost of musical instruments:
 - 3. Estimated cost of land & building (if applicable)
- b. Annual Income: (If needed attach separate sheet)
 - 1. Grant from Government/any other agency-
 - 2. Donation:
 - 3. Tuition fee:
 - 4. Other fee:
 - 5. Other source (If any)
- c. Details of loan A/C (If any) with loan agreement, audited balance sheet of last 3 years.

15. Particulars of the building: Building plan (blueprint) must be enclosed

a. No. of Classrooms with size

(Enclose a separate list) :

No. of toilets - Male:

- Female:

b. Details of Auditorium - Size:

- Capacity:

c. Details of playground (if available):

d. Enclose a separate list of Sports/Games items:

e. Whether Building is owned, rented or donated:

Owned ☐ Rented ☐ Donated ☐

If owned, enclose allotment registration letter:

If rented, mention the rent:

If donated, mention terms & conditions:

(Enclose a copy of donation/rental deed)

f. If the classes are conducted in Govt. building, enclose copy of the approval.

g. In case of any other arrangement, give details

16. Details of bank account of the college/center

a. Name of the bank:

b. Name of branch:

c. Type of account:

d. Authorized officer for operating the account:

17. Timing of the college:

PART -III

(TO BE FILLED ONLY BY THE COLLEGE/CENTER SEEKING
EXTENTION OF AFFILIATION/RECOGNITION FOR NEW
COURSES/SUBJECTS)

**1. Details of the Courses/Subjects for which
affiliation/recognition has been obtained previously:
(Annexure - III)**

2. Details of the Courses/Subjects for which affiliation is sought:

1. Courses

2. Subjects

3. No. of Students appeared in examination during the last three years.

3. Details of the dues, if any payable to the University.

**4. Enclose copy of the approval by the Government/Governing body for the
proposed affiliation/recognition.**

**5. Details of the dues, if any payable to the Government/Governing body for
the proposed affiliation.**

6. For new courses furnish following details:

a. Extra classrooms

b. Musical Instruments

c. Books

d. Furniture

**7. Whether the college has fulfilled all the terms & conditions of the
affiliation already granted? If not give reasons:**

Details of loan A/C if any, including repayment conditions.

DECLARATION

I hereby declare that all the above statements are true to the best of my knowledge & belief and also assure that college/center will fulfill all the terms and conditions as per the college code prescribed by the University from time totime.

Signature with Seal

President of the

Governing Body

(For Non Govt. College)

Signature with Seal

Statutory Officer

(Govt. College)

Signature & Seal

Principal

* ENCLOSERS

A: Teaching Staff

No.	Name	Designation	Date of Birth	Qualification		Date of Appointment	Salary (Pay-scale)
				Academic	Professional		
1.		Principal					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

B: Non-Teaching Staff

No.	Name	Designation	Date of Birth	Qualification	Date of Appointment	Salary(Pay-scale)
1.		Principal			00.00.0000	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

CHAPTER-XII

Section 45

57. (1) A Convocation for conferring its Degrees, Diplomas, Convocation

and other academic distinctions may be held by the University not more than once in a year on such date and at such time as the Executive Council may appoint.

(2) A special convocation may be held by the University with the prior approval of the Chancellor.

Section
45

58. The procedure to be observed at the convocations referred to in this Chapter and other matters connected therewith shall be such as may be laid down in the regulations.

Section
45

59. Where the University, does not find it convenient to hold the convocation in accordance with Statute the degrees, diploma and other academic distinctions may be dispatched to the candidates concerned by registered post.

A convocation for the purpose of conferring Degrees and making awards shall ordinarily be held every year in the month of December at the Head Quarters of the University and shall be held at such time as may be found necessary or convenient be fixed by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor.

Convocation
(Deekshant
Samaroh)
Procedure

1. University will grant Degrees and other awards to its eligible students regularly in every academic year.

2. To assist the eligible students going for employment, higher studies and/or other opportunities, by giving their Degrees and other awards without delay.

3. Ordinarily not less than four weeks' notice shall be given by the registrar for holding convocation. This period may however be reduced to 10 days in the case of Special Convocation or in any other case where such a course is considered expedient by the Vice-Chancellor.

4. The candidates desiring to receive degree in person must apply to the Registrar 15 calendar days before the date fixed for the convocation in the prescribed form together with a fee Prescribed by the university from time to time intimating their intention to be present at the convocation.

Provided that the Vice-Chancellor may in special cases permit the receipt of late applications up to seven days before the date of convocation, if such application are accompanied by a late fee Prescribed by the university from time to time.

5. Such candidates as are unable to present themselves in person at the convocation may apply for receiving their degrees in absentia in the prescribed form one month after the date of convocation along with a fee and postal Charges.

6. Every degree shall bear the signature of the Vice-Chancellor. The date on the degrees whether to be awarded at the convocation or otherwise, will be the same as the date of the University convocation. Furthermore, if for any reason the convocation is not held, then the date on the degrees will be as per the schedule mentioned in the Academic Calendar of the University.

7. The Chancellor, Vice-Chancellor, Deans of faculties, members of the Executive Council, Academic Council and Registrar shall wear the academic costumes of the University of which they are graduates or the gowns or any other costumes prescribed by the Executive Council.

8. Candidates at the convocation shall put on the academic robe prescribed by the Executive Council and no candidate shall be admitted to the

convocation without the academic robe prescribed by the University.

9. Degree will be distributed to the candidates attending the convocation at the place, time and day specified by notification after the convocation as decided by the University.

10. The University shall hold convocation or follow any other method on the date/s so fixed to confer the Degrees and other awards to eligible students.

11. If convocation is held, it shall include the ceremonial aspects, as per the provisions made for them.

12. If for any reason the convocation is not held, the University shall only give away the Degrees and other awards to the eligible applicants at this time.

13. The University shall have the power to assign selected Colleges to hold graduation ceremonies for their students on its behalf, on the date/s so fixed.

14. Such Colleges shall be required to abide by the directions of the University and hold the graduation ceremonies as per the schedule fixed.

15. The Chancellor the Vice-Chancellor, the Deans of the Faculties members of the Executive Council and Academic Council and the Registrar shall assemble at a place notified, at the appointed hour and shall walk in procession in the following order to the convocation ground-

1. The Registrar
2. Members of the Academic Council
3. Members of the Executive Council
4. Deans of faculties
5. The Vice-Chancellor
6. The Chief Guest, if any
7. The Chancellor

16. The Chancellor, the Chief Guest, the Vice-Chancellor, the Chief Minister, the Culture Minister, Deans of the Faculties, members of the Executive Council, Secretary Culture Department, the Registrar and such other persons named by the Executive Council shall take their seats on the Dias and the members of the Academic Council on Front of the Dias in places reserved for them.

17. The candidates present at the convocation shall take their seats at the places reserved for them before the procession enters in the convocation panel. Is the procession enters the convocation hall/pandal, all those present shall rise and remain standing until the members of the procession have taken their respective seats.

18. The Registrar shall declare the convocation open with the permission of the Chancellor or in his absence with the permission of the Vice-Chancellor. On a request from the Chancellor and in the absence of the Chancellor the Vice-Chancellor will permit the candidates to be presented. The following shall be the order of the presentation-

1. Honorary Degrees, if any
2. D.Litt.
3. Ph.D.
4. Post-Graduates

Degrees in the following faculties-

1. Faculty of Music
2. Faculty of Dance
3. Faculty of Visual Arts
4. Faculty of Arts and Languages.
5. Faculty of Folk Music & Arts

19. The Deans of their respective faculties shall present all the candidates for various degrees under the faculty and the Vice-Chancellor

shall admit the candidates present also in absentia to the degrees concerned. The Citation for the Deans of the faculties and the Vice-Chancellor shall be as prescribed by the Executive Council. Recipients of the degree shall remain standing while the Deans, and the Chancellor admits the candidates to the degree.

20. In the case of conferment of Honorary Degrees, the citation admitting the recipient to the degree may be modified by the Chancellor in a suitable manner. After the degrees have been conferred on regular and private candidates present at the convocation and also in absentia.

21. The Chancellor or in his absence the Vice-Chancellor shall then present the medals and prizes to the recipients of the medals and prizes who shall be called indents of the medals and prizes who shall be called individually by the Registrar and shall stand before the Chancellor shall be read out by the Registrar.

22. The Chancellor or in his absence the Vice-Chancellor shall then request the Chief Guest to address the convocation.

23. The convocation address will thereafter be delivered. The Registrar with the permission of the Chancellor and in his absence with the permission of the Vice-Chancellor will then declare the convocation closed and the procession will leave the convocation all shall remain standing till the procession moves out of the area.

24. Notwithstanding anything contained in the Statute the Chancellor may suspend holding of the annual convocation or convocations. In such case the degrees will be sent to the candidates duly signed by the Vice-Chancellor at their addresses. The Registrar shall notify the suspension of the convocation and invite applications from the candidates who desire to take the degree and shall fix the last date for receipt of such applications. The degree will be sent to those candidates who have applied for obtaining the degrees on payment of a fee Prescribed by the university from time to time plus postal charges. The candidates who do not apply within due date for obtaining degrees shall be given degree as in the case of absentia and the fee fixed for degree in absentia. The dates on such degree shall be the date fixed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Standing Committee of the Academic Council.

25. The Degree award date/s shall be within 180 days of the date/s by which the students are expected to qualify and become eligible for them. Furthermore, in order to facilitate timely disbursement of the Degrees. University may consider disbursing the degrees of the candidates through their respective colleges.

26. In addition to the schedules for academic activities like courses and examinations, the calendar shall also include the date for Degree awards.

27. If necessary, the University may schedule Degree awards more often than once in a year and the same shall be included in its academic calendar.

CHAPTER-XIII

60. CREATION AND FILLING UP OF TEACHING POSTS

(1) Teaching posts in universities, as far as feasible, may be created in accordance with the provisions contained in sec 29(1)(a) of the Act in a pyramidal order, that is, for instance, for one post of Professor, there shall be two posts of Associate Professors and four posts of Assistant Professors, per department.

Miscellaneous

Creation and
Filling up of
Teaching Posts

(2) All the sanctioned/approved posts in the university system shall

Work-Load	<p>be filled up on an urgent basis.</p> <p>61. WORK-LOAD</p> <p>(1) The workload of the teachers shall be as per U.G.C / State Government guidelines.</p>
Other Provisions	<p>62. OTHER PROVISIONS</p> <p>Save as otherwise provide a these statutes, other provisions, not covered by these statutes shall be governed by the relevant provisions of University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges).</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER-XIV</p> <p style="text-align: center;">EMPLOYMENT OF THE DEPENDENT OF DECEASED EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY</p> <p>63. In case a permanent employee, while in service, dies and the wife or husband, as the case may be, who is not already employed under the Central Government or any State Government or any Board or Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government (in which the University is included) a member of his family who is not already employed under the Central Government or the State Government (in which the University is included), may be appointed by the University for relaxation in procedure of selection and maximum age-limit, in a vacant non-teaching post of direct recruitment of Class III or Class IV provided that he applies for within 5 years' commencing from the date of the death of the employee and possesses minimum educational qualification for such a vacant non-teaching post.</p> <p>Explanation- For the purpose of this Statutes -</p> <p>(1) 'dependant' means the son, unmarried or widowed daughter, widow or the widower of the deceased;</p> <p>(2) 'employee' includes teacher/non-teaching employed in the institution.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER-XV</p>
Employment of the Dependent of Deceased employees of the University	
Definitions	<p>64. In these Statutes unless there is anything repugnant in the subject or context-</p> <p>(1) "Examiner" means the Examiner, Local Fund Account, U.P.</p> <p>(2) "Government" means the Government of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) "Officer of the University" means an officer mentioned in any of the clause (c) to (h) of Section 9 of the Act.</p>
Surcharge	<p>65. (1) In any case where the Examiner is of the opinion that there has been a loss, waste or misapplication, which includes misappropriation or unjustifiable expenditure of any money or property of the university as a direct consequence of neglect or misconduct of an officer he may call upon the officer to explain in writing why such officer should not be surcharged with the amount of such loss, waste or misapplication of money or the amount which represents the loss, waste or misapplication of property and such explanation will be furnished within a period not exceeding two months from the date such requisition is communicated to the person concerned.</p> <p>Provided that explanation from any of the officers other than the Vice-Chancellor shall be called for through the Vice-Chancellor.</p> <p>Note: (1) Any information required by the Examiner, or by a person appointed by him for the purpose, for preliminary inquiry shall be furnished and all connected papers and records shown to him by the officer (or if such information, papers or records are in possession of a person other than the said officer, by such person) within a reasonable time not exceeding two weeks in any case.</p>

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in clause (1) the Examiner may call for the explanation in the following cases:-

(a) Where expenditure has been incurred in contravention of the provisions of these Statutes or of the Act or of the Ordinances or regulations made thereunder,

(b) where loss has been caused by acceptance of a higher tender without sufficient recorded reasons;

(c) Where any sum due to the University has been remitted in contravention of the provisions of these Statutes or the Act or the Ordinances or regulations made thereunder;

(d) Where loss has been caused to the University by neglect in realizing its dues; Where loss has been caused to the funds or property of the University on account of want of reasonable care for the custody of such money or property.

(3) On the written requisition of the officer from whom an explanation has been called the University shall give him necessary facilities for inspection of the connected records. The Examiner may, on an application from the officers concerned, allow a reasonable extension of time for submission of his explanation if he is satisfied that the officer charged has been unable for reasons beyond his control to inspect the connected records for the purpose of furnishing his explanation.

Explanation- Making of an appointment in contravention of the Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder shall amount to misconduct and payments to the person concerned of salary or other dues on account of such irregular appointment will be deemed to be a loss, waste or misapplication of university money.

After the expiry of the period prescribed and after considering the explanation, if received within time, the Examiner may surcharge the officer with the whole or a part of the sum for which such officer may in his opinion be liable:

Provided that in the case of loss, waste or misapplication accruing as a result of neglect or misconduct of two or more officers each such officer shall be jointly and severally liable:

Provided also that no officer shall be liable for any loss, waste or misapplication after the expiry of ten years from the occurrence of such loss, waste or misapplication or after the expiry of six years from the date of his ceasing to be such officer whichever is later.

66. An officer aggrieved by an order of surcharge passed by the Examiner may prefer an appeal to the Commissioner of the division in which the University is situated within thirty days from the date on which such order is communicated to him. The Commissioner may confirm, rescind or vary the order passed by the Examiner or may pass such order as he thinks fit. The order so passed shall be final, and no appeal shall lie against it.

Appeal against
order of
Surcharge

67. (1) The officer who has been surcharged shall pay the amount of surcharge within sixty days from the date on which such order is communicated to him or within such further time, not exceeding one year, from the said date as may be permitted by the Examiner:

Payment of
Surcharge

Provided that where an appeal has been preferred against the order of surcharge passed by the Examiner all proceedings for recovery of the amount from the person who has preferred the appeal may be stayed by the Commissioner until the appeal has been finally decided.

(2) If the amount of surcharge is not paid within the period specified in clause (1) it shall be recoverable as arrears of land revenue.

68. Where a suit is instituted in a Court to question an order of surcharge and the Examiner or the State Government is a defendant in such a suit, all cost incurred in defending the suit shall be paid by the University and it shall be the duty of the University to make such payment without any delay.

Suit against
order of
Surcharge

69. All existing Statutes and all such Ordinances of the University, as are inconsistent with these Statutes, shall to the extent of such inconsistency, be rescinded and shall forthwith cease to have effect except as respects things done or omitted to be done before such recession.

Recession

Form of
Agreement with
Members of
Teaching Staff
of the University

APPENDIX 'A'
(See Chapter IX)
FORM OF AGREEMENT WITH MEMBERS OF TEACHING
STAFF OF THE UNIVERSITY

Agreement made thisday of20.....,
between Sri..... of first part the University of.....
(hereinafter called "the University") of the other part:

It is hereby agreed as follows:

(1) That the University hereby appoints shri/ shrimati/
km.....to be a teacher of the University with effect from the
date the party of the first part takes charge of the duties of his/her office, and
the party of the first part, hereby accepts the engagement, and undertakes to
take such part, and perform such duties in the University as may be required
of his/her, including the management and protection of the University
property or funds, the organization of instruction the teaching formal or
informal and the examinations of students, the maintenance of discipline and
the promotion of students' welfare in connection with any curricular or
residential activities and perform such extra-curricular duties of the University
as may be entrusted to him/her and to submit himself/herself to the officers
under whom he/she is for the time being placed by the authorities of the
University and shall abide by and conform to the Code of Conduct for
teachers laid down by the University as amended from time to time.

Provided that the teacher shall be on probation for a period of one
year in the first instance and the Executive Council may on its discretion
extend the period of probation by one year.

(2) That, the party of first part shall retire in accordance with the
provisions of the Statutes of the University.

(3) The scale of pay attached to the post of teacher to which the party
of the first part is appointed shall be the party of the first part shall from the
date he/she takes charge of his/her said duties be granted pay at the rate of
Rs..... per mensem in the aforesaid scale and shall receive pay in
the succeeding stages in the scale unless the annual increment is withheld in
pursuance of the provisions of the Statutes:

Provided that where an efficiency bar is prescribed in the time scale,
the increment next above the bar shall not be given to the party of the first part
without the specific sanction of the authority empowered to withhold
increment.

(4) That the party of the first shall obey, and to the best of his/her
ability carry out the lawful directions of any officer, authority or body of the
University, to whose authority he/she may while this agreement is in force, is
subject under the Provisions of the said Act, or under any Statutes, Ordinances
or Regulations made thereunder.

(5) That the party of the first part hereby under- takes to abide by and
conform to the Code of Conduct laid down for the teachers, by the University,
as amended from time to time.

(6) That on the termination of this agreement from whatever cause,
the party of the first part shall deliver up to the University all books,
apparatus, record and other articles belonging to the University that may be in
his possession.

(7) In all matters, the mutual rights and obligations of the parties
hereto shall be governed by the Statutes and Ordinances of the University, for
the time being in force, which shall be deemed to be incorporated herein and
shall be as such a part of this agreement as if they were reproduced herein, and
by the provisions of Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2022.

In witness whereof the parties hereto affix their hands and seal on the
day year first above written.

.....
Signature of the Teacher

.....
Signature of the Finance Officer
Representing the University.

Witness:

1.

2.

APPENDIX 'B'**CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS**

Whereas a teacher, conscious of his responsibilities and trust placed in him to mould the character of the youth and to advance knowledge, intellectual freedom and social progress, is expected to realize that he can fulfill the role of moral leadership more by example than by precept through a spirit of dedication, moral integrity and purity in thought, word and deed.

Now, therefore, in keeping with the dignity of his calling, this code of conduct is hereby laid down to be truly and faithfully observed:

(1) Every teacher shall perform his academic duties with absolute integrity and devotion.

(2) No teacher shall show any partiality or bias in the assessment of the students nor shall he practice victimization against them.

(3) No teacher shall incite one student against another or against his colleagues or the Alma Mater.

(4) No teacher shall discriminate against any pupil on grounds of caste, creed, sect, religion, sex, nationality or language. He shall also discourage such tendencies, amongst his colleague's subordinates and students, and shall not try to use the above considerations for the improvement of his own prospects.

(5) No teacher shall refuse to carry out the decision of the appropriate bodies and functionaries of the University or the college, as the case may be.

(6) No teacher shall divulge any confidential information relating to the affairs of the University or college, as the case may be, to any person not authorized in respect thereof.

(7) No teachers shall run any other business Part time home teaching (tuition) and coaching classes.

(8) The teachers shall remain available to the students for necessary assistance and guidance even after the classes without any remuneration.

(9) With a view to completing the educational programme, a teacher shall take leave only in unavoidable circumstances with the prior permission as far as possible.

(10) The teacher shall remain engaged in developing his/her academic achievements by a continuous study, research and training.

(11) Every teacher shall provide assistance in the University or College, as the case may be, in educational responsibilities e.g. in admission, helping and counseling to students, conducting of examination, invigilation, supervision evaluation of answer books, teaching and other curricular activities of the University or College.

(12) As per the ideals of democracy, patriotism and peace, teacher shall create the feeling of respect among students towards scientific temperament and physical labour.

By order,

MUKESH KUMAR MESHRAM,

Pramukh Sachiv.